आर्थिक और सामाजिक विकास

बैंकिंग प्रणाली, वित्त, बीमा, पेंशन

2025

1. निवेश के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिये:
   I. बॉण्ड
   II. प्रतिरक्षा निधियाँ (हेज फंड्स)
   III. स्टॉक
   IV. जोखिम पूंजी

   उपर्युक्त में से कितनों को वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है?

   (a) केवल एक (b) केवल दो
   (c) केवल तीन (d) सभी चार

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: वैकल्पिक निवेश निधि (Alternative Investment Funds – AIFs) ऐसे वित्तीय साधन होते हैं, जो पारंपरिक निवेश श्रेणियों (जैसे- शेयर, बॉण्ड या नकद) में नहीं आते हैं।

- इसके उदाहरण में हेज फंड्स, जोखिम पूंजी या वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट और कमोडिटीज आदि शामिल हैं।

वैकल्पिक निवेश निधि (AIF) की तीन श्रेणियाँ

श्रेणी	निवेश का क्षेत्र	प्रमुख उदाहरण
श्रेणी-1	स्टार्टअप्स और बुनियादी ढाँचा (शुरुआती चरण)	वेंचर कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
श्रेणी-2	इक्विटी और ऋण (जो श्रेणी 1 व 3 में नहीं हैं)	रियल एस्टेट, प्राइवेट इक्विटी फंड
श्रेणी-3	जटिल रणनीतियाँ और डेरिवेटिव्स	हेज फंड, PIPEs (Private Investment in Public Equity) फंड

- भारत में वेंचर कैपिटल फंड्स और हेज फंड्स दोनों को वैकल्पिक निवेश निधि (AIFs) के रूप में वर्गीकृत (जैसा कि SEBI के वैकल्पिक निवेश निधि विनियमन, 2012 के तहत परिभाषित है) किया गया है।

अतः विकल्प (b) सही है।

- बॉण्ड्स पारंपरिक निवेश साधन होते हैं और इन्हें स्थिर आय प्रतिभूति (Fixed-Income Securities) की श्रेणी में रखा जाता है, जो अलग-अलग नियामकीय ढाँचे के अंतर्गत आते हैं।
- स्टॉक पारंपरिक इक्विटी निवेश के उदाहरण हैं।

2. निम्नलिखित में कौन-कौन से भारतीय रिज़र्व बैंक की आय के स्रोत हैं?
   I. सरकारी बॉण्डों का क्रय और विक्रय
   II. विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय
   III. पेंशन निधि प्रबंधन
   IV. निजी कंपनियों को ऋण देना
   V. करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

   (a) केवल I और II (b) II, III और IV
   (c) I, III, IV और V (d) I, II और V

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत की गई थी। यह देश की सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण, बैंकिंग प्रणाली का नियामक और मुद्रा जारी करने वाला निकाय है। आरबीआई का कार्य एक व्यावसायिक बैंक की तरह नहीं होता; इसकी आय मुख्यतः इसके नियामक एवं मौद्रिक कार्यों से होती है। इसके प्रमुख स्रोतों में शामिल हैं:

- **सरकारी बॉण्ड्स का क्रय और विक्रय:** RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) का क्रय और विक्रय करता है।
  - यह अपने पोर्टफोलियो में रखे गए सरकारी बॉण्डों से ब्याज से प्राप्त आय (interest income) अर्जित करता है, जो इसके मुख्य आय के मुख्य स्रोतों में से एक है।
- **विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय:** RBI विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से लाभ अर्जित करता है और विदेशी परिसंपत्तियों पर ब्याज से प्राप्त आय भी अर्जित करता है।
- **करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण:** RBI मुख्य रूप से सेग्नोरेज (Seigniorage) प्रक्रिया के माध्यम से करेंसी नोटों की छपाई और वितरण से अप्रत्यक्ष रूप से आय अर्जित करता है।
  - सेग्नोरेज वह लाभ है जो केंद्रीय बैंक को प्राप्त होता है, क्योंकि उसके द्वारा जारी की गई मुद्रा का अंकित मूल्य उन नोटों के उत्पादन और वितरण की लागत से बहुत अधिक होता है।
  - उदाहरण के लिये, यदि एक ₹500 का नोट छापने की लागत ₹3 है, तो शेष ₹497 का अंतर सरकार/आरबीआई के लिये लाभ की तरह होता है।
- RBI इन नोटों को वाणिज्यिक बैंकों को अंकित मूल्य पर बेचता है और अंकित मूल्य व उत्पादन लागत के बीच का अंतर केंद्रीय बैंक के लिये राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बनता है।

- पेंशन निधिफंड का प्रबंधन (कथन III) और निजी कंपनियों को ऋण देना (कथन IV)- ये दोनों RBI की आय के स्रोत नहीं हैं। अत: केवल I, II और V सही हैं। **अत: विकल्प (d) सही है।**

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

I. भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट [बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट (BRSR)] प्रस्तुत करने का अधिदेश करता है।

II. भारत में, व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (BRSR) प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी, इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है जो मुख्यत: गैर-वित्तीय स्वरूप के हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल I **(b) केवल II**
(c) I और II दोनों **(d) न तो I और न ही II**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (BRSR) का अधिदेश SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) द्वारा दिया गया है, न कि RBI द्वारा। SEBI ने शुरू में बाज़ार पूंजीकरण (Market Capitalization) के आधार पर शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिये BRSR को अनिवार्य किया था। **अत: कथन I गलत है।**

BRSR रिपोर्ट मुख्य रूप से गैर-वित्तीय (Non-financial) विवरणों पर केंद्रित है। इसमें कंपनियाँ अपने संचालन के उन पहलुओं की जानकारी देती हैं जिनका सीधा संबंध वित्तीय लाभ-हानि से नहीं होता, जैसे- पर्यावरणीय प्रभाव (कार्बन उत्सर्जन, अपशिष्ट प्रबंधन); सामाजिक ज़िम्मेदारी (कर्मचारी कल्याण, मानवाधिकार); शासन (नैतिकता, भ्रष्टाचार विरोधी नीतियाँ)।

- यह निवेशकों को यह समझने में मदद करता है कि कंपनी भविष्य के जोखिमों (जैसे -जलवायु परिवर्तन) के प्रति कितनी तैयार है। **इसलिये केवल कथन-II सही है।**

अत: विकल्प (b) सही है।

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

कथन I: जहाँ तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक-धारकों की तुलना में बॉण्ड-धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है।

कथन II: बॉण्ड-धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, जबकि स्टॉक-धारक उसके स्वामी होते हैं।

कथन III: पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिये किसी कंपनी द्वारा बॉण्ड-धारकों को स्टॉक-धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं।
(b) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन I, कथन II की व्याख्या करता है।
(c) कथन II और कथन III में से केवल एक सही है तथा वह कथन I की व्याख्या करता है।
(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

सही उत्तर: (a)

व्याख्या:

- बॉण्ड-धारकों (Bondholders) को स्टॉक-धारकों (Stockholders) की तुलना में कम जोखिम होता है, क्योंकि उन्हें एक निश्चित ब्याज प्राप्त होता है और उन्हें पुनर्भुगतान में प्राथमिकता दी जाती है। स्टॉक-धारकों की आय कंपनी के प्रदर्शन पर निर्भर होने के साथ परिवर्ती होती है। **अत: कथन I सही है।**
- बॉण्ड-धारक कंपनी को उधार देते हैं, इसलिये वे कंपनी के ऋणदाता (Creditors) होते हैं, वहीं स्टॉक-धारक कंपनी के हिस्सेदार होते हैं क्योंकि वे कंपनी के शेयर खरीदते हैं। **अत: कथन II सही है।**
- अगर कंपनी को बंद करना पड़े या वह दिवालिया हो जाए, तो सबसे पहले बॉण्ड-धारकों को पुनर्भुगतान किया जाता है, उसके बाद ही स्टॉक-धारकों को कोई राशि मिलती है। पुनर्भुगतान में इस प्राथमिकता से बॉण्ड-धारकों के लिये जोखिम और भी कम हो जाता है। **इसलिये कथन III सही है।**

अत: विकल्प (a) सही है।

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

I. वैश्विक स्तर पर किये गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक वृहद् अंश होता है, इस प्रकार भारत सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है।

II. हाल के विगत समय में भारत का स्टॉक बाज़ार तेज़ी से बढ़ा है, यहाँ तक कि उसने एक समय इसमें हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया।

III. छोटे निवेशकों को या तो विकल्प व्यापार जोखिमों की चेतावनी देने या इस विषय में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने के लिये कोई नियामक निकाय नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-कौन से सही हैं?

(a) केवल I और II **(b) केवल II और III**
(c) केवल I और III **(d) I, II और III**

सही उत्तर: (a)

व्याख्या:

- भारत विश्व का सबसे बड़ा इक्विटी ऑप्शन मार्केट बन गया है, जहाँ 2023 और 2024 की पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर ट्रेड किये गए सभी इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में 84% से अधिक हिस्सा भारत का रहा। अप्रैल 2024 तक भारत में 154 मिलियन ट्रेडिंग खाते थे जो अप्रैल 2019 में मौजूद 36 मिलियन ट्रेडिंग खातों की तुलना में चार गुना से अधिक वृद्धि को दर्शाता है।
- यह एक तीव्र वृद्धि को दर्शाता है, इसे आमतौर पर ऑप्शन ट्रेडिंग में "बूम" के रूप में वर्णित किया जा रहा है। **अत: कथन I सही है।**
- जनवरी 2024 में, भारत का स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन (Market Capitalisation) हांगकांग से आगे निकल गया, जिससे भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक/शेयर बाज़ार बन गया। **अत: कथन II भी सही है।**
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI)- भारत की एक सक्रिय विनियामक संस्था है। SEBI नियमित रूप से निवेशकों को ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों के प्रति चेतावनी देता है, हाल ही में इसने गैर-पंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर अंकुश लगाने और रिटेल निवेशकों की सुरक्षा हेतु नए नियम लागू किये हैं।
- SEBI के नियामकीय उपायों में शामिल हैं- ऑप्शन ट्रेडिंग के लिये कड़े नियम, निवेशक शिक्षा पहल, गैर-पंजीकृत सलाहकारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई। **इसलिये कथन III सही नहीं है।**

अत: विकल्प (a) सही है।

6. RTGS और NEFT के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

I. RTGS में भुगतान उसी क्षण हो जाता है, जबकि NEFT के मामले में भुगतान करने में कुछ समय लगता है।

II. RTGS में ग्राहक से आवक लेन-देन के लिये प्रभार लिया जाता है जबकि NEFT में ऐसा नहीं होता।

III. RTGS के लिये कतिपय दिनों में प्रचालन के घंटे सीमित हैं जबकि NEFT में ऐसा नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल I	**(b) I और II**
(c) I और III	**(d) केवल III**

सही उत्तर: (a)

व्याख्या:

- RTGS (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) लेन-देन/हस्तांतरण को व्यक्तिगत रूप से और वास्तविक समय में संसाधित करता है, जिसका अर्थ है कि हस्तांतरण जैसे ही शुरू होता है उसका निपटान तत्काल कर दिया जाता है। यह मुख्य रूप से बड़ी राशियों (न्यूनतम ₹ 2 लाख) के लिये है।
- NEFT (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) आधे घंटे के बैचों (आस्थगित शुद्ध निपटान) में लेन-देन की प्रक्रिया करता है, इसलिये लाभार्थी के खाते में धनराशि जमा होने में देरी होती है। सामान्यत: NEFT में पैसा पहुँचने में RTGS की तुलना में थोड़ा अधिक समय लगता है। **अत: कथन I सही है।**
- RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, RTGS और NEFT दोनों में आवक लेन-देन (Inward Transactions) के लिये कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है। **अत: कथन II सही नहीं है।**
- RBI के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार RTGS और NEFT दोनों अब ऑनलाइन लेन-देन के लिये वर्ष के 365 दिन, 24×7 उपलब्ध हैं। **अत: कथन III सही नहीं है।**
- इससे पहले RTGS का कार्य-समय सीमित हुआ करता था, लेकिन दिसंबर 2020 से यह चौबीसों घंटे काम करता है। NEFT को भी 24×7 कर दिया गया है।

अत: विकल्प (a) सही है।

7. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिये:

I. संयुक्त अरब अमीरात

II. फ्राँस

III. जर्मनी

IV. सिंगापुर

V. बांग्लादेश

उपर्युक्त में भारत के अलावा ऐसे कितने देश हैं, जहाँ UPI के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वणिक भुगतान (इंटरनैशनल मर्चेंट पेमेंट) स्वीकार किये जाते हैं?

(a) केवल दो	**(b) केवल तीन**
(c) केवल चार	**(d) सभी पाँच**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), भारत की रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तार कर चुकी है, जिससे भारतीय यात्रियों को विदेशों में व्यापारिक भुगतान की सुविधा प्राप्त हो गई है। प्रत्येक देश में UPI की स्थिति निम्नलिखित है:

- **संयुक्त अरब अमीरात (UAE) :** UAE की NeoPay और Mashreq Bank के साथ साझेदारी के माध्यम से UPI स्वीकार किया जाता है।
- **फ्राँस :** फरवरी 2024 में लॉन्च के बाद से, UPI भुगतान आइफिल टॉवर जैसे प्रमुख स्थलों पर स्वीकार किये जाते हैं।
- **जर्मनी :** ये वर्तमान में UPI के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। मई 2025 तक कोई आधिकारिक समझौता या साझेदारी नहीं हुई है।
- **सिंगापुर :** सिंगापुर के PayNow सिस्टम से UPI जुड़ा हुआ है। Google Pay और PhonePe जैसे ऐप्स के माध्यम से 30,000 से अधिक व्यापारियों द्वारा स्वीकार किया जाता है।

- **बांग्लादेश :** इनके साथ UPI एकीकरण नहीं है। भारत-बांग्लादेश के बीच सीमा पार लेन-देन पारंपरिक तरीकों से होते हैं, न कि UPI के माध्यम से। **अतः विकल्प (b) सही है।**

नोट : भारत के अलावा, फरवरी 2026 तक आठ देशों में UPI के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मर्चेंट भुगतान स्वीकार किये जाते हैं जिनमें सिंगापुर, यूएई, मॉरीशस, फ्राँस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और कतर शामिल हैं।

2024

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

कथन-I : यदि संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) अपने ऋण पर चूक करता है, तो US ट्रेजरी बॉण्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिये अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे।

कथन-II : USA सरकार का ऋण कोई मूर्त (हार्ड) परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की व्याख्या करता है

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, किंतु कथन-II, कथन-I की व्याख्या नहीं करता है

(c) कथन-I सही है, किंतु कथन-II सही नहीं है

(d) कथन-I सही नहीं है, किंतु कथन-II सही है

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: यदि संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) अपने ऋण पर चूक करता है, तो US ट्रेजरी बॉण्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिये अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिकी सरकार द्वारा जारी किये गए ट्रेजरी बॉण्ड किसी भी ठोस परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं होते हैं, बल्कि सरकार के विश्वास पर आधारित होते हैं। **अतः कथन I सही है।**

- अमेरिकी सरकार का ऋण, जिसमें ट्रेजरी बॉण्ड, बिल और नोट शामिल हैं, किसी विशिष्ट मूर्त (हार्ड) परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है। इसके बजाय, यह अमेरिकी सरकार के 'पूर्ण विश्वास और साख' द्वारा समर्थित है। **अतः कथन II भी सही है और कथन-I की सही व्याख्या करता है।**

अतः विकल्प (a) सही है।

2. डिजिटल रुपये के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिये:

1. यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रिक (सॉवरेन) मुद्रा है।

2. यह RBI के तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) पर देयता रूप में दिखाई देता है।

3. यह अपने डिज़ाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है।

4. यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिये स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 1 और 3**

(c) केवल 2 और 4 **(d) 1, 2 और 4**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या:

डिजिटल रुपया:

- डिजिटल मुद्रा से तात्पर्य ऐसी किसी भी मुद्रा से है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हो। डिजिटल रुपया आभासी मुद्रा है, जो भौतिक मुद्रा के समान ही उद्देश्य पूरा करती है।
- डिजिटल रुपया एक केंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जिसे RBI द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विनियमित किया जाता है, जो पारंपरिक मुद्राओं से जुड़ी स्थिरता और विश्वास को बनाए रखता है।
- डिजिटल टोकन के रूप में डिजिटल मुद्रा विधि मान्य मुद्रा का प्रतिनिधित्व करती है।
- इस प्रकार, डिजिटल मुद्रा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई एक संप्रभु मुद्रा (सॉवरेन करेंसी) है। **अतः कथन 1 सही है।**
- यह RBI तुलन-पत्र पर एक देयता के रूप में दिखाई देता है। इसे उसी मूल्यवर्ग में जारी किया जाता है जिसमें वर्तमान में कागज़ी मुद्रा और सिक्के जारी किये जाते हैं। **अतः कथन 2 सही है।**
- यह अपने डिज़ाइन के कारण मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत नहीं है। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कहा है कि डिजिटल रुपया मूलतः भौतिक रुपये जैसा ही है, केवल डिजिटल रूप में है और 1:1 के अनुपात में विनिमय योग्य है। रुपये सहित भौतिक मुद्रा भी मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशील है। जैसे-जैसे वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ती है, रुपये (भौतिक या डिजिटल) की क्रय शक्ति घटती जाती है।
- यह वाणिज्यिक बैंक की मुद्रा और नकदी के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। नकदी के मामले में, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और इसे बैंकों में जमा जैसे अन्य प्रकार के धन में परिवर्तित किया जा सकता है। **इसलिये कथन 4 सही है।**

अतः विकल्प (d) सही है।

3. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस योजना में नामांकन के लिये प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष है।

2. लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा।

3. इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक (सब्स्क्राइबर) को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹3,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी।

4. पारिवारिक पेंशन पति/पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) 1, 3 और 4 **(b) केवल 2 और 3**

(c) केवल 2 **(d) 1, 2 और 4**

सही उत्तर: **(b)**

व्याख्या: प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिकों के लिये एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें **अधिकतम मासिक आय ₹15000** है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**

- यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें अंशदान की राशि प्रवेश की आयु पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिये यदि कोई 18 वर्ष की आयु में जुड़ता है तो उसे ₹55 प्रतिमाह देने होंगे, जबकि 40 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले को ₹200 प्रतिमाह देने होंगे। केंद्र सरकार भी लाभार्थी के बराबर का ही (50 : 50 अनुपात) अंशदान करती है। **अतः कथन 2 सही है।**
- आवेदक के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है।
- इसके तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लाभार्थी को ₹ 3000 की सुनिश्चित मासिक पेंशन (जैसा भी मामला हो) मिलेगी। **अतः कथन 3 सही है।**
- योजना के अनुसार, यदि लाभार्थी या पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवनसाथी पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। इसके तहत **पारिवारिक पेंशन केवल जीवनसाथी** (अविवाहित बेटियों के लिये नहीं) पर लागू होती है। **अतः कथन 4 सही नहीं है। अतः विकल्प (b) सही है।**

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं।

2. भारत में, विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के धारक बन सकते हैं।

3. भारत में, शेयर बाज़ार (स्टॉक एक्सचेंज) ऋणों के लिये पृथक व्यापारिक मंच (ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) प्रदान कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 3**

(c) 1, 2 और 3 **(d) केवल 2 और 3**

सही उत्तर: **(c)**

व्याख्या: चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) भारत में RBI द्वारा प्रयुक्त एक मौद्रिक नीति उपकरण है, जो बैंकों को अल्पकालिक नकदी की कमी या अधिकता को पूरा करने में मदद करता है, जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता और ब्याज दरों को नियंत्रित किया जा सके।

- LAF का उपयोग बैंकों को आर्थिक अस्थिरता की अवधि के दौरान या उनके नियंत्रण से परे बलों के कारण होने वाले किसी भी अन्य प्रकार के दबाव से निपटने में सहायता के लिये किया जाता है। यद्यपि भारत में, सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक की तरलता समायोजन सुविधा विंडो का लाभ नहीं उठा सकती हैं, लेकिन वे RBI से प्राथमिक डीलर के रूप में पंजीकृत होकर इसका उपयोग कर सकती हैं। **अतः कथन 1 सही है।**

■ भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2018 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों या FPI को केंद्र सरकार द्वारा निर्गत किये गए राजकोष बिलों में निवेश करने की अनुमति दी थी। यद्यपि, निवेशकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी प्रतिभूतियों के साथ-साथ एक वर्ष से कम की परिपक्वता वाले कॉर्पोरेट बॉण्ड में उनका निवेश कुल निवेश के 20% से अधिक नहीं होना चाहिये।

- विदेशी निवेशक, चाहे वे विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) के रूप में पंजीकृत हों या नहीं, FII मार्ग के बाहर भी भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। **अतः कथन 2 सही है।**
- FII, अनिवासी भारतीयों (NRI) तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) को पोर्टफोलियो निवेश योजना (PIS) के माध्यम से भारत में प्राथमिक और द्वितीयक पूंजी बाज़ारों में निवेश करने की अनुमति है।

■ वर्ष 2018 में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने **देश का पहला समर्पित 'क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म' शुरू किया।**

- अलग-अलग ऋण ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खुदरा निवेशकों को एक चलनिधि और पारदर्शी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर कॉर्पोरेट बॉण्ड में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है। यह खुदरा और संस्थागत निवेशकों को ऋण प्रतिभूतियों को क्रय-विक्रय करने की सुविधा देता है। **इसलिये कथन 3 सही है।**

अतः विकल्प (c) सही है।

5. भारत में, निम्नलिखित में से कौन कॉर्पोरेट बॉण्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं?

1. बीमा कंपनियाँ **2. पेंशन निधि**

3. खुदरा निवेशक

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3 *सही उत्तर:* (d)

व्याख्या: वर्ष 2022 के आँकड़ों के अनुसार, बीमा कंपनियाँ प्रीमियम संग्रह में वृद्धि के कारण सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) पर अधिक निवेश कर रही हैं, जबकि बैंक इन प्रतिभूतियों में अत्यधिक निवेश के कारण इस मोर्चे पर अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। RBI के नवीनतम आँकड़ों से पता चलता है कि दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में 24.9% से दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही में **बीमा कंपनियों का सरकारी बॉण्ड में स्वामित्व** बढ़कर 26.14% हो गया है।

- वर्ष 2021 में, **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)** ने बीमा कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) एवं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITS) द्वारा निर्गत ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी। इस कदम का उद्देश्य बीमा कंपनियों द्वारा रखे गए पोर्टफोलियो की समग्र उपज में सुधार करना है, साथ ही रियल एस्टेट क्षेत्र को अधिक दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करना है।
  - InvITs और REITS दोनों को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है।
- **इसलिये, बीमा कंपनियाँ G-Secs और कॉर्पोरेट बॉण्ड दोनों में निवेश कर सकती हैं।**

- **पेंशन निधि को ऐसे कॉर्पोरेट बॉण्ड/प्रतिभूतियों** में निवेश करने की अनुमति है, जिनकी लागू रेटिंग स्केल में न्यूनतम 'A' रेटिंग या समकक्ष रेटिंग हो।
  - विकास के विभिन्न उपायों के साथ, बाज़ार में सहकारी बैंकों, लघु पेंशन, भविष्य निधि और अन्य निधियों आदि जैसी लघु संस्थाओं का प्रवेश भी देखा गया है। **इन संस्थाओं को संबंधित विनियमों के माध्यम से G-Secs में निवेश करना अनिवार्य है।**
  - **अत: पेंशन निधि G-Secs और कॉर्पोरेट बॉण्ड दोनों में व्यापार कर सकते हैं।**

- खुदरा निवेशक बैंकों और RBI के साथ गिल्ट खाते खोलकर सीधे **G-Sec में निवेश कर सकते हैं।** रिटेल डायरेक्ट स्कीम खुदरा निवेशकों को प्राथमिक नीलामी में G-Sec खरीदने के साथ-साथ द्वितीयक बाज़ार में G-Sec खरीदने और बेचने की अनुमति देती है।
  - सेबी ने **निजी तौर पर रखे जाने वाले कॉर्पोरेट बॉण्ड** के न्यूनतम टिकट आकार को ₹ 1 लाख से घटाकर ₹ 10,000 कर दिया है। इस कदम से **खुदरा निवेशकों के लिये निवेश का एक नया अवसर खुल गया है,** जो पहले बाज़ार से बाहर थे।
  - **अत: खुदरा निवेशक G-Secs और कॉर्पोरेट बॉण्ड दोनों में व्यापार कर सकते हैं।**

अत: विकल्प (d) सही है।

6. निम्नलिखित पर विचार कीजिये:

1. एक्सचेंज RBI के नियमों के अनुसा, भारत में अपनी ट्रेडेड फंड (ETF)

2. मोटर वाहन

3. मुद्रा की अदला-बदली

उपर्युक्त में से किसे/किन्हें वित्तीय लिखत (इंस्ट्रूमेंट) माना जाता है?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2 और 3

(d) केवल 1 और 3 *सही उत्तर:* (d)

व्याख्या: वित्तीय लिखत (Financial Instrument) उन संपत्तियों को कहा जाता है, जिनका व्यापार किया जा सकता है या जो दो पक्षों के बीच एक वित्तीय अनुबंध के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात् वे अमूर्त परिसंपत्तियाँ जिनसे भविष्य में नकदी के रूप में लाभ मिलने की संभावना होती है।

- वित्तीय लिखत को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: नकद लिखत और व्युत्पन्न लिखत या ऋण लिखत या इक्विटी लिखत जैसे परिसंपत्ति वर्ग के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। तीसरी विशिष्ट श्रेणी विदेशी मुद्रा लिखतों की है।
- **वित्तीय लिखतों के उदाहरणों में** स्टॉक, **एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF)**, बॉण्ड, जमा प्रमाण-पत्र (CD), म्यूचुअल फंड, ऋण और व्युत्पन्न अनुबंध आदि शामिल हैं। **अत: 1 सही है।**
- IMF e-लाइब्रेरी के अनुसार, **विगत दो दशकों में, औद्योगिक देशों में केंद्रीय बैंकों की बढ़ती संख्या ने घरेलू चलनिधि** को संतुलित करने के लिखतों में विदेशी मुद्रा स्वैप को शामिल किया है, **भले ही अधिकांश देशों में वास्तविक उपयोग सीमित रहा हो। अत: कथन 3 सही है। विदेशी मुद्रा लिखतों में मुद्रा स्वैप,** विदेशी मुद्रा विकल्प, विदेशी मुद्रा स्वैप शामिल हैं और ये मुख्य रूप से मुद्राओं से संबंधित हैं।
- यद्यपि मोटर वाहन एक मूर्त परिसंपत्ति है, इसलिये यह वित्तीय लिखत नहीं है। **इसलिये 2 सही नहीं है।**

अत: विकल्प (d) सही है।

7. विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियम/नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों (बैंकिंग सब्सिडरियों) के लिये कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है।

2. भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों (बैंकिंग सब्सिडरियों) के लिये, बोर्ड सदस्यों के कम-से-कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिये।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2 *सही उत्तर:* (d)

व्याख्या: भारत में विदेशी बैंकों द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (WOS) के लिये नियम:

- पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लिये आरंभिक न्यूनतम प्रदत्त मताधिकारी इक्विटी पूंजी ₹ 5 बिलियन या ₹500 करोड़ होना अनिवार्य है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि भारत में स्थापित विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निदेशक मंडल स्थानीय संस्था के सर्वोत्तम हित में कार्य करे, RBI अन्य देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप यह आदेश दे सकता है कि कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक होने चाहिये। **इसलिये कथन 2 सही नहीं है।**

अतः विकल्प (d) सही है।

8. भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नियमों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. CSR नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा।

2. CSR नियम CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2 *सही उत्तर:* (a)

व्याख्या: कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(d)(iv) में कहा गया है कि कंपनी के कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने वाली कोई भी गतिविधि अर्हत CSR गतिविधि नहीं मानी जाएगी। नियम के अनुसार, कर्मचारियों के लाभ के लिये विशेष रूप से अभिकल्पित की गई कोई भी गतिविधि 'कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने वाली गतिविधि' मानी जाएगी और स्वीकार्य CSR व्यय के रूप में योग्य नहीं होगी। **अतः कथन 1 सही है।**

- भारत विश्व के उन चुनिदा देशों में से है जिसने CSR व्यय को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया है। प्रत्येक कंपनी, जिसके लिये CSR प्रावधान लागू होते हैं, के निदेशक मंडल को यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनी अपनी CSR नीति के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम-से-कम 2% व्यय करे। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

अतः विकल्प (a) सही है।

9. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, "संपार्श्विकीकृत उधार लेन-देन संबंधी दायित्व" निम्नलिखित में से किसके लिखत (इंस्ट्रूमेंट) हैं?

(a) बॉण्ड बाज़ार

(b) विदेशी मुद्रा बाज़ार

(c) मुद्रा बाज़ार

(d) शेयर (स्टॉक) बाज़ार *सही उत्तर:* (c)

व्याख्या:

- संपार्श्विकीकृत उधार लेन-देन संबंधी दायित्व (CBLO) मुद्रा बाज़ार के लिखत (Instruments) है जो ऋण की शर्तों और नियमों के संबंध में उधारकर्त्ता एवं ऋणदाता के बीच दायित्व का प्रतिनिधित्व करता है। CBLO किसी भी विशिष्ट देश में अंतर-बैंक कॉल मनी मार्केट का उपयोग करने से प्रतिबंधित लोगों को अल्पकालिक मुद्रा बाज़ारों में भाग लेने की अनुमति देता है।
- चूँकि संपार्श्विकीकृत उधार लेन-देन संबंधी दायित्व (CBLO) के माध्यम से लेन-देन की अवधि 1 दिन से लेकर 1 वर्ष (सामान्यतः 19 दिनों तक) के बीच होती है। इसलिये यह स्पष्टतया मुद्रा बाज़ार की श्रेणी में आता है। जबकि पूंजी बाज़ार (बॉण्ड या शेयर बाज़ार) दीर्घकालिक निवेश के लिये होते है। **अतः विकल्प (c) सही है।**

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

कथन-I : सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्त्ता के चूक (डिफाल्ट) का जोखिम बढ़ाता है।

कथन-II : सामूहिक ऋण एक नियत राशि एकमुश्त निधि हो सकती है, किंतु ऋण व्यवस्था (क्रेडिट लाइन) नहीं हो सकती ।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की व्याख्या करता है।

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, किंतु कथन-II, कथन-I की व्याख्या नहीं करता है।

(c) कथन-I सही है, किंतु कथन-II सही नहीं है।

(d) कथन-I सही नहीं है, किंतु कथन-II सही है।

नोटः संघ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है।

2023

1. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:**

कथन-I: कोविड विश्वमारी के बाद के हाल के विगत काल में, पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थीं।

कथन-II : आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का, मौद्रिक नीति के उपायों से, प्रतिकार करने की सामर्थ्य है।

उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।

(c) कथन-I सही है किंतु कथन-II गलत है ।

(d) कथन-I गलत है किंतु कथन-II सही है।

सही उत्तर: **(a)**

व्याख्या:

- कोविड महामारी (विश्वमारी) के बाद के वर्षों में, विश्व भर में अनेकों केंद्रीय बैंकों ने महामारी के उपरांत की मुद्रास्फीति को रोकने के लिये ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। उदाहरण के लिये, RBI की मौद्रिक नीति समिति ने मई 2022 से कई बार दरों में बढ़ोतरी कर चुकी है। **अतः कथन I सही है।**
- केंद्रीय बैंकों को सामान्यतया वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने का कार्य सौंपा जाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा आर्थिक उतार-चढ़ाव का प्रबंधन करने तथा मूल्य स्थिरता प्राप्त करने के लिये मौद्रिक नीति (विशेष रूप से ब्याज दरों) का उपयोग किया जाता है। **इसलिये कथन II भी सही है।**

अतः विकल्प (a) सही है।

2. **भारतीय रिज़र्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को 'बंध्यकरण (स्टेरिलाइज़ेशन)' के एक के रूप में माना जाता है?**

(a) 'खुला बाज़ार कार्रवाई' का संचालन

(b) निपटारा और भुगतान प्रणालियों की निगरानी

(c) केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिये ऋण एवं रोकड़ प्रबंधन

(d) गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों के कार्यों का विनियमन

सही उत्तर: **(a)**

व्याख्या:

- बंध्यकरण (स्टेरिलाइज़ेशन) उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India - RBI) अर्थव्यवस्था में प्रवेशित नवीन मुद्रा को प्रभावहीन करने हेतु बैंकिंग प्रणाली से मुद्रा का निर्गमन करता है। बंध्यकरण की प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक खुला बाज़ार की क्रियाएँ (खुला बाज़ार परिचालन) जैसे मौद्रिक उपकरणों का प्रयोग करता है। यह स्टेरिलाइज़ेशन का मुख्य उपकरण है। इसके माध्यम से RBI प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करके बाज़ार में नकदी का बहिर्प्रवाह और अंतर्प्रवाह होता है। **अतः विकल्प (a) सही है।**
- सामान्यतः RBI बंध्यकरण के लिये बाज़ार स्थिरीकरण योजना (Market Stabilisation Scheme - MSS) को अपनाता है।
- **बाज़ार स्थिरीकरण योजना (MSS):** इसमें बड़ी पूंजी के प्रवाह से उत्पन्न अधिशेष तरलता को अल्प-दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेज़री बिलों की बिक्री के माध्यम से कम किया जाता है।

3. **निम्नलिखित बाज़ारों पर विचार कीजिये:**

   1. **सरकारी बॉण्ड बाज़ार**
   2. **शीघ्रावधि द्रव्य बाज़ार (कॉल मनी मार्केट)**
   3. **कोषपत्र बाज़ार (ट्रेज़री बिल मार्केट)**
   4. **स्टॉक बाज़ार**

पूंजी बाज़ार में, उपर्युक्त में से कितने शामिल हैं?

(a) केवल एक **(b) केवल दो**

(c) केवल तीन **(d) सभी चार**

सही उत्तर: **(b)**

व्याख्या:

- सरकारी बॉण्ड बाज़ार, पूंजी बाज़ार का एक हिस्सा है। **अतः विकल्प 1 सही है।**
- शीघ्रावधि द्रव्य (कॉल मनी) दर, वह दर है जिस पर धन को अल्पकालिक ऋण के रूप में लेकर बाज़ार में दिया जाता है। **अतः विकल्प 2 सही नहीं है।**
- कोषपत्र (ट्रेज़री बिल) सरकार द्वारा जारी अल्पकालिक ऋण प्रतिभूतियाँ हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष की होती है। इन्हें सबसे सुरक्षित प्रकार का द्रव्य बाज़ार साधन माना जाता है। **अतः विकल्प 3 सही नहीं है।**
- स्टॉक मार्केट, पूंजी बाज़ार का हिस्सा है। **इसलिये विकल्प 4 भी सही है।**

अतः विकल्प (b) सही है।

4. **वित्त के संदर्भ में, शब्द 'बीटा' किसे निर्दिष्ट करता है?**

(a) अलग-अलग प्लेटफॉर्मों से, साथ-साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया।

(b) किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की, जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन लाने की, निवेश कार्यनीति।

(c) एक प्रकार का व्यवस्थागत जोखिम, जो वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है।

(d) एक संख्यात्मक मान, जो पूरे स्टॉक बाज़ार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है।

सही उत्तर: **(d)**

व्याख्या:

- वित्त के संदर्भ में 'बीटा' शब्द का आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें शेयर बाज़ार के समग्र रूप से बढ़ने या घटने पर किसी व्यक्तिगत संपत्ति के उतार-चढ़ाव को मापा जाता है। इसका उपयोग जोखिम की माप के रूप में किया जाता है और यह कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल (CAPM) का एक प्रमुख घटक है। उच्च बीटा वाली कंपनी में अधिक जोखिम होता है और अधिक अपेक्षित रिटर्न भी होता है। बीटा गुणांक की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है:
  - $\beta = 1$ बिल्कुल बाज़ार की तरह स्थिर
  - $\beta > 1$ बाज़ार से अधिक अस्थिर
  - $\beta <1>0$ बाज़ार से कम अस्थिर
  - $\beta = 0$ बाज़ार से असंबद्ध
  - $\beta < 0$ बाज़ार से नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध
- बीटा गुणांक की गणना प्रतिभूति के प्रतिफल के सहप्रसरण के गुणनफल और एक निर्दिष्ट अवधि में बाज़ार के प्रतिफल के प्रसरण द्वारा होने वाले प्रतिफल को विभाजित करके की जा सकती है।
- एक प्रकार का ऐसा प्रणालीगत जोखिम जो तब होता है जब परफेक्ट हेजिंग संभव नहीं होती है, **आधार जोखिम** कहा जाता है।
- जोखिम बनाम लाभ को संतुलित करने हेतु किसी पोर्टफोलियो मैनेजर की निवेश रणनीति को **एसेट एलोकेशन** कहा जाता है।
- कीमतों में होने वाले अंतर से लाभ प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्लेटफॉर्मों, एक्सचेंजों या स्थानों से एक साथ संपत्ति की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया को आर्बिट्रेज कहा जाता है।
- ऐसा संख्यात्मक मान जिससे किसी स्टॉक के उतार-चढ़ाव को समग्र स्टॉक मार्केट में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है, बीटा कहलाता है।

अतः विकल्प (d) सही है।

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. स्वयं सहायता समूह [सेल्फ-हेल्प ग्रुप (एस.एच.जी.)] कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था।

2. किसी एस.एच.जी. में, समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिये उत्तरदायित्व लेते हैं, जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एस.एच. जी. को समर्थन देते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक **(b) केवल दो**

(c) सभी तीन **(d) कोई भी नहीं**

सही उत्तर: **(b)**

व्याख्या:

- स्वयं सहायता समूह या SHG लगभग दो दशक में एक प्रसिद्ध अवधारणा बन गई है। देश के आर्थिक विकास को गति देने में स्वयं सहायता समूहों की अपनी भूमिका है। स्वयं सहायता समूह पिछले कुछ वर्षों में आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है। **हम बांग्लादेश में डॉ. महमूद यूनुस द्वारा स्थापित स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा की उत्पत्ति का पता लगा सकते हैं। भारत ने बांग्लादेश के मॉडल को संशोधित रूप में अपनाया है।**
- **वर्ष 1970 में अहमदाबाद में 'सेवा' (स्व-नियोजित महिला संघ) संगठन की संस्थापक सदस्य ईलाबेन भट ने 'महिला एवं सूक्ष्म-वित्त' की अवधारणा विकसित की थी।** महाराष्ट्र में अन्नपूर्णा 'महिला मंडल' और तमिलनाडु में 'कामकाजी महिला मंच' तथा कई राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) प्रायोजित समूहों ने 'सेवा' द्वारा निर्धारित पथ का अनुसरण किया है।
- **वर्ष 1991-92 में नाबार्ड ने बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना शुरू किया, जो 'SHG आंदोलन' के लिये वास्तविक अनुकरण बिंदु था।** वर्ष 1993 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी स्वयं सहायता समूहों को बैंकों में बचत खाते खोलने की अनुमति दी। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- ऐसे **समूह उन सदस्यों के लिये सामूहिक सुनिश्चितता प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं जो संगठित स्रोतों से ऋण लेने का प्रस्ताव रखते हैं।** निर्धन लोग अपनी बचत पूंजी को बैंकों में जमा करते हैं। जिसके बदले में उन्हें अपनी सूक्ष्म इकाई उद्यम शुरू करने के लिये न्यूनतम ब्याज दर पर आसानी से ऋण प्राप्त होता है। **अतः कथन 2 सही है।**

Table 2 : Pattern of Partnership
Number of Participating Banks
Number of Branches of Banks Lending to SHGs
Commercial Banks
Regional Rural Banks (RRBs)
Co-operatives
Number of Participating NGO and other Agencies

इसलिये कथन 3 सही है।

अतः विकल्प (b) सही है।

2022

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. US फेडरल रिज़र्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है।

2. पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋणग्रहण (External Commercial Borrowings –ECBs) वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है।

3. घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, ECBs से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 2 और 3**

(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: **(*)**

व्याख्या:

* ध्यातव्य है कि संघ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर रखा है।

- सख्त या संकुचनकारी मौद्रिक नीति एक मौद्रिक उपाय है जिसका अर्थ है केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक विस्तार की दर में कमी। यह एक सूक्ष्म आर्थिक उपकरण है जिसे केंद्रीय बैंकों या सरकारी अंत:क्षेपों द्वारा निर्मित की गई उद्गामी मुद्रास्फीति या अन्य आर्थिक विकृतियों से निपटने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
- सख्त मौद्रिक नीति एक केंद्रीय बैंक जैसे कि फेडरल रिज़र्व द्वारा अर्थव्यवस्था की अत्यधिक तीव्र वृद्धि को धीमा करने के लिये की गई कार्रवाई है।
- केंद्रीय बैंक छूट दर और संघीय निधि दर में नीतिगत परिवर्तनों के माध्यम से अल्पकालिक ब्याज दरों को बढ़ाकर नीति को सख्त बनाता है या मुद्रा को संकुचित करता है। ब्याज दरों में वृद्धि से उधार लेने की लागत बढ़ जाती है और प्रभावी रूप से इसके आकर्षण में कमी आती है।
- केंद्रीय बैंक छूट दर और संघीय निधि दर में नीतिगत परिवर्तनों के माध्यम से अल्पकालिक ब्याज दरों को बढ़ाकर नीति को मज़बूत करता है या पैसे को तंग करता है।

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत में, साख क्षमता-निर्धारण एजेंसियाँ (क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं।

2. ICRA नाम से जानी जाने वाली क्षमता-निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है।

3. ब्रिकवर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता-निर्धारण एजेंसी है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 2 और 3**

(c) केलव 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: **(b)**

व्याख्या:

- भारत में सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 द्वारा विनियमित किया जाता है। यद्यपि RBI बैंकों के पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के लिये इन रेटिंग्स का उपयोग करता है, लेकिन मुख्य नियामक सेबी (SEBI) ही है। **अत: कथन 1 सही नहीं है।**
- ICRA लिमिटेड (पूर्व में इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड) की स्थापना 1991 में प्रमुख वित्तीय/निवेश संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय सेवा कंपनियों द्वारा स्वतंत्र और पेशेवर निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में की गई थी।
- वर्तमान ICRA और उसकी सहायक कंपनियाँ मिलकर ICRA ग्रुप ऑफ कंपनीज (ग्रुप ICRA) बनाती हैं। ICRA एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसके शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। अत: कथन 2 सही है
- ब्रिकवर्क रेटिंग्स, सेबी पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को भी आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह एक भारतीय एजेंसी है जिसका मुख्यालय बंगलूरू में है। भारत की अन्य प्रमुख एजेंसियाँ CRISIL, CARE और India Ratings & Research हैं। **इसलिये कथन 3 सही है।**

अत: विकल्प (b) सही है।

3. 'बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB)' के संदर्भ में, निम्नलिखित में कौन-से कथन सही हैं?

1. RBI का गवर्नर BBB का चेयरमैन होता है।

2. BBB, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिये संस्तुति करता है।

3. BBB, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को कार्यनीतियों और पूंजी-वर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 2 और 3**

(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: **(b)**

व्याख्या: बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) का गठन 'भारत में बैंकों के बोर्डों के शासन की समीक्षा समिति, मई 2014 (अध्यक्ष- पी.जे. नायक)' की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2016 में की गई थी।

- **गठन:** वर्ष 2016 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) और राज्य के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों के पूर्णकालिक निदेशकों और गैर-कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति हेतु सिफारिश करने के लिये पेशेवरों और अधिकारियों के एक निकाय के रूप में BBB के गठन को मंजूरी दी।

- यह एक स्वायत्त सलाहकारी निकाय है।
- बैंक बोर्ड ब्यूरो में अध्यक्ष, तीन पदेन सदस्य सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और पाँच विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं, जिनमें से दो निजी क्षेत्र से हैं। RBI का गवर्नर BBB का चैयरमैन नहीं होता है। **अतः कथन 1 गलत है।**
- बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है।
- बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रणनीति विकसित करने और पूंजी जुटाने में मदद करता है। इसका मुख्य कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शीर्ष प्रबंधन में पारदर्शिता दक्षता लाना है। **इसलिये कथन 2 और 3 सही हैं।**

नोट: 1 जुलाई, 2022 से BBB का नाम बदलकर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIS) कर दिया गया है, जिसकी शक्तियाँ और कार्यक्षेत्र अब और भी व्यापक (बीमा क्षेत्र तक) हो गए हैं।

अतः विकल्प (b) सही है।

4. परिवर्तनीय बॉण्ड के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. चूँकि बॉण्ड को ईक्विटी के लिये बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉण्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं।

2. इक्विटी के लिये बदलने का विकल्प बॉण्ड-धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से सहलग्नता (इंडेक्सेशन) की मात्रा प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1, न ही 2**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: एक परिवर्तनीय बॉण्ड एक निश्चित आय वाली कॉर्पोरेट ऋण सुरक्षा है जो ब्याज भुगतान प्राप्त करती है, लेकिन इसे सामान्य स्टॉक या इक्विटी शेयरों की पूर्व निर्धारित संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है।

- कंपनियाँ ऋण पर कूपन दर (कम ब्याज दर) तथा मंदन को कम करने के लिये परिवर्तनीय बॉण्ड जारी करती हैं। **अतः कथन 1 सही है।**
- ये निवेशकों के लिये अधिक आकर्षक हो सकते हैं क्योंकि परिवर्तनीय बॉण्ड स्टॉक की कीमत को भविष्य में पूंजी अभिमूल्यन के माध्यम से विकास क्षमता प्रदान करते हैं। इसलिये उपभोक्ता कीमतों में बढ़ोतरी से निवेशकों को फायदा होगा। **अतः कथन 2 सही है।**
- परिवर्तनीय बॉण्ड आमतौर पर सीधे कॉर्पोरेट बॉण्ड की तुलना में कम ब्याज दरों का भुगतान करते हैं- ब्याज व्यय में बचत महत्त्वपूर्ण हो सकती है।
- निवेशक कम ब्याज भुगतान स्वीकार करते हैं क्योंकि परिवर्तन विकल्प स्टॉक मूल्य में वृद्धि से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है। **अतः विकल्प (c) सही है।**

5. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, "मुद्रास्फीति-सहलग्न बॉण्ड (Inflation-Indexed Bonds – IIBs)" के क्या लाभ हैं?

1. सरकार IIBs के रूप में अपने ऋणग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है।

2. IIBs निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

3. IIBs पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर-योग्य नहीं होते।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 2 और 3**

(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: मुद्रास्फीति-सहलग्न बॉण्ड (IIBS) ऐसे ऋण साधन हैं जिन्हें विशेष रूप से मुद्रास्फीति के जोखिम से निवेशकों को बचाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, 1997 में जारी पूंजी अनुक्रमित बॉण्ड (Capital Indexed Bonds) ने केवल मूल धन को मुद्रास्फीति संरक्षण प्रदान किया, न कि ब्याज भुगतान को। जबकि IIB के नए उत्पाद मूल धन और ब्याज भुगतान दोनों को मुद्रास्फीति सुरक्षा प्रदान करेंगे।
- मुद्रास्फीति के खिलाफ समायोजित मूल धन पर निश्चित कूपन दर का भुगतान करके ब्याज दर को मुद्रास्फीति से सुरक्षा प्रदान की जाएगी तथा सरकार IIBs के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। **अतः कथन 1 और 2 सही हैं।**
- मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉण्ड (आईआईबी) 1997 के दौरान पूंजी अनुक्रमित बॉण्ड (सीआईबी) के नाम पर जारी किये गए थे तथा आईआईबी का द्वितीयक बाज़ार (बीएसई, एनएसई, और अन्य स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से) में भी कारोबार किया जा सकता है, हालाँकि, यदि वे द्वितीयक बाज़ार में बेचे जाते हैं और लाभ कमाया जाता है, तो पूंजीगत लाभ पर कर का भुगतान करना होता है। **इसलिये कथन 3 सही नहीं है।**

अतः विकल्प (a) सही है।

6. भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार-माध्यमों में अक्सर चर्चित "अप्रत्यक्ष अंतरण" को निम्नलिखित में कौन-सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है?

(a) कोई भारतीय कंपनी, जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उस बाहरी देश को कर अदा करती हो।

(b) कोई विदेशी कंपनी, जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती हो।

(c) कोई भारतीय कंपनी, जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और उनका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है तथा प्राप्ति को भारत में अंतरित कर देती है।

(d) कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। *सही उत्तर:* (d)

व्याख्या: जन संचार माध्यमों में अक्सर चर्चित शब्द 'अप्रत्यक्ष हस्तांतरण' उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहाँ विदेशी संस्थाएँ भारत में शेयर या संपत्ति रखती हैं, ऐसी विदेशी संस्थाओं के शेयरों को भारत में अंतर्निहित परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के बजाय स्थानांतरित किया जाता है। **अत: विकल्प (d) सर्वाधिक उपयुक्त है।**

2021

1. निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है?

(a) बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि

(b) बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात में वृद्धि

(c) लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि

(d) देश की जनसंख्या में वृद्धि *सही उत्तर:* (c)

व्याख्या: किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक उसके मौद्रिक आधार और मुद्रा आपूर्ति के संबंध को व्यक्त करता है। मुद्रा गुणक से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा के स्टॉक और शक्तिशाली मुद्रा (High Powered Money) के स्टॉक के अनुपात से है।

मुद्रा गुणक = M/H

यहाँ M से तात्पर्य मुद्रा का स्टॉक और H से शक्तिशाली मुद्रा से है।

- चूँकि, मुद्रा का स्टॉक सामान्यतया शक्तिशाली मुद्रा के मूल्य से अधिक होता है, इसलिये मुद्रा गुणक का मूल्य 1 से अधिक होता है। जनता की बैंकिंग आदतों की वृद्धि के साथ बैंक जमाओं में वृद्धि होने से बैंकों द्वारा अधिक ऋण सृजन होगा, जिससे चलन में मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी। **अत: विकल्प (c) सही है।**

2. भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाज़ार में 'राजकोष बिल (ट्रेज़री बिल)' और 'भारत सरकार के ऋण बॉण्ड' में निवेश कर सकते हैं।

2. 'बातचीत से तय लेन-देन प्रणाली-ऑर्डर मिलान (नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग)' भारतीय रिज़र्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है।

3. 'सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेज़ लिमिटेड' का भारतीय रिज़र्व बैंक एवं बंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 1 और 2**

(c) केवल 3 **(d) 2 और 3**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: फरवरी 2021 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने खुदरा निवेशकों को आरबीआई के साथ गिल्ट खाते खोलकर सीधे सरकारी बॉण्ड खरीदने की अनुमति दी। आरबीआई ने खुदरा निवेशकों को आरबीआई के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में पहुँच प्रदान की है। **अत: कथन (1) सही है।**

- इसके तहत खुदरा निवेशक गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों के लिये स्टॉक एक्सचेंजों पर खुद को पंजीकृत करके सरकारी बॉण्ड खरीद सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिये सरकारी बॉण्ड खरीदने का एक अन्य तरीका सरकारी प्रतिभूतियाँ म्यूचुअल फंड हैं। बातचीत से तय लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान [नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम)] आरबीआई के स्वामित्व वाला सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापारिक मंच है। इसकी सदस्यता बैंकों, प्राथमिक डीलरों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड आदि जैसी संस्थाओं के लिये खुली है। **अत: कथन (2) सही है।**
- सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) को बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) द्वारा प्रवर्तित किया गया था। **इसलिये कथन (3) सही नहीं है।**

अत: विकल्प (b) सही है।

3. भारत में, 'अंतिम उधारदाता (लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट)' के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यत: निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है/हैं?

1. अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना

2. अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिये चलनिधि उपलब्ध कराना

3. बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिये सरकारों को ऋण देना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) 1 और 2 **(b) केवल 2**

(c) 2 और 3 **(d) केवल 3**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु बैंकिंग परिचालन के विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है जो समस्त वित्तीय प्रणाली और निजी बैंकों में पर्याप्त नकदी की उपलब्धता दैनिक आधार पर करता है तथा सभी बैंकों के लिये अंतिम उधारदाता (लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट) की भूमिका निभाता है। अत: कथन (2) सही है।

आरबीआई, व्यापार एवं उद्योग निकाय को अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति की विफलता पर तथा सरकार को बजटीय घाटों की पूर्ति के लिये ऋण प्रदान नहीं करता है। अतः कथन 1 और 3 सही नहीं हैं। **अतः विकल्प (b) सही है।**

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. केंद्र सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है।

2. भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आर.बी.आई. को निर्देश देने का अधिकार देते हैं।

3. आर.बी.आई. का गर्वनर अपना अधिकार (पावर) आर.बी.आई. अधिनियम से प्राप्त करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: **(c)**

व्याख्या: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) का केंद्रीय निदेशक बोर्ड इसके कारोबार का पर्यवेक्षण करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधि. नियम, 1934 की धारा 8 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा इस निदेशक बोर्ड में एक गवर्नर और अधिकतम 4 उप-गवर्नर नियुक्त किये जाते हैं। अतः कथन 1 सही है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 7 के अनुसार केंद्र सरकार बैंक के गवर्नर के परामर्श से समय-समय पर बैंक को जनहित में आवश्यक निर्देश दे सकती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- आरबीआई गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 से अपना अधिकार प्राप्त करता है। इसकी धारा 7 के अनुसार केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों में गवर्नर और उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा इस निमित्त नामित उप-गवर्नर के पास बैंक के मामलों और व्यवसाय के सामान्य अधीक्षण और निर्देशन की शक्तियाँ होती हैं। अतः कथन 3 सही है। **अतः विकल्प (c) सही है।**

5. भारत में नियोजित अनियत मज़दूरों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. सभी अनियत मज़दूर, कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं।

2. सभी अनियत मज़दूर नियमित कार्य-समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं।

3. सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मज़दूरी का भुगतान करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: **(b)**

व्याख्या: सभी अनियत मज़दूर, कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार नहीं होते है। अतः कथन 1 सहीं नहीं है।

- मज़दूरी संहिता, 2019 की धारा 13 और 14 में सामान्य कार्यदिवस में कार्य के घंटे का निर्धारण और समयोपरि (Overtime) भुगतान का प्रावधान है। अतः कथन 2 सही है।
- मज़दूरी संदाय अधिनियम, 1936 में मज़दूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2017 के माध्यम से संशोधन किया गया था। जिसके तहत नियोक्ता को कर्मचारियों को सिक्कों या करेंसी नोट्स में या चेक द्वारा या कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा करके वेतन भुगतान की अनुमति दी गई थी। इसके तहत चेक द्वारा या कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा करके वेतन भुगतान करने की स्थिति में कर्मचारी की लिखित अनुमति लेने संबंधी शर्त हटा दी गई। हालाँकि केंद्र या राज्य सरकार कुछ विशिष्ट औद्योगिक या अन्य स्थापन्न को यह निर्देश दे सकती है कि उनके नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को केवल चेक द्वारा, या कर्मचारी के बैंक खाते में जमा करने के माध्यम से ही वेतन भुगतान करना होगा। अतः कथन 3 सही है। **अतः विकल्प (b) सही उत्तर होगा।**

6. भारत में 'शहरी सहकारी बैंकों' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है।

2. वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं।

3. उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के कार्य-क्षेत्र में लाया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: **(b)**

व्याख्या: शहरी सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय मंडल द्वारा नहीं किया जाता है। इनका पर्यवेक्षण और विनियमन आरबीआई और राज्य के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कॉपरेटिव सोसायटीज द्वारा किया जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

- बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को आरबीआई की अनुमति से इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही है।
- शहरी सहकारी बैंकों की व्यावसायिकता के बारे में चिंताओं ने बेहतर विनियमन की ओर बल दिया। बड़े सहकारी बैंकों, जिनकी चुकता शेयर पूंजी और कोष ₹ 1 लाख है, को 1 मार्च, 1966 से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) के कार्य-क्षेत्र में लाया गया। इसके साथ ही इन्हे रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण के अधीन किया गया। **इसलिये कथन 3 सही है। अतः विकल्प (b) सही है।**

7. भारतीय सरकारी बॉण्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे/किनसे प्रभावित होता है/होते हैं?

1. यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिज़र्व की कार्रवाई
2. भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्रवाई
3. मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 2**
(c) केवल 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: बॉण्ड प्रतिफल एक निवेशक को उस बॉण्ड पर मिलने वाला प्रतिफल (रिटर्न) है। यह प्रतिफल बॉण्ड की कीमत पर निर्भर करता है जो इसकी मांग से प्रभावित होता है। प्रतिफल को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति, सरकार की वित्तीय स्थिति, सरकार का ऋण कार्यक्रम, वैश्विक बाज़ार की स्थिति और मुद्रास्फीति की दर हैं।

- यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिज़र्व की कार्रवाइयाँ भी भारतीय सरकारी बॉण्ड के प्रतिफल को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिये यदि फेडरल रिज़र्व ब्याज दर में वृद्धि करता है तो निवेशक सरकारी बॉण्ड का विक्रय करेंगे, जिसके फलस्वरूप बॉण्ड के मूल्य में कमी होगी और बॉण्ड प्रतिफल में वृद्धि होगी। अत: कथन 1 सही है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विभिन्न मुद्रास्फीति प्रबंधन उपकरणों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में उपलब्ध तरलता और कोष की लागत का निर्धारण करता है। कोष की लागत बाज़ार में सरकारी बॉण्ड की मांग को सीधे प्रभावित करेगी और इस तरह इस पर प्रतिफल को प्रभावित करेगी। अत: कथन 2 सही है।
- मुद्रास्फीति और अल्पकालिक ब्याज दरें अर्थव्यवस्था में लोगों की क्रय क्षमता निर्धारित करती हैं। इसलिये, इसका सरकारी बॉण्ड की मांग और कीमत पर भी असर पड़ता है जिससे बॉण्ड प्रतिफल प्रभावित होता है। अत: कथन (3) सही है। **अत: विकल्प (d) सही होगा।**

2020

1. यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते (Demand Deposit Account) से ₹ 1,00,000 की नकद राशि निकालते हैं, तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

(a) मुद्रा की समग्र पूर्ति में ₹1,00,000 की कमी आएगी
(b) मुद्रा की समग्र पूर्ति में ₹1,00,000 की वृद्धि होगी
(c) मुद्रा की समग्र पूर्ति में ₹1,00,000 से अधिक की वृद्धि होगी
(d) मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी।

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: यदि कोई व्यक्ति अपने बैंक के मांग जमा खाते (Demand Deposit Account) से ₹ 1,00,000 की नकद राशि निकालता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। उदाहरण के लिये अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल पूर्ति ₹3,00,000 है जिसमें जनता के पास मुद्रा के रूप में ₹1,00,000 है, बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमा के रूप में मुद्रा की कुल पूर्ति ₹1,00,000 एवं आरबीआई के पास अन्य जमा राशि के रूप में ₹1,00,000 हैं। यदि जनता बैंकिंग प्रणाली से ₹50,000 निकाल लेती है तो मुद्रा की समग्र पूर्ति के रूप में जनता के पास ₹1,50,000 है। बैंकिंग प्रणाली में ₹50,000 एवं आरबीआई के पास अन्य जमा राशि के रूप में ₹1,00,000 होंगे। इस तरह अर्थव्यवस्था में मुद्रा की समग्र पूर्ति ₹3,00,000 की ही होंगी। अत: मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। **अत: विकल्प (d) सही है।**

2. भारत में फर्म के 'ब्याज-व्याप्ति अनुपात (Interest Coverage Ratio)' पद का क्या महत्त्व है?

1. यह उस फर्म, जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है, के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है।
2. यह उस फर्म, जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है, के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है।
3. उधार लेने वाली फर्म का ब्याज-व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा, उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी खराब होगी।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: ब्याज व्याप्ति अनुपात (Interest Coverage Ratio) किसी फर्म की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिये उपयोग किया जाने वाला एक पैरामीटर है। इसकी गणना एक विशिष्ट समय अवधि के लिये की जाती है, जो व्यवसाय के आधार पर मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक हो सकती है। यह वह अनुपात है जो ऋणों पर ब्याज की उपयुक्तता को दर्शाता है। यह दीर्घकालिक ऋणों पर देय ब्याज की सुरक्षा का मापक है, जो ब्याज के भुगतान हेतु उपलब्ध लाभ और देय ब्याज की राशि के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ब्याज व्याप्ति अनुपात से किसी फर्म के वर्तमान जोखिम के साथ-साथ आने वाले जोखिमों को भी समझने में मदद मिलती है। इसे निम्नवत परिकलित किया जाता है-

$$\text{ब्याज व्याप्ति अनुपात} = \frac{\text{ब्याज व कर देने से पूर्व निवल लाभ}}{\text{दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज}}$$

अर्थात, उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा, उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही अच्छी होगी। **अत: विकल्प (a) सही है।**

3. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. 'वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper)' अल्पकालीन प्रतिभूति- रहित वचन-पत्र है।

2. 'जमा प्रमाण-पत्र (Certificate of Deposit)' भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है।

3. 'शीघ्रावधि द्रव्य (Call Money)' अंतरबैंक लेन-देनों के लिये प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है।

4. 'शून्य-कूपन बॉण्ड (Zero-Coupon Bonds)' अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किये जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन बॉण्ड हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 4**

(c) केवल 1 और 3 **(d) केवल 2, 3 और 4**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: विभिन्न वित्तीय प्रपत्रों में 'वाणिज्यिक पत्र' (Commercial paper) वचन पत्र के रूप में जारी प्रतिभूति रहित अल्प अवधि के प्रपत्र हैं। 'जमा प्रमाण पत्र' एक विशिष्ट प्रकार के मुद्रा बाज़ार प्रपत्र (Nagotiable Money Market Instrument) है जिसे बैंक अपने पास जमा की गई मुद्रा के संबंध में जमाकर्त्ता को जारी करता है। जमा प्रमाण पत्र अथवा Certificate of Deposit के लिये कम-से-कम ₹ 1 लाख का निवेश आवश्यक है इसके पश्चात इसके गुणक में यह जारी किया जा सकता है। यह भी अल्प अवधि का प्रपत्र है।

- 'कॉल मनी' ऐसे ऋण को कहते है जो अगले दिन की वापसी की शर्त पर प्रदान किया जाता है तथा इसका उपयोग बैंक के आपसी लेनदेन में होता है।
- जीरो कूपन बॉण्ड एक ऋण प्रतिभूति है जो ब्याज अदा नहीं करता है लेकिन यह बड़ी छूटों (Discount) पर व्यापारित होता है। **अतः विकल्प (c) सही है।**

4. यदि आर.बी.आई. प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा?

1. वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना

2. सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना

3. बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 2**

(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाने के लिये ब्याज दरों में कटौती कर मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाना प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करना कहलाता है। वैधानिक तरलता अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात, बैंक दर एवं रेपो दर, रिवर्स रेपो दर एवं सीमान्त स्थायी सुविधा दर आदि को घटाकर अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि, परिणामतः समग्र मांग में वृद्धि की जा सकती है वहीं इसके विपरीत नीति संकुचनकारी मौद्रिक नीति कहलाती है। जिसमें उपर्युक्त अनुपातों एवं दरों में वृद्धि की जाती है। **इस प्रकार विकल्प (b) सही है।**

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान करने के संदर्भ में, 'ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs)' 'अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों' एवं 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों' की तुलना में अधिक ऋण देते हैं।

2. डी.सी.सी.बी. (DCCBs) का एक सबसे प्रमुख कार्य 'प्राथमिक कृषि साख समितियों' को निधि उपलब्ध कराना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1 न ही 2**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: सामान्यतः अल्पावधि सहकारी संस्थाओं की संरचना तीन स्तर की होती है शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, मध्यवर्ती स्तर पर ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक तथा जमीनी स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियाँ/ज़िला केंद्रीय संहकारी बैंक जनता से जमा राशि जुटाता है और जनता एवं प्राथमिक कृषि साख समितियों को ऋण प्रदान करता है।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के ऋण में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की भागीदारी लगभग 78-80 प्रतिशत है वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भागीदारी 5 प्रतिशत है। राज्य सहकारी बैंक, ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक एवं प्राथमिक कृषि साख समितियों की सम्मिलित रूप से भागीदारी 15-16 प्रतिशत है। **अतः विकल्प (b) सही है।**

6. भारत में, किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन-कौन से लाभ दिये जाते हैं?

1. यदि कोई मालवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुँच बाधित कर देता है, तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत

2. यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्त्व द्वारा जान-बूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत

3. यदि साइबर बलात्-ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिये विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएँ लेने पर लगने वाली लागत

4. यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1, 2 और 4 **(b) केवल 1, 3 और 4**

(c) केवल 2 और 3 **(d) 1, 2, 3 और 4**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: भारत में व्यक्ति के साइबर बीमा करने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अलावा अन्य निम्न लाभ भी दिये जाते हैं-

- मालवेयर द्वारा कंप्यूटर तक व्यक्ति की पहुँच को बाधित करने पर, कम्प्यूटर प्रणाली को पुन: प्रचालित करने में लगने वाली लागत।
- यदि साइबर अपकर्षण होता है तो इस हानि को कम करने के लिये विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएँ लेने पर लगने वाली लागत।
- यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कम्प्यूटर को नुकसान पहुँचाया गया है तो उसकी रिपेयरिंग बीमा के अंतर्गत कवर किया जाएगा लेकिन नए कम्प्यूटर की लागत नहीं। अत: कथन 2 सही नहीं होगा। **अत: विकल्प (b) सही है।**

2019

1. सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था?

(a) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(b) अग्रणी बैंक योजना (लीड बैंक स्कीम)

(c) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना

(d) राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: सेवा क्षेत्र उपागम 'लीड बैंक स्कीम' कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था।

- सेवा क्षेत्र उपागम, ग्रामीण (Rural) तथा अर्द्ध-शहरी (Semi-urban) क्षेत्रों के नियोजित एवं क्रमबद्ध विकास के लिये अप्रैल 1989 में आरंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादक ऋणों में वृद्धि करना तथा बैंक ऋण एवं उत्पादन, उत्पादकता व आय स्तर में वृद्धि के मध्य प्रभावी संबंध स्थापित करना था।

लीड बैंक स्कीम

- लीड बैंक स्कीम का संचालन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 1969 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य ज़िलों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना था।
- इसके अंतर्गत प्रत्येक ज़िले के लिये एक बैंक को लीड बैंक घोषित कर दिया जाता है। जिस बैंक को लीड बैंक घोषित किया जाता है वह ज़िला स्तर पर ऋणों की योजना बनाने, सरकारी कार्यक्रमों से संबंधित वित्त प्रबंधन करने, विशिष्ट कार्यक्रमों में अन्य बैंकों को सहयोग करने, उस क्षेत्र में वित्तीय संस्थानों में समन्वय कायम करने एवं उस क्षेत्र में बैंकिंग प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। **अत: विकल्प (b) सही है।**

2. भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है?

(a) अग्रिम

(b) जमा

(c) निवेश

(d) मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा (मनी ऐट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस)

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति (Assets) में जमाएँ (Deposits) शामिल नहीं होती हैं। दरअसल, जमाएँ (सावधि और मांग जमाएँ दोनों) बैंकों की देयताओं (Liabilities) का भाग होती हैं। किसी वाणिज्यिक बैंक (Commercial Bank) की परिसंपत्ति (Assets) में निम्नलिखित शामिल होते हैं-

- मनी ऐट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस
- निवेश (Investments), ऋण (Loan) और अग्रिम (Advances)
- मेच्योरिटी के एक वर्ष के भीतर की सरकारी प्रतिभूतियाँ
- कैश ऐट द सेंट्रल बैंक, कैश-इन-हैंड
- बिल्स डिस्काउंटेड आदि।

3. हाल ही में, भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर-ऋणदाता करार (इंटर-क्रेडिटर ऐग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था?

(a) भारत सरकार के राजकोषीय घाटे और चालू लेखा घाटे के वर्षानुवर्ष पड़ने वाले भार को कम करना

(b) केंद्रीय और राज्य सरकारों की आधारिक-संरचना परियोजनाओं को संबल प्रदान करना

(c) ₹50 करोड़ या अधिक के ऋणों के आवेदनों के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करना

(d) ₹50 करोड़ या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियों (स्ट्रेस्ड ऐसेट्स) का, जो सह-संघ उधारी (कॉन्सॉर्टियम लेंडिंग) के अंतर्गत है, अधिक तेज़ी से समाधान करने का लक्ष्य रखना

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks-PSBs) की गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों (Non-performing Assets-NPAs) और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों (Stressed Assets) की समस्या का समाधान करने के लिये सुनील मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक समग्र नीति 'प्रोजेक्ट सशक्त' बनाई गई है। प्रोजेक्ट सशक्त के तहत लीड बैंक को अधिकार देने वाले एक समझौते इंटर-क्रेडिटर एग्रीमेंट (ICA) पर हस्ताक्षर किये गए हैं। इस हस्ताक्षर का उद्देश्य है ₹50 करोड़ या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियों का, जो कॉन्सॉर्टियम लेंडिंग के अंतर्गत है, अधिक तेज़ी से समाधान करने का लक्ष्य रखना।

नोट : वर्तमान में भारतीय बैंक अपने उन ऋणों को गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों (NPAs) में डालते हैं, जिनकी किस्त एवं ब्याज का भुगतान 90 दिनों तक नहीं हो पाता।

4. सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है?

(a) बैंक बोर्ड ब्यूरो

(b) भारतीय रिज़र्व बैंक

(c) केंद्रीय वित्त मंत्रालय

(d) संबंधित बैंक का प्रबंधन

सही उत्तर: (a)

व्याख्याः सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों (Public Sector Banks) के अध्यक्षों का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो (Bank Board Bureau) करता है।

बैंक बोर्ड ब्यूरो से संबंधित तथ्य

- बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना बैंकों के प्रशासन से संबंधित 'पी.जे. नायक समिति' की सिफारिशों के आधार पर की गई।
- बैंक बोर्ड ब्यूरो ने 1 अप्रैल, 2016 से एक स्वायत्त सलाहकार निकाय के रूप में अपना कार्य करना शुरू किया।
- विनोद राय को बैंक बोर्ड ब्यूरो का प्रथम चेयरमैन नियुक्त किया गया था।

नोटः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा अगस्त 2015 में एक सात सूत्री कार्य योजना की घोषणा की गई, जिसे 'इंद्रधनुष' नाम दिया गया। इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई। बैंक बोर्ड ब्यूरो सरकार और बैंक के बीच कड़ी का काम करेगी।

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

'भुगतान प्रणाली आँकड़ों के भंडारण (स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डाटा)' के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल का निदेश, जिसे प्रचलित रूप से डाटा डिक्टैट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं (पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स) को समादेशित करता है कि

1. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आँकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किये जाएँ

2. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें

3. वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को समेकित प्रणाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: (a)

व्याख्याः RBI ने 'भुगतान प्रणाली डाटा रखे जाने' को लेकर अप्रैल 2018 में भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को निर्देश जारी किया था। उसमें कहा गया था कि देश के भुगतान से संबंधित सभी आँकड़े केवल भारत में ही रखना होगा। RBI के निर्देशानुसार, यदि भुगतान की प्रक्रिया विदेश में होती है तो वहाँ उससे संबंधित डाटा को हटा दिया जाए और उसे भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के एक कारोबारी दिवस या 24 घंटे के भीतर, जो भी पहले हो, भारत वापस लाया जाए। इन आँकड़ों में मैसेज/भुगतान निर्देश के हिस्से के रूप में शुरुआत से लेकर अंत तक के समस्त लेन-देन संबंधी विवरण/संग्रह की गई/लाई गई/संसाधित की गई सूचना शामिल होनी चाहिये। अतः कथन 1 सही है।

- 'भुगतान प्रणाली आँकड़ों' के भंडारण के संदर्भ में RBI इनके स्वामित्व एवं संचालन में निजी क्षेत्रों को प्रतिबंधित नहीं करता। अतः कथन 2 गलत है।

कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् भुगतान प्रणाली प्रदाता सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट (SAR) प्रस्तुत करेंगे। यह ऑडिट 'CERT-IN' सूचीबद्ध लेखापरीक्षकों द्वारा की जाएगी। अतः कथन (3) गलत है।

6. किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक (मनी मल्टिप्लायर) निम्नलिखित में से किस एक के साथ-साथ बढ़ता है?

(a) आरक्षित नकदी (कैश रिज़र्व) अनुपात में वृद्धि

(b) जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि

(c) सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि

(d) देश की जनसंख्या में वृद्धि

सही उत्तर: (b)

व्याख्याः किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक उसके मौद्रिक आधार और मुद्रा आपूर्ति के संबंध को व्यक्त करता है। मुद्रा गुणक से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा के स्टॉक और शक्तिशाली मुद्रा (High Powered Money) के स्टॉक के अनुपात से है।

मुद्रा गुणक = M/H

यहाँ M = मुद्रा का स्टॉक

H = शक्तिशाली मुद्रा

चूँकि, मुद्रा का स्टॉक सामान्यतया शक्तिशाली मुद्रा के मूल्य से अधिक होता है, इसलिये मुद्रा गुणक का मूल्य 1 से अधिक होता है।

- जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ बैंक जमाओं में वृद्धि होने से बैंकों द्वारा अधिक ऋण सृजन होगा, जिससे चलन में मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी। **अतः विकल्प (b) सही है।**

2018

1. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिये मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1, न ही 2**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: पिछले दशक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति को सुधारने एवं सुदृढ़ करने के लिये भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इन बैंकों में पूंजी का अंतर्वेशन (Infusion) किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक विगत कई वर्षों से गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों (NPAs) की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसका असर उनकी बैंकिंग गतिविधियों पर पड़ रहा है। बैंकों की इस मुश्किल स्थिति के मद्देनज़र वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा सात सूत्री इंद्रधनुष योजना को क्रियान्वित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बैंकों के फँसे ऋण की मात्रा को कम करना अर्थात् NPA में कमी लाना तथा बैंकों का प्रदर्शन सुधारना है। इस योजना के अंतर्गत बैंकों को चार वर्षों में कुल ₹70,000 करोड़ दिये जाने हैं। गौरतलब है कि इस योजना के अतिरिक्त भी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी का अंतर्वेशन किया गया है, जैसे 2017-18 के वित्तीय वर्ष के लिये भारत सरकार ने तय किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के 20 बैंकों में कुल ₹88,139 करोड़ का अंतर्वेशन किया जाएगा। इनमें ₹80000 करोड़ री-कैपिटिलाइज़ेशन बॉण्ड्स (Recapitalisation Bonds) तथा शेष ₹8139 करोड़ सीधे बजटीय आवंटन (Budgetary allocation) के ज़रिये दिये जाएंगे।

कथन (1) में पिछले दशक अर्थात् 2007-08 से 2016-17 के दौरान भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि होने की बात कही गई है, जो वित्त मंत्रालय और RBI की आधिकारिक साइट के आधार पर असत्य है।

अप्रैल 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से इसके पाँच एसोसिएट बैंकों (स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तथा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद) का इसमें विलय कर दिया गया। इसलिये कथन (2) सही है। **अतः विकल्प (b) सही है।**

2. निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन वैध मुद्रा (लीगल टेंडर मनी) के अर्थ को सही वर्णित करता है?

(a) न्यायालय में विधिक मामलों के लिये फीस के चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है

(b) वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिये बाध्य होता है

(c) चैक, ड्राफ्ट, विनिमय बिलों, आदि के रूप में बैंक मुद्रा

(d) किसी देश में चलन में धातु मुद्रा

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: वैधानिक मुद्रा वह है जो विधान या सरकारी आज्ञा पर चलन में आती है तथा जिसे स्वीकार करने के लिये प्रत्येक व्यक्ति बाध्य होता है। इसको लेने से इनकार करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जाता है। सरकार एवं केंद्रीय बैंक (भारत में रिज़र्व बैंक) द्वारा जारी किये गए सभी नोट एवं सिक्के वैधानिक मुद्रा हैं, क्योंकि इन्हें भुगतान में स्वीकार करने की कानूनी बाध्यता होती है। वर्तमान में लगभग सभी देशों की मुद्रा वैधानिक मुद्रा होती है। **अतः विकल्प (b) सही है।**

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सी.ए.आर.) वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है जिससे वे, यदि खाता-धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है, तो उसका प्रतिकार कर सकें।

2. सी.ए.आर. का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग-अलग किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1, न ही 2**

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) का अभिप्राय है, बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति तथा अपनी-अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात बैंकों के पूंजी जोखिम को तय करने का एक तरीका है जो बैंक के ऋणदान को प्रतिशत के रूप में बताता है। इस अनुपात का प्रयोग जमाकर्त्ताओं के हितों को संरक्षित करने के लिये किया जाता है। अतः कथन (1) सही है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात का निर्धारण देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के तहत वर्ष 1992 में पूंजी पर्याप्तता अनुपात को अपनाया गया। अतः कथन (2) सही नहीं है। **अतः विकल्प (a) सही है।**

4. कभी-कभी समाचारों में आने वाले पद "व्यापारी छूट दर" (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) को निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे सही स्पष्ट करता है?

(a) यह किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिये दिया जाने वाला प्रोत्साहन है।

(b) यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेन-देनों के लिये डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है।

(c) यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है।

(d) यह सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहकों से 'पॉइंट ऑफ सेल' (पी.ओ.एस.) मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। *सही उत्तर:* (c)

व्याख्या: व्यापारी छूट दर एक शुल्क है जिसे व्यापारियों द्वारा प्रत्येक डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड ट्रांज़ेक्शन के लिये बैंकों को अदा किया जाता है। इस प्रकार, उगाही गई राशि को कार्ड जारी करने वाले बैंक, ऋणदाता कंपनी जिसके प्वॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का उपयोग किया जा रहा है तथा पेमेंट गेटवे (Master Card/Visa आदि) के बीच बाँट दिया जाता है। **अतः विकल्प (c) सही है।**

5. निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी ATM को जोड़ता है?

(a) भारतीय बैंक एसोसिएशन

(b) राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड (नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपोज़िटरी लिमिटेड)

(c) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया)

(d) भारतीय रिज़र्व बैंक *सही उत्तर:* (c)

व्याख्या: भारत में सभी ATMs को जोड़ने वाले नेटवर्क National Financial Switch या राष्ट्रीय वित्तीय स्विच एटीएम नेटवर्क का संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया जाता है। **अतः विकल्प (c) सही है।**

2017

1. निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सम्मिलित हो सकता है?

(a) केवल निवासी भारतीय नागरिक

(b) केवल 21 से 55 तक की आयु के व्यक्ति

(c) राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख के पश्चात् सेवा में आए हैं

(d) सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, जो 1 अप्रैल, 2004 को या उसके बाद सेवाओं में आए हैं

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) 1 जनवरी, 2004 को प्रारंभ की गई। यह केंद्रीय सरकारी सेवा (सशस्त्र बल के अलावा) के तथा 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में आने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सभी नए कर्मचारियों पर लागू है। अन्य कोई सरकारी कर्मचारी जो NPS के तहत अनिवार्य रूप से शामिल नहीं है, वह भी उपस्थित सेवा प्रदाता के माध्यम से 'सभी नागरिक मॉडल' के तहत भी अभिदान कर सकता है।

- भारत के सभी नागरिक चाहे वे निवासी हों या अनिवासी 18 वर्ष की उम्र से लेकर 65 वर्ष तक NPS में शामिल हो सकते हैं।

NPS राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है, जो राज्य सरकारों की अधिसूचना की तारीख के बाद राज्य स्वायत्त निकायों में शामिल होते हैं।

2. भारत में लघु वित्त बैंकों (SFBs) को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है?

1. लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना

2. लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना

3. युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3 *सही उत्तर:* (a)

व्याख्या: भारत में लघु वित्त बैंक को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य/प्रयोजन है–

1. सेविंग व्हीकल (Vehicle) के रूप में
2. वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिये
3. लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना
4. लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना
5. अन्य असंगठित क्षेत्र की इकाइयाँ जो उच्च तकनीक एवं कम लागत पर उत्पाद तैयार करती हैं।

युवा उद्यमियों तथा ग्रामीण क्षेत्र व्यापार को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं रहा है। **अतः विकल्प (a) सही है।**

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया/NPCI) देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है।

2. NPCI ने एक कार्ड भुगतान स्कीम RuPay प्रारंभ की है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 , न ही 2

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: NPCI भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिये एक वृहद् संस्था है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के मार्गदर्शन और समर्थन के साथ स्थापित किया गया था। यह देश के वित्तीय समावेशन के संवर्द्धन में सहायता करता है।

रुपे भारत की राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा निर्मित और लॉन्च की गई एक भारतीय घरेलू कार्ड योजना है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक की घरेलू, खुली लूप और भारत में भुगतान की बहुपक्षीय व्यवस्था की पूर्ति के लिये बनाई गई थी। **इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प (c) है।**

4. 'एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (यूनिफाइड पेमेंट्स इन्टरफेस/UPI)' को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है?

(a) ऑनलाइन भुगतानों के लिये मोबाइल वालेट आवश्यक नहीं होंगे।

(b) लगभग दो दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी।

(c) FDI अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी।

(d) निर्धन व्यक्तियों को उपदानों (सब्सिडीज़) का प्रत्यक्ष अंतरण (डाइरेक्ट ट्रांसफर) बहुत प्रभावकारी हो जाएगा।

सही उत्तर: **(a)**

व्याख्या: UPI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा लॉन्च किया गया तथा RBI द्वारा रेगुलेटेड एक सिस्टम है। इसके माध्यम से दो अलग बैंक अकाउंट में त्वरित गति से धन अंतरण (Fund Transfer) किया जा सकता है।

इसका FDI के अंतर्वाह से संबंध नहीं है और न ही सब्सिडी का अंतरण इस माध्यम से होता है। दो दशक में यह पूरी तरह से 'भौतिक मुद्रा' को डिजिटल मुद्रा में स्थान भी नहीं दिला सकता। अत: विकल्प **(b)**, **(c)** एवं **(d)** पूर्णत: गलत हैं।

विकल्प (a) सही है, क्योंकि UPI को कार्यान्वित करने से किसी मोबाइल वॉलेट, जैसे– Paytm, Airtel money, Phone Pe इत्यादि रखने की मजबूरी नहीं होगी।

2016

1. भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 'भुगतान बैंकों (पेमेंट बैंक्स)' की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर-बाज़ार शृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं।

2. भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं।

3. भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 और 2	**(b) केवल 1 और 3**
(c) केवल 2	**(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: **(b)**

व्याख्या: वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से स्थापित पेमेंट बैंक ग्राहकों को एटीएम-डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, परंतु ये बैंक नियमित बैंकों की तरह कर्ज़ नहीं दे सकते तथा क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते। ये बैंक अपने पास नकदी या सरकारी प्रतिभूतियाँ ही रख सकते हैं।

पेमेंट बैंक के लिये रिज़र्व बैंक ने 2013 में डिस्कशन पेपर जारी किया था। इसके बाद नचिकेत मोर समिति का गठन किया गया। तत्पश्चात् रिज़र्व बैंक ने पेमेंट बैंक हेतु लाइसेंस जारी करने के लिये नियम-कानून तय किये थे। इन भुगतान बैंकों की प्रवर्तक कंपनियों का स्वामित्व भारतीय व्यक्तियों के पास होना आवश्यक है।

2. 'कोर बैंकिंग समाधान (Core Banking Solutions)' पद कभी-कभी समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से इस पद का सही वर्णन करता है/करते हैं?

1. यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो।

2. यह व्यावसायिक बैंकों पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से RBI का नियंत्रण बढ़ाने का एक प्रयास है।

3. यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अनर्जक (नॉन-परफॉर्मिंग) परिसम्पत्ति वाले बैंक का अधिग्रहण दूसरे बैंक द्वारा कर लिया जाता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1	**(b) केवल 2 और 3**
(c) केवल 1 और 3	**(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: **(a)**

व्याख्या: 'कोर बैंकिंग समाधान' (सीबीएस) बैंक शाखाओं की नेटवर्किंग (जाल) प्रणाली है। 'कोर बैंकिंग' एक बैंकिंग सेवा है जो नेटवर्किंग बैंक शाखाओं द्वारा प्रदान की जाती है तथा जिसमें उपभोक्ता बैंक की किसी भी शाखा से मूल लेन-देन एवं ज़रूरी बैंकिंग सेवाएँ आसानी से प्राप्त कर सकता है। कोर बैंकिंग शाखाओं के तहत उपभोक्ता कहीं भी एवं बैंक की किसी भी शाखा से, भले ही उपभोक्ता ने अपना खाता किसी दूसरे शहर या स्थान पर खुलवाया हो, वह सभी प्रकार की सेवाएँ प्राप्त कर सकता है। सामान्य कोर बैंकिंग प्रकार्य में खातों के लेन-देन, ऋण बंधक (Mortgage) और भुगतान इत्यादि शामिल हैं। बैंक इन सभी सुविधाओं को उपभोक्ता तक आसानी से उपलब्ध कराने हेतु कई प्रणालियों, जैसे- एटीएम, इंटरनेट, बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग तथा शाखाओं का उपयोग करता है।

कोर बैंकिंग सर्विस कम्प्यूटर तथा नेटवर्क तकनीकी पर संचालित होती है जिसमें बैंक सभी शाखाओं के रिकॉर्ड को केंद्रीकृत कर सकता है और इसे किसी भी स्थान तक पहुँचा सकता है। यह एक प्रकार से दूरसंचार क्षेत्र के पोर्टेबिलिटी की तरह है।

3. RBI द्वारा घोषित 'कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर [Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR),' का/के उद्देश्य क्या है/हैं?

1. ये दिशानिर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं।

2. ये दिशानिर्देश बैंक साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले एवं बैंक दोनों के लिये न्यायसंगत हैं।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1 और न ही 2**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: आरबीआई द्वारा घोषित 'कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर के उद्देश्य:

आरबीआई ने सीमांत निधि लागत पर आधारित अग्रिमों पर ब्याज दरों के परिकलन के अंतिम दिशानिर्देश दिसंबर 2015 में जारी किये थे, जो 1 अप्रैल, 2016 से लागू हो गए। ये दिशानिर्देश अग्रिमों पर ब्याज दरों के निर्धारण के लिये बैंकों द्वारा अपनाई जा रही पद्धति में पारदर्शिता को बेहतर बनाने में सहायक होंगे तथा इनसे ऐसी दरों पर बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित होगी जो उधार लेने वालों के साथ-साथ बैंकों के लिये उचित हो। अत: दोनों कथन सही हैं।

4. 'वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद् (Financial Stability and Development Council)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यह नीति (NITI) आयोग का एक अंग है।

2. संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है।

3. यह अर्थव्यवस्था के समष्टि सविवेक (मैक्रो-प्रूडेंशियल) पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण (मॉनिटरिंग) करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 3**

(c) केवल 2 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: 'वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद' का प्रमुख केंद्रीय वित्तमंत्री होता है। इसके सदस्यों में रिज़र्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार, सेबी के अध्यक्ष, इरडा (IRDA) के अध्यक्ष तथा पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष होते हैं। यह अर्थव्यवस्था के समष्टि सविवेक पर्यवेक्षण की मॉनिटरिंग करता है।

'वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद' (एफएसडीसी) भारत में वित्तीय सशक्तता और वित्तीय संस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 2010 में प्रणब मुखर्जी (वित्तमंत्री) के समय की गई। इसकी अनुशंसा रघुराम राजन समिति ने की थी। एफएसडीसी का क्रियान्वयन निम्न उद्देश्यों के लिये है-

- एफएसडीसी का कार्य देश में वित्तीय शिक्षा एवं वित्तीय समावेशन पर नज़र रखना है।
- इसका काम देश में मज़बूत वित्तीयन संरचना एवं तंत्र का विकास करना है।
- यह वित्तीय घटनाओं पर नज़र रखेगी।
- साथ ही यह प्रमुख वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोगी के रूप में कार्य करेगी।

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ए.पी.ई.सी. (APEC) द्वारा की गई है।

2. न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना BRICS देशों (ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका) द्वारा की गई है।

न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना विकासशील देशों में संरचनात्मक एवं समावेशी विकास को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के उद्देश्य के साथ की गई। ब्रिक्स सम्मेलन, 2014 में 100 अरब डॉलर की राशि के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की उद्घोषणा की गई। माना जा रहा है कि इस बैंक व फंड को पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाली संस्था आईएमएफ व विश्व बैंक की टक्कर में खड़ा किया गया है। इस बैंक का सबसे बड़ा उद्देश्य वैश्विक, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाना है।

6. 'अटल पेंशन योजना' के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. यह एक न्यूनतम गारंटित पेंशन योजना है, जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों को लक्ष्य बनाती है।

2. परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है।

3. अभिदाता (सब्स्क्राइबर) की मृत्यु के पश्चात् जीवनसाथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटित रहती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 2 और 3**

(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: अटल पेंशन योजना 1 जून, 2015 से प्रभावी है। यह योजना मूल रूप से असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिये है जो किसी भविष्य निधि से जुड़े नहीं हैं। इसमें अभिदाता की मृत्यु के बाद उसके जीवन साथी को आजीवन पेंशन की राशि मिलती है। इस योजना में एक परिवार के एक ही सदस्य को लाभ प्रदान करने का ज़िक्र नहीं है।

2015

1. 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' निम्नलिखित में से किसके लिये प्रारंभ की गई है?

(a) गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिये

(b) पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिये

(c) देश में वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इंक्लूज़न) को प्रोत्साहित करने के लिये

(d) उपांतिक (मार्जिनलाइज़्ड) समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये *सही उत्तर: (c)*

व्याख्या: प्रधानमंत्री जन-धन योजना की घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2014 को देश में वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इंक्लूज़न) को प्रोत्साहित करने के लिये की गई थी। औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत 28 अगस्त, 2014 को हुई। यह वित्तीय सेवाओं, जैसे- बैंकिंग/बचत और जमा खातों, रेमिटेन्स (वित्त प्रेषण), साख, बीमा और पेंशन तक वहनीय (Affordable) रूप में भारतीय जनता की पहुँच सुनिश्चित करने का माध्यम है।

2. जब भारतीय रिज़र्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात (स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो) को 50 आधार अंक (बेसिस पॉइंट) कम कर देता है, तो निम्नलिखित में से क्या होने की सम्भावना होती है?

(a) भारत की GDP विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी।

(b) विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी लाएंगे।

(c) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी उधार देने की दर को घटा सकते हैं।

(d) इससे बैंकिंग व्यवस्था की नकदी (लिक्विडिटी) में प्रबलता से कमी आ सकती है। *सही उत्तर: (c)*

व्याख्या: जब भारतीय रिज़र्व बैंक सांविधिक तरलता अनुपात (स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो: SLR) को 50 आधार अंक (बेसिस प्वाइंट) कम कर देता है, तो यह संभावना हो सकती है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी उधार देने की दर (Interest rate) को घटा सकते हैं। विकल्प **(a)** गलत है, क्योंकि भारत की GDP विकास दर प्रबलता से तब बढ़ेगी जब वस्तुओं एवं सेवाओं का समग्र उत्पादन बढ़े, निर्यात में बढ़ोतरी हो, व्यापार घाटे की स्थिति न हो, निवेश की अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हो। सांविधिक नकदी अनुपात एक मौद्रिक उपकरण मात्र है, जिससे तरलता अथवा मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने में ही सहायता मिल सकती है।

विकल्प **(b)** भी गलत है, क्योंकि बैंकों के पास अपनी जमा की एक निर्धारित मात्रा को खर्च न कर उसे नकद, स्वर्ण, विदेशी मुद्रा या स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखने से विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) को देश में पूंजी लगाने के लिये आकर्षित करने में मदद नहीं मिलती है। सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) से संबंधित कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू निम्नवत् हैं:

- सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) की व्यवस्था के तहत बैंकों को अपने पास अपनी जमा का कम-से-कम 0 प्रतिशत से अधिकतम 40 प्रतिशत तक नकद, स्वर्ण, विदेशी मुद्रा या स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखना अनिवार्य है। यह दर RBI निर्धारित करता है।
- यदि इस निर्धारित राशि को कम मात्रा में रखने की सुविधा आरबीआई के ज़रिये मिले तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी उधार देने की दर को घटा सकते हैं क्योंकि बैंकों के पास उधार देने के लिये अधिक धनराशि उपलब्ध होगी और वे अधिक उधार लेने के लिये लोगों को आकर्षित करने हेतु ब्याज दरों को घटा सकते हैं।

3. समाचारों में प्राय: आने वाला 'बेसल III (Basel III) समझौता' या सरल शब्दों में 'बेसल III'

(a) जैव-विविधता के संरक्षण और धारणीय (सस्टेनेबल) उपयोग के लिये राष्ट्रीय कार्यनीतियाँ विकसित करने का प्रयास करता है।

(b) बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबन्धन को उन्नत करने का प्रयास करता है।

(c) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करता है किंतु विकसित देशों पर अपेक्षाकृत भारी बोझ रखता है।

(d) विकसित देशों से निर्धन देशों को प्रौद्योगिकी के अंतरण का प्रयास करता है ताकि वे प्रशीतन में प्रयुक्त होने वाले क्लोरोफ्लोरो कार्बन के स्थान पर हानिरहित रसायनों का प्रयोग कर सकें। *सही उत्तर: (b)*

व्याख्या: समाचारों में आने वाला 'बेसल III (Basel III) समझौता' या सरल शब्दों में बेसल III बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। अत: विकल्प **(b)** सही है। बेसल समझौते से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य निम्नवत् हैं:

- **बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS)** के अनुसार, बैंकिंग निरीक्षण पर गठित बेसल समिति के निर्माण का इतिहास 1973 में प्रबंधित विनिमय दरों की ब्रेटनवुड्स प्रणाली के बिखर जाने से वित्तीय बाज़ारों में आए तनावों को दूर करने के लिये हुए प्रयासों से शुरू हुआ।

- **बेसल-I:** यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय वित्त बाज़ारों में पूंजी पर्याप्तता की दशा को बनाए रखने के लिये किया गया था। 1988 में हुए इस समझौते में 1992 के अंत तक 8 प्रतिशत जोखिम भारित परिसंपत्तियों के न्यूनतम पूंजी अनुपात को क्रियान्वित करने का आह्वान किया गया था। 1991 में इसमें संशोधन किया गया था।
- **बेसल-II:** जून 1999 में बेसल समिति ने 1988 के समझौते को प्रतिस्थापित करने के लिये नई पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा का प्रस्ताव दिया। जून 2004 में आई इसी संशोधित पूंजी रूपरेखा को बेसल II कहते हैं। इसमें न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को बनाए रखने की बात की गई है। साथ ही किसी संस्था की पूंजी पर्याप्तता और आंतरिक आकलन प्रक्रियाओं की निरीक्षकीय समीक्षा की बात भी की गई है।
- **बेसल-III:** लेहमन ब्रदर्स जैसे औद्योगिक निकायों के धराशायी होने से उत्पन्न हुए वित्तीय संकट को देखते हुए दिसंबर 2010 में बेसल-III मानकों को लाया गया। इसमें पूंजी संरक्षण बफर, प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (Counter Cyclic Capital Buffer) को बनाने की बात की गई है ताकि अर्थव्यवस्थाएँ वित्तीय उतार-चढ़ाव से बच सकें।

4. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिये-

1. बैंक दर
2. खुली बाज़ार कार्रवाई (ओपेन मार्केट ऑपरेशन)
3. लोक ऋण (पब्लिक डेब्ट)
4. लोक राजस्व (पब्लिक रेवेन्यू)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से मौद्रिक नीति का/के घटक है/हैं?

(a) केवल 1 | **(b) 2, 3 और 4**
(c) 1 और 2 | **(d) 1, 3 और 4**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: मौद्रिक नीति के घटकों में शामिल हैं: बैंक दर, खुली बाज़ार की क्रियाएँ, परिवर्तनीय कोष अनुपात (Variable Reserve Ratio), नकद कोष अनुपात (CRR) तथा वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) आदि। भारत के रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के नियमन अथवा उस पर नियंत्रण रखने का कार्य किया जाता है, जबकि सार्वजनिक अथवा लोक व्यय, करारोपण, लोक ऋण, हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति आदि राजकोषीय नीति के घटक होते हैं। **अत: विकल्प (c) सही है।** भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रश्नगत शब्दावलियों का परिचय निम्नवत् है:

- **बैंक दर (Bank Rate):** वह दर जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक व्यावसायिक बैंकों को उधार देता है। तरलता को रोकने या बढ़ाने के लिये RBI बैंक दर में बढ़ोतरी या कमी करता है।
- **खुला बाज़ार प्रचालन (Open Market Operation):** यह मौद्रिक नीति का महत्त्वपूर्ण उपकरण है। इसके तहत आरबीआई द्वारा खुले बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर अथवा खरीदकर तरलता पर नियंत्रण रखा जाता है।
- **सार्वजनिक ऋण (Public Debt):** भारत सरकार द्वारा आंतरिक व बाह्य उधारी लेने को लोक ऋण के रूप में जाना जाता है। आंतरिक ऋण में विक्रय योग्य प्रतिभूतियाँ, ट्रेज़री बिल्स, गैर विक्रय योग्य प्रतिभूतियाँ (14 दिवसीय इंटरमीडिएट ट्रेज़री बिल्स), क्षतिपूरक व अन्य बॉण्ड, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की जाने वाली प्रतिभूतियाँ, लघु बचतों के विरुद्ध प्रतिभूतियाँ शामिल हैं, जबकि बाह्य ऋण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुपक्षीय व द्विपक्षीय ऋण, IMF से ऋण, निर्यात ऋण (export credit) अनिवासी भारतीय जमा, रुपया ऋण, विदेशी सहायता, बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB) आदि शामिल हैं।
- **लोक राजस्व (Public Revenue):** लोक राजस्व विभिन्न सरकारी स्रोतों से प्राप्त वह आय है जिससे जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आवश्यक व्यय किये जा सकें। कर और गैर कर राजस्व के माध्यम से लोक राजस्व की प्राप्ति होती है। विविध प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों व गैर कर राजस्व, जैसे- फीस, अर्थदंड आदि से लोक राजस्व बनता है।

2014

1. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं का/के उद्देश्य है/हैं?

1. केंद्रीय बैंक को बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना।
2. बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित व तरल रखना।
3. व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना।
4. बैंकों को दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त कोष्ठ नकदी (वॉल्ट कैश) रखने को बाध्य करना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 | **(b) केवल 1 और 2**
(c) केवल 2 और 3 | **(d) 1, 2, 3 और 4**

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: विकल्प **(a)** सही है, क्योंकि सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं के तहत सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) के माध्यम से केंद्रीय बैंक बाज़ार में तरलता संकट न होने देने अथवा तरलता प्रबंधन के लिये बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण करता है। सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं के तहत वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा नकद, स्वर्ण, विदेशी मुद्रा या स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखना अनिवार्य है। अप्रैल 2016 में RBI ने सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) घटाकर 21.25% कर दिया।

2. शाखारहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं (बैंक साथी) की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन-सी सुविधा/सुविधाएँ प्राप्त होती है/हैं?

1. यह लाभार्थियों को अपने गाँव में अपने साहाय्य (Subsidies) और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाती है।

2. यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने व आहरण करने योग्य बनाती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 | **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों | **(d) न तो 1 और न ही 2**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: उपर्युक्त दोनों ही कथन सत्य हैं। मार्च 2011 में वित्तीय समावेशन के ज़रिये ग्रामीण भारत के रूपांतरण के लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार द्वारा जिस **'स्वाभिमान'** योजना की शुरुआत की गई, उसके तहत उक्त दोनों ही सेवाएँ ग्रामीणों को प्रदान की जाती हैं। अत: विकल्प **(c)** सही है। इस योजना के तहत दी जाने वाली अन्य सेवाएँ हैं-

- 2000 अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले बैंकरहित गाँवों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ देने का वायदा।
- ग्रामीण भारत में वित्तीय साक्षरता के संवर्द्धन में मदद करने के बजाय संचलन सुविधाओं (movement facilities), बैंक खातों को खोलना, आवश्यकता आधारित साख और धन प्रेषण सुविधाओं (remittance facilities) को प्रदान करना।
- लघु व सीमान्त किसानों के मध्य साख के लिये मांग को बढ़ाना।
- तकनीकों के इस्तेमाल के ज़रिये शाखारहित बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना।
- सूक्ष्म वित्त और सूक्ष्म पेंशन उत्पादों की लोगों तक पहुँच सुनिश्चित करना।।
- बैंकिंग सेवाएँ, जैसे- सेविंग्स बैंक, रीकरिंग डिपॉज़िट, सावधि जमा, धन प्रेषण (remittance), ओवरड्राफ्ट फेसिलिटी, किसान क्रेडिट कार्ड, जनरल क्रेडिट कार्ड और चेकों का संग्रहण आदि प्रदान कराना।

3. 'सीमान्त स्थायी सुविधा दर' तथा 'निवल मांग और सावधि देयताएँ' पदबन्ध कभी-कभी समाचार में आते रहते हैं। उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है?

(a) बैंक कार्य

(b) संचार नेटवर्किंग

(c) युद्ध कौशल

(d) कृषि उत्पादों की पूर्तिएवं मांग

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: ये दोनों ही पदबन्ध बैंक कार्य के संबंध में प्रयुक्त किये जाते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मौद्रिक नीति 2011-12 में सीमान्त स्थायी सुविधा की शुरुआत की जिसके तहत बैंक भारत के रिज़र्व बैंक से आपात स्थिति में रातभर के लिये (Overnight) धन उधार ले सकते हैं।

निवल मांग और सावधि देयताओं (NDTL) में दो प्रकार की देयताएँ शामिल हैं- मांग देयताएँ (बचत खाता, चालू खाता, डिमांड ड्राफ्ट आदि) एवं सावधि देयताएँ (सावधि जमाएँ, स्वर्ण जमाएँ आदि)। इनके आधार पर ही बैंक अपनी सी.आर.आर., एसएलआर, पीएसएल आदि आवश्यकताओं का मापन करता है।

4. किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है, तो वह

(a) अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटाएगा

(b) सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा

(c) अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा

(d) अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: ब्याज दर को घटाए जाने पर लोग बैंकों से विभिन्न कार्यों के लिये अधिक मात्रा में ऋण लेते हैं। इससे उन्हें अपना निवेश व्यय बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे उच्च समग्र मांग (higher aggregate demand) और आर्थिक संवृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है लेकिन समग्र मांग में वृद्धि के चलते मुद्रास्फीतिक दबाव भी सामने आ सकता है। ब्याज दर के घटने से बचत के प्रति उत्प्रेरणा (incentive) में कमी आएगी क्योंकि कम ब्याज दर बचत से बहुत अल्प रिटर्न प्रदान करती है। इसलिये लोग बचत के बजाय व्यय और निवेश को आगे आएंगे। सस्ता ऋण लागत व्यय व निवेश को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। **अत: विकल्प (c) सही है।**

2013

1. निम्नलिखित में से कौन-से मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है?

1. परिसंपत्तियों की तरलता | **2. शाखा विस्तार**

3. बैंकों का विलय | **4. बैंकों का समापन**

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 और 4 | **(b) केवल 2, 3 और 4**

(c) केवल 1, 2 और 3 | **(d) 1, 2, 3 और 4**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: वाणिज्यिक बैंकों के संदर्भ में नकद आरक्षित अनुपात (CRR), सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) आदि के माध्यम से रिज़र्व बैंक परिसंपत्तियों की तरलता को नियंत्रित करता है। रिज़र्व बैंक के अधिकार व कार्यक्षेत्र से संबंधित पहलू निम्नवत् हैं-

- भारतीय रिज़र्व बैंक शाखा विस्तार के मामलों में भी वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। वर्ष 2011 में आरबीआई ने अनुसूचित

वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाओं का 25 प्रतिशत (बैंकिंग सुविधा सहित) ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने का निर्देश दिया था।

- यदि कोई बैंकिंग कंपनी सांविधिक आवश्यकताओं से अनुरूपता रखने में असफल रहती है तो भी आरबीआई उसके समापन के लिये उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है।
- बैंकों के विलय के मामले में भी भारत का रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। वाणिज्यिक बैंक विलय के दौरान बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44-A के तहत प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हैं। इस मामले में आरबीआई ही बैंकों को निर्देशित करता है।

2. बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि-

(a) ब्याज की बाज़ार दर के गिरने की संभावना है

(b) केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज़े नहीं दे रहा

(c) केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है

(d) केंद्रीय बैंक महँगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। तरलता को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इस दर में आरबीआई द्वारा वृद्धि की जाती है। **बैंक दर में वृद्धि के चलते वाणिज्यिक बैंक भी अपने ग्राहकों पर उधारी दर या (Lending Rate) ब्याज दर बढ़ा देते हैं। फलतः लोग कम ऋण लेंगे और तरलता की समस्या का समाधान होगा।** इस प्रकार बैंक दर में वृद्धि का मतलब है कि केंद्रीय बैंक (RBI) संकुचित अथवा महँगी मुद्रा नीति (Tight money policy) का अनुसरण कर रहा है।

3. निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिये-

1. बैंकों के पास मांग जमा

2. बैंकों के पास सावधिक जमा

3. बैंकों के पास बचत जमा

4. करेंसी

इन परिसंपत्तियों का, तरलता के घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है-

(a) 1–4–3–2 **(b) 4–3–2–1**

(c) 2–3–1–4 **(d) 4–1–3–2**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: वे परिसंपत्तियाँ जो आसानी से मुद्रा में परिवर्तित हो सकती हैं, तरल परिसंपत्तियाँ कहलाती हैं। अत: विकल्प **(d)** सही है। करेन्सी अथवा मुद्रा सर्वाधिक तरल परिसंपत्ति है क्योंकि इसको आसानी से प्राप्त और प्रयोग किया जा सकता है। इसके उपरांत सर्वाधिक तरल परिसंपत्ति बैंकों के पास मांग जमा है। यह बैंकों के पास बचत जमा से अधिक तरल परिसंपत्ति है क्योंकि मांग जमा के तहत एटीएम अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से क्रय-विक्रय की आवश्यकताएँ पूरी की जा सकती हैं। बचत जमा तीसरी सर्वाधिक तरल परिसंपत्ति है क्योंकि R.D अथवा रीकरिंग डिपॉज़िट और पीपीएफ के रूप में जमा धन का भुगतान सावधि जमा (FD) के भुगतान से पहले संभव है। सावधि जमा सबसे कम तरल परिसंपत्ति है क्योंकि एक निश्चित समयावधि के पूर्व अथवा जमा के मेच्योर होने के पूर्व इसका भुगतान संभव नहीं होता।

4. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 'खुला बाज़ार प्रचालन' किसे निर्दिष्ट करता है?

(a) अनुसूचित बैंकों द्वारा RBI से ऋण लेना

(b) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना

(c) RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: खुला बाज़ार प्रचालन ऐसा बाज़ार प्रचालन (Market Operation) होता है जिसे भारत के रिज़र्व बैंक द्वारा संपादित किया जाता है। इसका प्रचालन सरकारी प्रतिभूतियों को बाज़ार से खरीदने अथवा उसे बेचने के ज़रिये किया जाता है। खुला बाज़ार प्रचालन से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य निम्नवत् हैं-

- इस प्रचालन का मुख्य उद्देश्य बाज़ार में एक स्थिर आधार पर रुपये की तरलता स्थितियों का समायोजन करना है।
- जब कभी भी आरबीआई यह महसूस करता है कि बाज़ार में तरलता आवश्यकता से अधिक है तो यह अपनी प्रतिभूतियों को बाज़ार में बेचकर बाज़ार से मुद्रा बाहर करने का मार्ग अपनाता है।
- इसी प्रकार से जब तरलता दशाएँ कमज़ोर होती हैं तो आरबीआई बाज़ार से प्रतिभूतियों को खरीदकर बाज़ार में मुद्रा अथवा तरलता प्रवाहित करना शुरू कर देता है।
- आरबीआई की इन सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय को खुले बाज़ार में संपन्न करने के कारण इसे 'खुला बाज़ार प्रचालन' (OMO) कहते हैं।

5. भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है?

(a) कृषि **(b) लघु (माइक्रो) एवं छोटे उद्यम**

(c) दुर्बल वर्ग **(d) उपर्युक्त सभी**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से आशय अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को ऋण देने से है जिन्हें विशेष व्यवस्था किये बिना समय पर व पर्याप्त मात्रा में साख (Credit) उपलब्ध नहीं हो पाता है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान के संबंध में जारी दिशानिर्देश के अनुसार, भारतीय व्यापारिक बैंकों तथा 20 से अधिक शाखा वाले विदेशी बैंकों के लिये न्यूनतम 40% ऋणदान प्राथमिक क्षेत्र के लिये करने की अनिवार्यता है। यद्यपि 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिये यह सीमा 32% है, किंतु वर्ष 2019-20 से इनके लिये भी प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान की अनिवार्यता को 40% कर दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र को 18% ऋणदान करने का प्रावधान किया गया है। सामान्यतया ये कम लागत वाले ऋण होते हैं, जो निम्नलिखित क्षेत्रों को दिये जाते हैं:

- कृषि और संबंधित गतिविधियाँ;
- लघु, छोटे एवं मध्यम उपक्रम;
- दुर्बल वर्ग को आवास (Housing) के लिये;
- छात्रों को शिक्षा के लिये;
- निर्यात साख (Export Credit) के लिये;
- सामाजिक अवसंरचना;
- नवीकरणीय ऊर्जा;
- अल्प आय समूहों एवं अन्य।

6. ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है/करते हैं?

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2. कृषि और ग्रामीण विकास के लिये राष्ट्रीय बैंक

3. भूमि विकास बैंक

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 2**

(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई थी। इन्हें गठित करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रों के लिये संस्थागत साख के विस्तार के लिये 'सहकारी साख संरचना' का सुदृढ़ चैनल विकसित करना है। यह ग्रामीण सीमान्त कृषकों व कृषि श्रमिकों को सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है। विकल्प **(b)** सही नहीं है, क्योंकि कृषि और ग्रामीण विकास के लिये राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) (NABARD) ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण प्रदान न कर सहकारी समिति, सूक्ष्मवित्तीय कंपनियों इत्यादि जैसे मध्यस्थों के माध्यम से ऋण प्रदान करता है। वैद्यनाथन समिति के सुझावों के आधार पर नाबार्ड ने केंद्रीय सहकारी बैंकों को धन देने के लिये अल्पकालिक बहुउद्देशीय साख उत्पाद का डिज़ाइन तैयार किया है।

भूमि विकास बैंक भी ग्रामीण परिवारों एवं कृषकों को सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है। भूमि को समतल करने, भूमि संरक्षण उपायों को अपनाने तथा भूमि निम्नीकरण (Land Degradation) को दूर करने हेतु ग्रामीण कृषकों को भूमि विकास बैंक ऋण प्रदान करता है।

2012

1. निम्नलिखित पर विचार कीजिये-

1. होटल तथा रेस्तराँ **2. मोटर परिवहन उद्योग**

3. समाचार पत्र प्रतिष्ठान **4. निजी चिकित्सा संस्थान**

उपर्युक्त में से किस इकाई/किन इकाइयों के कर्मचारी, 'कर्मचारी राज्य बीमा योजना' के अंतर्गत 'सामाजिक सुरक्षा' कवच प्राप्त कर सकते हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 **(b) केवल 4**

(c) केवल 1, 3 और 4 **(d) 1, 2, 3 और 4**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत भारत के कामगारों के लिये सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के प्रावधानों के अनुपालन में 24 फरवरी, 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना का उद्घाटन कानपुर (उ.प्र.) में किया गया था। निम्नलिखित इकाइयों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त है-

- निजी चिकित्सा एवं शैक्षणिक संस्थान।
- दुकान, होटल व रेस्तराँ।
- सिनेमा व प्रिव्यू थियेटर्स।
- मोटर परिवहन उद्योग।
- समाचार पत्र और विज्ञापन संस्थान, जहाँ 10 या अधिक व्यक्ति कार्य में लगे हों।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बैंकरों के बैंक (केंद्रीय बैंक) के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन-से हैं?

1. अन्य बैंक RBI के पास अपनी जमा संचित रखते हैं।

2. आवश्यकता के समय RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है।

3. RBI वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है।

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 2 और 3 **(b) केवल 1 और 2**

(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकरों के बैंक (केंद्रीय बैंक) के रूप में कार्य करता है। इसका आशय है-

- प्रत्येक बैंक को वैधानिक बाध्यता के तहत अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित न्यूनतम भाग रिज़र्व बैंक में नकद आरक्षित अनुपात (CRR) के रूप में रखना होता है। इस रूप में आरबीआई 'बैंकों के बैंक' के रूप में काम करता है। इस नकद आरक्षित से वह अनुसूचित बैंकों को संकट के समय ऋण उपलब्ध करा सकता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंकों अथवा वाणिज्यिक बैंकों को स्वीकृत प्रतिभूतियों के बदले ऋण अथवा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।
- RBI वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को परामर्श दरअसल RBI के नैतिक प्रत्यायन

(Moral Suasion) से संबंधित है। इसके तहत RBI वाणिज्यिक बैंकों को साख के नियंत्रित वितरण हेतु निर्देशित करता है।

3. लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि–

(a) बड़े बैंक प्रत्येक ज़िले में अपने कार्यालय खोलने का प्रयास करें

(b) विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा हो

(c) प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिये पृथक्-पृथक् ज़िलों को अपनाए

(d) सभी बैंक अपने पास जमा राशि जुटाने के लिये गहन प्रयास करें

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: लीड बैंक योजना के विचार की उत्पत्ति प्रो. डी.आर. गाडगिल की अध्यक्षता वाले अध्ययन समूह के निष्कर्षों से प्रभावित है। 1969 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम पर बनी नरीमन समिति ने **क्षेत्र दृष्टिकोण (Area Approach)** अपनाते हुए 'लीड बैंक योजना' की शुरुआत करने की सिफारिश की थी। इस क्षेत्र दृष्टिकोण (Area Approach) की इकाई ज़िला (District) होंगे तथा प्रत्येक ज़िला लीड बैंक की भूमिका को निभाने वाले बैंक को आवंटित किया जाएगा।

2011

1. 'आम आदमी बीमा योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–

1. इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुम्ब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिये।

2. बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष के आयु वर्ग में होना चाहिये।

3. योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे दो बच्चों तक के लिये नि:शुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: 'आम आदमी बीमा योजना' 2 अक्तूबर, 2007 को लागू की गई थी। इस योजना के मुख्य प्रावधान हैं–

- योजना के तहत देश के ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया अथवा आय अर्जित करने वाले किसी सदस्य की स्वाभाविक मौत एवं दुर्घटना से हुई मौत और आंशिक या स्थायी रूप से विकलांगता के लिये बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाना।
- यह योजना 18 से 59 आयु वर्ग के उन व्यक्तियों को जीवन और विकलांगता कवर प्रदान करती है जो 47 व्यावसायिक/पेशेवर समूहों, जिनमें ग्रामीण भूमिहीन परिवार शामिल हैं, के अंतर्गत आते हैं। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिये है।
- यह योजना प्राकृतिक मृत्यु होने पर ₹30 हज़ार, दुर्घटनावश मृत्यु होने पर ₹75,000, दुर्घटना के कारण आंशिक विकलांगता के लिये ₹37,500, दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता होने पर ₹ 75 हज़ार का बीमा कवर प्रदान करती है।
- यह योजना बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे अधिकतम दो बच्चों तक के लिये नि:शुल्क छात्रवृत्ति (प्रति बच्चा 100 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति अर्द्धवार्षिक आधार पर भुगतान के साथ) का प्रावधान करती है।

2. सूक्ष्म-वित्त (माइक्रोफाइनेंस) निम्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिये वित्तीय सेवाओं का प्रावधान कराता है। ये सेवाएँ उपभोक्ताओं और स्वरोज़गार में जुटे व्यक्तियों, दोनों को प्रदत्त की जाती हैं। सूक्ष्म-वित्त के अंतर्गत जो सेवा/सेवाएँ उपलब्ध की जाती है/हैं, वह है/वे हैं-

1. ऋण सुविधाएँ **2. बचत सुविधाएँ**

3. बीमा सुविधाएँ **4. निधि अंतरण सुविधाएँ**

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 1 और 4**

(c) केवल 2 और 3 **(d) 1, 2, 3 और 4**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: सूक्ष्म वित्त वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उपलब्ध कराया जाता है ताकि ग्रामीण व निर्धन लोगों को भी विभिन्न बैंकिंग सुविधाएँ मिल सकें। सूक्ष्म वित्त सेवाओं में शामिल हैं: ऋण सुविधाएँ, बचत सुविधाएँ, बीमा सुविधाएँ निधि अंतरण सुविधाएँ, कुछ गैर वित्तीय सेवाएँ जैसे प्रशिक्षण तथा काउन्सलिंग।

3. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले लोक-लुभावन ऋण (टीज़र लोन) क्यों आर्थिक चिंता के विषय हैं?

1. लोक-लुभावन ऋण (टीज़र लोन) अधोमुख्य ऋणों (सब-प्राइम लेंडिंग) के ही एक रूप समझे जाते हैं तथा बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता न हों।

2. देश में लोक-लुभावन ऋण (टीज़र लोन) मुख्यत: अनुभवहीन उद्यमियों को उत्पादन संबंधी अथवा निर्यात इकाइयाँ स्थापित करने के लिये दिये जाते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1 और न ही 2**

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: ऐसे गिरवी ऋण को टीज़र लोन (लोक-लुभावन ऋण) कहते हैं जिसमें ऋण पर देय ब्याज इस प्रकार से समायोजित होता है

कि शुरू में ब्याज दर कम हो पर कुछ वर्षों के बाद ब्याज दर में वृद्धि हो जाए। ऐसे ऋणों में ऋण लेने वाला कम ब्याज दर के कारण ऋण लेने के लिये आकृष्ट होता है तथा ऐसा माना जाता है कि यदि वह निर्धारित समय में ऋण का भुगतान नहीं करता है तो उसे ब्याज की ऊँची दर के हिसाब से ब्याज देना पड़ता है। टीज़र लोन 'सब-प्राइम लेंडिंग' का ही एक रूप समझा जाता है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप

(a) बाज़ार की तरलता बढ़ जाती है

(b) बाज़ार की तरलता घट जाती है

(c) बाज़ार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता

(d) वाणिज्यिक बैंक अधिक जमा पूंजी संगृहीत कर लेते हैं

सही उत्तर: **(a)**

व्याख्या: बैंक दर वह दर होती है जिस पर रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। यह दर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लिये जाने वाले उधार पर ब्याज दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है। इस दर के द्वारा रिज़र्व बैंक साख की उपलब्धता तथा साख की लागत को प्रभावित कर सकता है और इस प्रकार बैंकों की साख सृजन क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

राजकोषीय नीति एवं कर संरचना

2025

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

I. पूंजीगत प्राप्तियाँ देयता का सृजन करती हैं या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं।

II. उधार-ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं।

III. ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सृजन करता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-कौन से सही हैं?

(a) केवल I और II
(b) केवल II और III
(c) केवल I और III
(d) I, II और III

सही उत्तर: **(a)**

व्याख्या:

- पूंजीगत प्राप्तियाँ ऐसी प्राप्तियाँ होती हैं जिनसे या तो सरकार की देयता बढ़ती है (जैसे- ऋण लेना) या फिर सरकार की संपत्ति में कमी आती है (जैसे- विनिवेश)।
- **उदाहरण:** ऋण लेने से सरकार की देयताओं में वृद्धि होती है, जबकि सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) में से शेयरों की बिक्री से संपत्ति में कमी आती है।
- **अतः कथन I सही है।**
- उधार (जैसे- ऋण, बॉण्ड) से देयता का सृजन होता है, जिससे इन्हें पूंजीगत प्राप्तियों की श्रेणी में रखा जाता है।
- विनिवेश (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयरों की बिक्री) से परिसंपत्तियों में कमी आती है तथा इसे भी पूंजीगत प्राप्तियों की श्रेणी में रखा जाता है।

अतः कथन II सही है।

- सरकार द्वारा दिये गए ऋण पर प्राप्त ब्याज राजस्व प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति नहीं। इससे किसी देयता का सृजन नहीं होता है, बल्कि यह सरकार के लिये आय है।
- **उदाहरण :** राज्यों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिये गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज आवर्ती आय है और इसे गैर-कर राजस्व के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। **इसलिये कथन III सही नहीं है।**

अतः विकल्प (a) सही है।

2. मान लीजिये सरकार का राजस्व व्यय ₹ 80,000 करोड़ है और राजस्व प्राप्ति ₹ 60,000 करोड़ है। सरकारी बजट ₹10,000 करोड़ के उधार-ग्रहण और ₹ 6,000 करोड़ के ब्याज भुगतान को भी प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित कथनों में कौन-कौन से सही हैं?

I. राजस्व घाटा ₹ 20,000 करोड़ है।

II. राजकोषीय घाटा ₹ 10,000 करोड़ है।

III. प्राथमिक घाटा ₹4,000 करोड़ है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

(a) केवल I और II

(b) केवल II और III

(c) केवल I और III

(d) I, II और III

सही उत्तर: **(d)**

व्याख्या:

- **राजस्व घाटा (Revenue Deficit):** राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार का नियमित राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है।

राजस्व घाटा = राजस्व व्यय − राजस्व प्राप्तियाँ

= ₹80,000 **करोड़** − ₹60,000 **करोड़** = ₹20,000 **करोड़**

अतः कथन I सही है।

- **राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit):** राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी को दर्शाता है। यह कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है।

राजकोषीय घाटा = कुल उधार-ग्रहण = ₹10,000 करोड़

अतः कथन II सही है।

- **प्राथमिक घाटा (Primary Deficit):** प्राथमिक घाटा यह दर्शाता है कि चालू वित्तीय वर्ष के खर्चों (ब्याज भुगतान को छोड़कर) को पूरा करने के लिये सरकार को कितनी उधारी की आवश्यकता है।

  प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान

  = ₹10,000 करोड़ – ₹6,000 करोड़ = ₹4,000 करोड़

  इसलिये कथन III भी सही है।

अत: विकल्प (d) सही है।

3. किसी देश का राजकोषीय घाटा ₹50,000 करोड़ है। इसे गैर-ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से ₹10,000 करोड़ प्राप्त हो रहे हैं। उस देश की ब्याज देयताएँ ₹1,500 करोड़ हैं। उसका सकल प्राथमिक घाटा कितना है?

(a) ₹ 48,500 करोड़
(b) ₹ 51,500 करोड़
(c) ₹ 58,500 करोड़
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

सही उत्तर: *(a)*

व्याख्या:

- प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
  - राजकोषीय घाटा = ₹50,000 करोड़
  - ब्याज भुगतान = ₹1,500 करोड़
  - प्राथमिक घाटा = ₹50,000 करोड़ – ₹1,500 करोड़ = ₹48,500 करोड़

अत: विकल्प (a) सही है।

4. भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, निम्नलिखित में कौन-कौन से कथन सही हैं?

I. इसने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणामों में उन्नयन लाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिये वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक ₹ 4,800 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की है।

II. संघ के करों के निवल आगम का 45%, राज्यों के साथ बाँटा जाना चाहिये।

III. सभी राज्यों के लिये कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में ₹ 45,000 करोड़ रखे जाएँ।

IV. इसने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु कर प्रयास निकष (टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया) को फिर से आरंभ किया।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

(a) I, II और III **(b) I, II और IV**
(c) I, III और IV **(d) II, III और IV**

सही उत्तर: *(c)*

व्याख्या:

- 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को शैक्षणिक उपलब्धियों, विशेषकर स्कूली शिक्षा में सुधार के लिये प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2022–23 से 2025–26 की अवधि के लिये कुल ₹4,800 करोड़ की अनुदान राशि की अनुशंसा की है। यह अनुदान उन राज्यों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किया जाएगा, जो शैक्षणिक परिणामों और शिक्षा-क्षेत्र की सुशासन व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार दर्शाएंगे। **अत: कथन I सही है।**
- 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021–2026 की अवधि के लिये संघ करों की शुद्ध प्राप्तियों में से 41% राज्यों को स्थानांतरित करने की अनुशंसा की, जो 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित स्तर के अनुरूप है। हालाँकि, यह प्रतिशत प्रारंभ में सुझाये गए 42% से घटाया गया, ताकि नवगठित संघ राज्यक्षेत्रों— 'जम्मू-कश्मीर' तथा 'लद्दाख' की वित्तीय आवश्यकताओं को समायोजित किया जा सके। **अत: कथन II सही नहीं है।**
- 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को कुछ विशिष्ट कृषि सुधारों को लागू करने के लिये ₹45,000 करोड़ की प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन राशि देने की अनुशंसा की थी। **अत: कथन III सही है।**
- इसके अतिरिक्त, आयोग ने 'कर प्रयास' (Tax Effort) मानदंड को अपने क्षैतिज कर वितरण (Horizontal Tax Devolution) के सूत्र में पुन: शामिल किया, जिसे पहले हटा दिया गया था। इसका उद्देश्य राज्यों की बेहतर वित्तीय प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना और उसे पुरस्कृत करना था। इस मानदंड को 2.5% का भार (Weight) दिया गया। यह उस राज्य के कर-राजस्व और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के अनुपात के रूप में आँका जाता है तथा उन राज्यों को लाभ देता है जो अधिक राजस्व सृजन करते हैं। **अत: कथन IV भी सही है।**

अत: विकल्प (c) सही है।

2024

1. भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये:

(वस्तु)		(श्रेण)
1. किसान का हल	–	कार्यशील पूंजी
2. कंप्यूटर	–	स्थिर पूंजी
3. बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत	–	स्थिर पूंजी
4. पेट्रोल	–	कार्यशील पूंजी

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक **(b) केवल दो**
(c) केवल तीन **(d) सभी चार**

सही उत्तर: *(b)*

व्याख्या: अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी उत्पादन के उन साधनों को कहा जाता है, जो मनुष्यों द्वारा निर्मित होते हैं और जिनका उपयोग वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। सरल शब्दों में, यह वह इनपुट है जिसकी आवश्यकता उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर पड़ सकती है। इसे दो भागों में बाँटा जाता है- स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी।

- स्थिर पूंजी वह पूंजी है, जो उत्पादन प्रक्रिया में लंबे समय तक बनी रहती है। यह एक बार उपयोग से समाप्त नहीं होती है। **उदाहरणतया :** मशीनें, औज़ार, भवन, टैक्टर, कंप्यूटर और कारखाने।
- कार्यशील पूंजी वह पूंजी है, जो उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान खर्च या समाप्त हो जाती है। इसे परिवर्ती पूंजी भी कह सकते हैं। **उदाहरणतया :** कच्चा माल, ईंधन और नकदी रुपया आदि। **अतः युग्म 2 सही है।**
- उत्पादन के लिये कई तरह के कच्चे माल की ज़रूरत होती है, जैसे- बुनकर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला धागा, मशीनों और परिवहन में प्रयुक्त पेट्रोल या कुम्हार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी। साथ ही, उत्पादन के दौरान भुगतान करने और अन्य ज़रूरी सामान खरीदने के लिये हमेशा कुछ नकदी की ज़रूरत होती है। कच्चे माल और नकद को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। **अतः युग्म 3 सही नहीं है परंतु युग्म 4 सही है। अतः विकल्प (b) सही है।**

2022

1. किसी संगठन या कंपनी द्वारा किये गए व्यय के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

1. नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है।

2. ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है।

नीचे दिये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

सही उत्तर: (a)

व्याख्या:

- पूंजीगत व्यय एक कंपनी द्वारा संपत्ति, पौधों, भवनों, प्रौद्योगिकी या उपकरण जैसी भौतिक संपत्तियों को प्राप्त करने, अपग्रेड करने और बनाए रखने के लिये उपयोग की जाने वाली धनराशि है। पूंजीगत व्यय का उपयोग अक्सर किसी कंपनी द्वारा नई परियोजनाएँ या निवेश करने के लिये किया जाता है। **अतः कथन 1 सही है।**
- इक्विटी वित्तीयन किसी कंपनी के स्टॉक को नकदी के बदले में बेचकर किसी संगठन की तरलता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये धन जुटाने की एक विधि है, इसलिये इसे पूंजीगत व्यय में माना जाता है। **इसलिये कथन 2 सही नहीं है।**

अतः विकल्प (a) सही है।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋणग्रहण के लिये जाता है।

2. नीलामी में बाज़ार-संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ, आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**
(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1, न ही 2**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या:

- घरेलू वित्तीय बचत का तात्पर्य उस अधिशेष धन से है जिसे परिवार अपनी उपयोग आवश्यकताओं के वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश करते है। इनमें मुख्य रूप से बैंक जमा, बीमा प्रीमियम, पेंशन एवं भविष्य निधि और शेयरों व डिबेचरों में किया गया निवेश शामिल हैं।
- घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिये उपयोग में लाया जाता है। **अतः कथन (1) सही है।**
- बाज़ार ऋण - दिनांकित प्रतिभूतियाँ राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिये उपयोग किये जाने वाले प्रमुख साधन हैं। वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्रमशः अप्रैल-सितंबर और अक्तूबर-मार्च को कवर करने वाले दो छमाही जारी कैलेंडर के अनुसार नीलामी के माध्यम से जारी किये जाते हैं। **इसलिये कथन (2) सही है।**

अतः विकल्प (c) सही है।

2021

1. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है?

1. विस्तारकारी नीतियाँ

2. राजकोषीय प्रोत्साहन

3. मुद्रास्फीति सूचकांकन मज़दूरी (इनफ्लेशन-इंडेक्सिंग वेजेज़)

4. उच्च क्रय शक्ति

5. बढ़ती ब्याज दर

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 3, 4 और 5
(c) केवल 1, 2, 3 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: जब अर्थव्यवस्था में साधन लागत एकसमान रहती है, किंतु वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक हो जाती है तो उसे 'मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति' कहते हैं।

- मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति के कारणों में, लोगों की आय बढ़ने से उपजी उच्च क्रय शक्ति, सरकारी व्यय में तीव्र वृद्धि, बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में ऋण देना तथा जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीकरण आदि करने के परिणामस्वरूप मांग बढ़ना शामिल हैं।
- इसे विस्तारपूर्वक समझने का प्रयास करें तो, सरकार अर्थव्यवस्था में सकल मांग बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये राजकोषीय प्रोत्साहन के अंतर्गत 'कर प्रोत्साहन छूट' जैसी पहल कर सकती है।
- इस दृष्टिकोण के पीछे यह तर्क होता है कि यदि लोगों के कर अदायगी के भार को कम कर दिया जाए तो उनके पास व्यय करने या निवेश करने के लिये अधिक धन रहता है जो उच्च मांग को बढ़ावा देता है।
- परिणामस्वरूप उत्पादन की मांग बढ़ने से रोज़गार सृजन होता है, जिससे बेरोज़गारी में कमी आती है।
- इसके अलावा, सरकार अपने व्यय में वृद्धि कर आर्थिक विस्तार कर सकती है, जैसे– आधारभूत संरचना में निवेश के ज़रिये रोज़गार को बढ़ावा देकर मांग और विकास में वृद्धि की जा सकती है। **अतः विकल्प (a) सही है।**

2. आर्थिक मंदी के समय, निम्नलिखित में से कौन-सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है?

(a) कर की दरों में कटौती के साथ-साथ ब्याज दर में वृद्धि करना

(b) सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना

(c) कर की दरों में वृद्धि के साथ-साथ ब्याज दर में कमी करना

(d) सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना

सही उत्तर: **(b)**

व्याख्या: जब किसी देश की अर्थव्यवस्था लगातार दो तिमाही तक ऋणात्मक विकास दर अर्जित करती है तो इसे 'मंदी' कहा जाता है। मंदी का मूल कारण अर्थव्यवस्था में मांग का अभाव होता है। मंदी में अर्थव्यवस्था में निवेश तथा उत्पादन में गिरावट होती है। मंदी के प्रभाव को दूर करने के लिये सरकार के साथ केंद्रीय बैंक को क्रमशः विस्तारवादी राजकोषीय और मौद्रिक नीति का पालन करना चाहिये।

- कर की दरों में कटौती के साथ ब्याज दर में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में ऋण महँगा हो जाएगा, जिससे निवेश हतोत्साहित होगा, जो मंदी के समय वांछनीय नहीं है। **अतः विकल्प (a) सही नहीं होगा।**
- अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिये सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि एक उचित उपकरण है क्योंकि यह पुनर्निवेश को बढ़ावा देती है। जिससे जीडीपी और अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि होती है। इससे मांग में वृद्धि से मंदी से उबरने में मदद मिलती है। **अतः विकल्प (b) सही है।**
- कर दरों में वृद्धि से निवेशकों की आय में कमी होगी जो अर्थव्यवस्था में निवेश को हतोत्साहित करेगी। इसलिये मंदी के समय कर की दर में वृद्धि वांछनीय नहीं है। **अतः विकल्प (c) सही नहीं होगा।**
- सार्वजनिक परियोजनाओं पर खर्च में कमी मंदी के समय वांछनीय नहीं है क्योंकि इससे सरकारी खर्च में कमी होगी। **अतः विकल्प (d) सही नहीं होगा।**

3. भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन-सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है?

(a) स्थावर संपदा के क्रय और विलासितायुक्त आवास में निवेश के लिये संसाधनों का अपयोजन

(b) अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय

(c) राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास

(d) कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि

सही उत्तर: **(d)**

व्याख्या: राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान(एनआईपीएफपी) के अनुसार, 'काला धन वह धन है जिस पर कर की देनदारी तो बनती है लेकिन उसकी जानकारी कर विभाग को नहीं दी जाती है।' काला धन सरकार की आय में रुकावटें तो उत्पन्न करता ही है, साथ ही देश के सीमित वित्तीय साधनों को अवांछित दिशाओं में मोड़ देता है। इसमें अवैध तरीकों से अर्जित किया गया धन तथा कर योग्य, वह धन जिस पर कर न दिया गया हो, को काले धन की श्रेणी में रखा जाता है।

- काला धन के सृजन का एक स्रोत आपराधिक गतिविधियाँ भी हैं। इसमें अपहरण, तस्करी, नशीली दवाएँ, अवैध खनन, जालसाज़ी और घोटाले आदि आपराधिक गतिविधियाँ आती हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार जैसे रिश्वतखोरी और चोरी भी काले धन का प्रमुख स्रोत हैं। काले धन की उत्पत्ति का दूसरा स्रोत, कर अपवंचन है। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय आयकर के अंतर्गत है तथा वह आयकर की राशि को बचाने के लिये अपनी वास्तविक आय के स्थान पर कम आय को दर्शाता है तो वास्तविक आय और घोषित आय के बीच का अंतर काला धन कहलाता है। उल्लेखनीय है कि देश में काले धन के पैदा होने का सबसे बड़ा कारण यही है। विकल्प (a), (b) और (c) काले धन के सृजन और निवेश के तरीके हैं जबकि विकल्प (d) काले धन के निर्माण का प्रभाव है। **अतः विल्कप (d) सही होगा।**

2020

1. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से गैर-वित्तीय ऋण में सम्मिलित है/हैं?

1. परिवारों का बकाया गृह ऋण

2. क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि

3. राजकोष बिल (Treasury bills)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 1 और 2**

(c) केवल 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: गैर-वित्तीय ऋण में सरकारी संस्थाओं, घरों और व्यवसायों द्वारा जारी किए गए ऐसे क्रेडिट उपकरण शामिल होते हैं जो वित्तीय क्षेत्र में शामिल नहीं होते। इसके अंतर्गत औद्योगिक या वाणिज्यिक ऋण, ट्रेजरी बिल और क्रेडिट कार्ड शेष सम्मिलित हैं। **अतः विकल्प (d) सही है।**

2019

1. भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिये निम्नलिखित में से कौन-सा एक सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है?

(a) गैर-ज़रूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन

(b) भारतीय उधारकर्त्ताओं को रुपये मूल्यवर्ग के मसाला बॉण्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना

(c) विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना

(d) एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: भारतीय रुपये की गिरती कीमत को रोकने के लिये सरकार या RBI को ऐसे कदम उठाने चाहिये जो विदेशी मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाए या घरेलू मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करे। जबकि 'प्रसरणशील मौद्रिक नीति' इसके विपरीत कार्य करती है। **अतः विकल्प (d) सही है।**

2018

1. निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिये-

1. छिलका उतरे हुए अनाज

2. मुर्गी के अंडे पकाए हुए

3. संसाधित और डिब्बाबंद मछली

4. विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार-पत्र

उपर्युक्त मदों में से कौन-सा/से जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) के अंतर्गत छूट प्राप्त है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2 और 3**

(c) केवल 1, 2 और 4 **(d) 1, 2, 3 और 4**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) के अंतर्गत निम्नलिखित तीन वस्तुएँ- छिलका उतरा हुआ अनाज, मुर्गी के अंडे पकाए हुए तथा विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र को छूट प्राप्त है, अर्थात् इन पर कोई टैक्स/कर नहीं लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, जी.एस.टी. से छूट प्राप्त अन्य वस्तुओं में ताज़े फल व सब्ज़ियाँ, अनाज, फ्रेस मीट, बिंदी, सिंदूर, दूध, प्राकृतिक शहद, आटा, बेसन, स्टैम्प, कागज़ तथा हैंडलूम एवं प्रसाद शामिल हैं।

2. यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, तो

(a) विकल्प लागत शून्य होती है।

(b) विकल्प लागत की उपेक्षा की जाती है।

(c) विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है।

(d) विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से शासन को अंतरित कर दिया जाता है।

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, तो विकल्प लागत (Opportunity Cost) को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। **अतः कथन (c) सही विकल्प है।**

विकल्प लागत किसी अवसर या विकल्प के चूक जाने या छूट जाने की लागत है। यह उस लाभ के विपरीत है जो तब प्राप्त होता है जब कोई कार्य (जो नहीं किया गया) किया जाता है- यानी छूटा हुआ एक अवसर। यह अर्थशास्त्र में प्रयुक्त एक अवधारणा है। विकल्प लागत को सामान्यतया धन के रूप में परिभाषित किया जाता है लेकिन इसे समय, व्यक्ति, घंटे, यांत्रिक उत्पादन अथवा किसी भी निश्चित संसाधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं।

2. भारत सरकार कोष-पत्र (ट्रेज़री बिल) जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष-पत्र जारी नहीं करतीं।

3. कोष-पत्र ऑफर अपने सममूल्य से बट्टे पर जारी किये जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 3**

(c) केवल 2 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (c)

व्याख्याः

- रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र और राज्य सरकारों के खाते प्रबंधित करने के साथ-साथ उनके लिये व्यापारिक बैंक की भूमिका निभाता है। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के बाज़ार के विकास और व्यवस्थित कार्य संचालन को बढ़ावा दिया जाता है तथा यह केंद्र और राज्य सरकारों को बेहतर नकदी प्रबंधन की सलाह देता है।
- भारत सरकार (केंद्र सरकार) ट्रेज़री बिल जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें कोई ट्रेज़री बिल जारी नहीं करतीं।
- ट्रेज़री बिल ऑफर अपने सममूल्य से बट्टे पर जारी किये जाते हैं। अतः केवल कथन 2 और 3 सही हैं।

2017

1. मौद्रिक नीति समिति (मोनेटरी पॉलिसी कमिटी/MPC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. यह RBI की मानक (बेंचमार्क) ब्याज दरों का निर्धारण करती है।

2. यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें RBI का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है।

3. यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 1 और 2**

(c) केवल 3 **(d) केवल 2 और 3**

सही उत्तरः (a)

व्याख्याः मौद्रिक नीति समिति (MPC) केंद्रीय बैंक की एक समिति है जिसका नेतृत्व आर.बी.आई. के गवर्नर द्वारा किया जाता है। इसे RBI अधिनियम, 1934 में संशोधन के बाद स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य बेंचमार्क नीति दर (रेपो रेट) तय करना है ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। एम.पी.सी. के छः सदस्य होंगे। **अतः विकल्प (a) सही है।**

2. 'बेनामी संपत्ति लेन-देन का निषेध अधिनियम, 1988 (PBPT अधिनियम)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. किसी संपत्ति का लेन-देन बेनामी लेन-देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन-देन के बारे में अवगत नहीं है।

2. बेनामी पाई गई संपत्तियाँ सरकार द्वारा ज़ब्त किये जाने के लिये दायी होंगी।

3. यह अधिनियम जाँच के लिये तीन प्राधिकारियों का उपबंध करता है किंतु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) केवल 1 और 3 **(d) केवल 2 और 3**

सही उत्तरः (b)

व्याख्याः हाल ही में संशोधित किये गए बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम, 1988 के अनुसार बेनामी संपत्तियों को सरकार द्वारा ज़ब्त किया जा सकता है, जबकि किसी विवाद की दशा में इस अधिनियम में अपीलीय क्रियाविधि की व्यवस्था की गई है। अतः कथन 3 असत्य है।

3. 'वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स ऐंड सर्विसेज़ टैक्स/GST)' के क्रियान्वित किये जाने का/के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है/हैं?

1. यह भारत में बहु-प्राधिकरणों द्वारा वसूल किये जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाज़ार स्थापित करेगा।

2. यह भारत के 'चालू खाता घाटे' को प्रबलता से कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा।

3. यह भारत की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और आकार को बृहद रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 2 और 3**

(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तरः (a)

व्याख्याः वस्तु एवं सेवा कर की अवधारणा पूरे देश में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित एकल कर के रूप में विकसित की गई है, जबकि चालू खाते घाटे का संबंध व्यापार संतुलन से है। जीएसटी को लागू किये जाने से भारत की अर्थव्यवस्था को अवश्य ही मज़बूती मिलेगी, किंतु यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि यह भविष्य में चीन से आगे होगी।

2016

1. साल-दर-साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी कार्रवाई/कार्रवाइयाँ की जा सकती है/हैं?

1. राजस्व व्यय को घटाना

2. नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारम्भ करना

3. सहायिकी (सब्सिडी) को युक्तिसंगत बनाना

4. आयात शुल्क को कम करना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 2 और 3**

(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2, 3 और 4**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: साल-दर-साल लगातार घाटे का बजट रहा है। इस घाटे को कम करने के लिये सरकार द्वारा राजस्व व्यय को कम किया जा रहा है तथा सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नवीन कल्याणकारी योजनाओं का प्रारंभ एवं आयात-शुल्क को कम करना, बजट घाटे को कम करने हेतु की जाने वाली कार्रवाइयाँ नहीं हैं। अत: कथन 1 और 3 सत्य हैं।

घाटे के बजट को निम्न तरीकों से कम किया जा सकता है-

- गैर-ज़रूरी सब्सिडी को खत्म किया जाए तथा बाकी सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया जाए।
- राजस्व व्यय को भी कम किया जाना चाहिये।
- कर संरचना में सुधार किया जाना चाहिये। भारत सरकार को जल्द-से-जल्द जीएसटी को सम्पूर्ण देश में लागू करना होगा।
- सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के लाभ में वृद्धि करनी होगी।
- काले धन की वापसी एवं गैर-निष्पादनकारी सम्पत्तियों की पहचान कर उन्हें अर्थव्यवस्था में लगाना।
- सरकारी दफ्तरों एवं मंत्रियों पर होने वाले बड़े-बड़े खर्चों को भी थोड़ा कम करके बजट घाटे में सुधार किया जा सकता है।

2. निम्नलिखित में से किसको/किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है?

1. सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय

2. विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण

3. राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 2 और 3**

(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: भारत सरकार के पूंजी बजट में विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋणों, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को अनुदत्त ऋणों तथा सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण व्यय आदि सभी को शामिल किया जाता है।

पूंजी बजट में पूंजीगत प्राप्तियाँ और भुगतान शामिल होते हैं। इसमें सार्वजनिक खाते में किये गए लेन-देन शामिल किये जाते है पूंजीगत प्राप्तियाँ सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार होता है। जिन्हें बाज़ार ऋण कहा जाता है। सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक व अन्य पक्षों, राजकोषीय बिलों के विक्रय के माध्यम से उधार लिया जाता है। विदेशी सरकारों और निकायों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों व अन्य पक्षों को दिये गए ऋणों की वसूली शामिल है। पूंजीगत भुगतानों में भूमि, भवन, मशीनों और उपकरणों जैसी परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिये किये गए पूंजीगत व्यय, साथ ही अंशभागों में निवेश, केंद्र द्वारा राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, और अन्य पक्षों को प्रदान किये गए ऋण और उधार शामिल हैं।

3. समाचारों में कभी-कभी देखे जाने वाले 'आधार क्षय एवं लाभ स्थानान्तरण (Base Erosion and profit Shifting)' पद का क्या संदर्भ है?

(a) संसाधन-सम्पन्न किंतु पिछड़े क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा खनन कार्य।

(b) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किये जाने वाले कर-अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना।

(c) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किसी राष्ट्र के आनुवंशिक संसाधनों का दोहन।

(d) विकास परियोजनाओं की योजना एवं कार्यान्वयन में पर्यावरणीय लागतों के विचारों का अभाव।

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: आधार क्षय एवं लाभ स्थानांतरण से आशय कर-अपवंचन रणनीतियों से है, जिनके माध्यम से अर्जित लाभ को कृत्रिम ढंग से ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जहाँ कर की दर अत्यंत निम्न अथवा शून्य होती है।

2015

1. चौदहवें वित्त आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है।

2. इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े (सेक्टर-स्पेसिफिक) अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की हैं।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1 और न ही 2**

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: 14वें वित्त आयोग द्वारा 2015–16 से 2020–21 की अवधि के लिये की गई प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

- केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा वर्तमान 32 प्रतिशत से बढ़ाकर मूलत: 42 प्रतिशत किया जाए। अत: कथन (1) सही है। 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 42 प्रतिशत से घटाकर 41 प्रतिशत किया गया है।
- आयोग ने राज्यों के बीच विभाज्य पूल में राज्य हिस्से के वितरण के लिये नए क्षैतिज सूत्र का भी सुझाव दिया है। 13वें वित्त आयोग

की अपेक्षा 14वें वित्त आयोग ने दो नए परिवर्तनीय कारक जोड़े हैं- 2011 की जनसंख्या और वन क्षेत्र तथा राजकोषीय अनुपालन कारक को निकाल दिया गया है।

- 14वें वित्त आयोग ने 13वें वित्त आयोग के विपरीत सेक्टर विशिष्ट अनुदानों से संबंधित कोई सिफारिश नहीं की है। अतः कथन (2) सही नहीं है। कई अन्य प्रकार के अंतरणों का सुझाव दिया गया है, जिनके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान, आपदा राहत के लिये अनुदानों सहित निष्पादन अनुदान और राजस्व घाटा से संबंधित सुझाव सम्मिलित हैं। 2015–20 की अवधि के लिये ये अंतरण कुल मिलाकर लगभग 5.3 लाख करोड़ रुपये के हैं।

2. किसी देश की, कर से GDP के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है?

1. आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना

2. राष्ट्रीय आय का कम साम्यिक (एक्विटेबल) वितरण

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1 और न ही 2**

सही उत्तर: **(a)**

व्याख्या: कर से GDP के अनुपात (Tax to GDP ratio) में कमी का अर्थ है कि GDP के अनुपात में कर संग्रहण की मात्रा में कमी। आर्थिक विकास दर धीमी होने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का कुल संग्रहण कम हो जाता है। अतः केवल कथन 1 सही है।

3. वर्ष-प्रतिवर्ष निरन्तर घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी कार्रवाई/कार्रवाइयाँ की जा सकती है/हैं?

1. राजस्व व्यय में कमी लाना

2. नई कल्याणकारी योजनाएँ आरम्भ करना

3. उपदानों (सब्सिडीज़) का युक्तीकरण करना

4. उद्योगों का विस्तार करना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1

(d) 1, 2, 3 और 4

सही उत्तर: **(a)**

व्याख्या: घाटे को कम करने के लिये सरकार द्वारा की जा सकने वाली कार्रवाइयों में शामिल हैं: राजस्व व्यय में कमी लाना तथा उपदानों (सब्सिडीज़) का युक्तीकरण करना, कर सुधार करना तथा कर का अपवंचन रोकना। घाटे को कम करने से संबंधित कुछ अन्य पहलू निम्नवत् हैं-

- नई कल्याणकारी योजनाएँ आरंभ करने से घाटे में कमी नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसी योजनाओं के वित्तीयन हेतु भारी मात्रा में धनराशि की ज़रूरत होती है। वस्तुतः नई कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय गैर-योजनागत व्यय का भाग होता है जिससे सरकार के पास स्थायी उत्पादकीय परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता। अतः कथन (2) गलत है।
- उद्योगों के विस्तार के लिये सरकार को उन्हें कई प्रोत्साहन (जैसे कर छूट आदि) देने पड़ते हैं। अतः सरकार का व्यय बढ़ता है, न कि घटता है। इस प्रकार, यह घाटे के नियंत्रण का माध्यम नहीं हो सकता। अतः कथन (4) गलत है। इस प्रकार समग्र रूप से विकल्प **(a)** सही है।

2014

1. संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से गैर-योजना व्यय के अधीन आता है/आते हैं?

1. रक्षा व्यय

2. ब्याज अदायगी

3. वेतन एवं पेंशन

4. उपदान

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 2 और 3**

(c) 1, 2, 3 और 4 **(d) कोई नहीं**

सही उत्तर: **(c)**

व्याख्या: योजनागत व्यय के अलावा सभी व्यय जो सरकार की सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं से संबंधित होते हैं, वे गैर-योजनागत व्यय कहलाते हैं। बजट 2016-17 के आयोजना भिन्न व्यय नामक खंड में निम्नांकित को गैर-योजनागत व्यय के रूप में वर्णित किया गया है-

- ब्याज संबंधी अदायगियाँ और ऋण शोधन
- रक्षा
- मुख्य सब्सिडियाँ (उर्वरक सब्सिडी, आयातित (यूरिया) उर्वरक, पेट्रोलियम सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, ब्याज सब्सिडियाँ तथा हज सब्सिडी आदि।
- राज्यों को राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (NDRF) से सहायता।
- डाक संबंधी घाटा, वेतन तथा पेंशन।
- शिक्षा, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं पर व्यय। पुलिस और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रकों में व्यय।
- विदेशी सरकारों को अनुदान।

2013

1. भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिये संसाधनों को बढ़ाने के लिये उपयोग की जाती है?

(a) आर्थिक विकास के लिये

(b) सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिये

(c) भुगतान शेष का समायोजन करने के लिये

(d) विदेशी ऋण कम करने के लिये *सही उत्तर:* (a)

व्याख्या: जब घरेलू संसाधन तथा बाह्य सहायता सम्मिलित रूप से भी विकासात्मक खर्च की पूर्ति में अपर्याप्त सिद्ध हो जाते हैं तब वहाँ की सरकार घाटे के वित्तीय पोषण के लिये बाध्य होती है। यह स्थिति सामान्यत: विकासशील अथवा अल्प विकसित देशों में आती है जहाँ आय का स्तर तो निम्न होता है किंतु उपभोग की प्रवृत्ति उच्च होती है, परिणामत: बचत काफी कम हो जाती है। इस दशा में सरकार का दायित्व बनता है कि विकास कार्यों को सहज बनाए रखने के लिये संसाधनों का संवर्द्धन करे। यह अतिरिक्त राशि की मांग करती है जिसकी पूर्ति निम्नांकित तरीकों से की जाती है-

- केंद्रीय बैंक से उधार
- वाणिज्यिक बैंकों से उधार
- नई मुद्रा का सृजन

भारत सरकार पंचवर्षीय कार्यक्रमों के लिये वित्त आपूर्ति को इस माध्यम से पूरा करती है। अत: विकल्प **(a)** सही है।

2012

1. निम्नलिखित में से कौन-सी अनुशंसा/अनुशंसाएँ तेरहवें वित्त आयोग की सुस्पष्ट विशिष्टता/विशिष्टताएँ है/हैं?

1. वस्तुओं व सेवाओं पर कर (टैक्स) लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन से सम्बद्ध क्षतिपूर्ति पैकेज

2. भारत के जनांकिकीय लाभांश के अनुरूप अगले दस वर्षों में लाखों नौकरियाँ सृजन करने की योजना

3. केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 2 और 3**

(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: 13वाँ वित्त आयोग (अध्यक्ष- विजय केलकर) जिसने वर्ष 2010-15 की समयावधि के लिये सिफारिशें दीं, उनमें से मुख्य निम्नवत् हैं:

- 2010-11 से 2014-15 के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल बँटवारे योग्य केंद्रीय कर संग्रहण में 32 प्रतिशत हिस्सा राज्यों का होना। 11वें व 12वें वित्त आयोग ने इसे क्रमश: 29.5% और 30.5% करने की सिफारिश की थी।
- 13वें वित्त आयोग ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) को अपनाने की अनुशंसा की थी। आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों द्वारा जीएसटी को अपनाने से होने वाली क्षतियों की भरपाई के लिये ₹ 50 हज़ार करोड़ की राशि में से अनुदान दिया जाना चाहिये।
- केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश (**2.**28%) का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण।
- आयोग ने वस्तुत: प्रचलित कार्यक्रमों के ही बेहतर क्रियान्वयन पर बल देने की सिफारिश की थी। अत: कथन (2) आयोग की अनुशंसा से संबंधित नहीं है।

2011

1. निम्नलिखित में से कौन-सी 'मूल्य आधारित कर' (वैल्यू एडेड टैक्स) की विशेषता नहीं है?

(a) यह बहु-बिंदु लक्ष्य आधारित कर (टैक्सेशन) प्रणाली है

(b) यह उत्पादन/वितरण शृंखला में लेन-देन के हर चरण में हुए मूल्य-संवर्द्धन पर लगाया गया कर (टैक्स) है

(c) यह वस्तुओं तथा सेवाओं पर उपभोग के अंतिम चरण में लगाया गया कर (टैक्स) है जिसका वहन अंतत: उपभोक्ताओं को करना पड़ता है

(d) यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार का विषय है; और राज्य सरकारों का दायित्व इसे सफलता के साथ लागू करने तक सीमित है *सही उत्तर:* (d)

व्याख्या: भारत में मूल्यवर्धित कर (वैट) 1 अप्रैल, 2005 से 22 राज्यों एवं 7 केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया था। इसके बाद इसे जनवरी 2007 में तमिलनाडु, पुदुच्चेरी में और 2008 में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था।

2. भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSEs) में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है?

1. सरकार अपनी इक्विटी के विनिवेश से मिले राजस्व का उपयोग मुख्यत: अपने बाह्य ऋण को लौटाने में करना चाहती है।

2. सरकार अब CPSEs के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1 और न ही 2**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: विकल्प **(d)** सही है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSEs) में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश यानी उद्यमों में अपनी वित्तीय साझेदारी अथवा अंशधारिता को कम करने का उद्देश्य बाह्य ऋण लौटाना अथवा इन उद्यमों के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में रखने की इच्छा नहीं है।

भुगतान संतुलन एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

2023

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

कथन-I : वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है।

कथन-II : भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की 'उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव)' योजना का लाभ उठाया है।

उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।

(c) कथन-I सही है किंतु कथन-II गलत है।

(d) कथन-I गलत है किंतु कथन-II सही है।

सही उत्तर: **(d)**

व्याख्या: विश्व व्यापार संगठन की वैश्विक व्यापार आउटलुक एवं स्टेटिक्स रिपोर्ट के अनुसार, भारत वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में 1.8% से 2% के बीच की हिस्सेदारी रखता है। **अतः कथन I गलत है।**

- वर्ष 2024 के लिये अनुमानित 3.2% के लक्ष्य तक पहुँचने से पूर्व वर्ष 2023 में विश्व वाणिज्यिक वस्तु व्यापार की मात्रा में 1.7% वृद्धि का अनुमान है।
- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव) योजना कंपनियों को भारत में निर्मित उत्पादों के वृद्धिशील विक्रय पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसका उद्देश्य विदेशी कंपनियों को भारत में इकाइयाँ स्थापित करने के लिये आकर्षित करना है, जबकि स्थानीय कंपनियों को अपनी विनिर्माण इकाइयों का विस्तार करने एवं अधिक रोज़गार सृजन करने तथा आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिये प्रोत्साहित करना है। **इसलिये कथन II सही है।**

अतः विकल्प (d) सही है।

2. केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यू.एस. डॉलर या एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी. प्रणाली का प्रयोग किये बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है।

2. कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध, जैसे कि इसके व्यय के समय-ढाँचे के साथ वितरित की जा सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1 और न ही 2**

सही उत्तर: **(c)**

व्याख्या:

- केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा नोटों का एक डिजिटल रूप है। इसके अंतर्गत डिजिटल मुद्रा में भुगतान US डॉलर या स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग किये बिना होता है। यह फिनटेक और डिजिटल संप्रभुता के नज़रिये से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। **अतः कथन 1 सही है।**
- CBDC को दो व्यापक प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्य प्रयोजन या खुदरा (CBDC-R) और थोक (CBDC-W)।
- खुदरा CBDC संभावित रूप से सभी के उपयोग के लिये, जैसे कि निजी क्षेत्र, गैर-वित्तीय उपभोक्ता एवं व्यवसाय आदि, उपलब्ध होता है जबकि थोक CBDC को कुछ चयनित वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुँच के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- थोक CBDC इंटरबैंक ट्रांसफर और संबंधित थोक लेनदेन के निपटान के लिये अभिप्रेत करता है, जबकि खुदरा CBDC मुख्य रूप से खुदरा लेनदेन के लिये नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है।
- **प्रोग्रामयोग्यता:** CBDC का एक **महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोग प्रोग्रामयोग्यता की तकनीकी संभावना है।** CBDC के पास अंतिम उपयोग को संदर्भित कर मुद्रा की प्रोग्रामिंग करने की संभावना होती है। उदाहरण के लिये, बैंकों द्वारा कृषि ऋण को यह सुनिश्चित करने के लिये प्रोग्राम किया जा सकता है कि इनका उपयोग केवल कृषि आवश्यक सामग्रियों की दुकानों पर ही किया जाए।
- हालाँकि, किसी मुद्रा की आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के लिये CBDC की प्रोग्राम योग्यता सुविधा का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने की आवश्यकता है। मौद्रिक नीति प्रसारण के लिये इसके अन्य निहितार्थ भी हो सकते हैं क्योंकि टोकन की समाप्ति तिथि हो सकती है, जो कि उन्हें खर्च करने की आवश्यकता को निर्धारित करेगा एवं इस प्रकार खपत सुनिश्चित हो सकेगी। **अतः कथन 2 सही है।**

अतः विकल्प (c) सही है।

- निम्नलिखित का उपयोग करके टोकन की प्रोग्राम योग्यता प्राप्त की जा सकती है:
  - **स्मार्ट अनुबंध:** व्यावसायिक नियमों को संहिता के रूप में संगृहीत किया जाता है जो लेन-देन के दौरान निष्पादित किया जाता है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि टोकन का सही उपयोग किया जा रहा है।

- **टोकन संस्करण:** टोकन संस्करण को तकनीकी कोड वर्ग से संबद्ध किया जा सकता है। इसमें विकल्प यह है कि संस्करण को टोकन डाटा फील्ड के रूप में संगृहीत किया जाता है।

2022

1. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. अंकित प्रभावी विनिमय दर (Nominal Effective Exchange Rate – NEER) में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि को दर्शाता है।

2. वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (Real Effective Exchange Rate – REER) में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है।

3. अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति NEER और REER के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 2 और 3**

(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: **(c)**

व्याख्या:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) 36 व्यापारिक साझेदार देशों की मुद्राओं के संबंध में रुपये की 'नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट' (Nominal Effective Exchange Rate-NEER) को सारणीबद्ध करता है। सरल शहरों में, NEER भारत के व्यापारिक भागीदारों की मुद्राओं के एक बास्केट (समूह) के मुकाबले रुपये का भारित औसत है।
- यदि NEER बढ़ता है, तो इसका अर्थ है रुपया औसतन अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में मज़बूत हो रहा है। NEER में वृद्धि का सीधा अर्थ है- रुपये का अधिमूल्यन। **अतः कथन (1) सही है।**
- REER सामान्यतः NEER ही है लेकिन इसमें मुद्रास्फीति के अंतर को भी समायोजित किया जाता है। NEER के अतिरिक्त 'रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट' (Real Effective Exchange Rate-REER) भी भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों को मापने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मापदंड है।
- REER के अंतर्गत NEER में शामिल अन्य कारकों के अतिरिक्त विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू मुद्रास्फीति को भी ध्यान में रखा जाता है, जिसके कारण इसका महत्त्व अधिक बढ़ जाता है।
- यदि किसी देश का REER बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि उस देश में वस्तुएँ और सेवाएँ उसके व्यापारिक भागीदरों की तुलना में महँगी हो गई हैं। जब हमारी वस्तुएँ महँगी होंगी, तो विदेशों में उनकी मात्रा कम होगी। इसलिये REER में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्द्धात्मकता में गिरावट को दर्शाती है, सुधार को न हीं। **अतः कथन (2) गलत है।**
- REER की गणना NEER में मूल्य परिवर्तन को समायोजित करने के पश्चात् की जाती है। इस प्रकार अर्थशास्त्री NEER की अपेक्षा REER को अधिक महत्त्व देते हैं।
- NEER = विशेष आहरण अधिकार (SDR) के संदर्भ में घरेलू विनिमय दर/विशेष आहरण अधिकार (SDR) के संदर्भ में विदेशी विनिमय दर
- REER=NEER × (घरेलू मूल्य सूचकांक/विदेशी मूल्य सूचकांक)। **इसलिये कथन (3) सही है।**

अतः विकल्प (c) सही है।

2. भारत में कार्य कर रही विदेशी-स्वामित्व की e-वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

1. अपने प्लेटफॉर्मों को बाज़ार-स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं।

2. वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है।

नीचे दिये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1, न ही 2**

सही उत्तर: **(d)**

व्याख्या:

- e-वाणिज्य की नियमावली के आधार पर, बाज़ार-स्थान प्रदान करने वाली ई-कॉमर्स संस्थाएँ इन्वेंट्री यानी बेची जाने वाली वस्तुओं पर स्वामित्व का प्रयोग नहीं करेंगी। इन्वेंट्री पर इस तरह का स्वामित्व व्यवसाय को एक इन्वेंट्री आधारित मॉडल में प्रस्तुत करेगा। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- एक ई-वाणिज्य इकाई अपने बाज़ार-स्थान के माध्यम से प्रभावित बिक्री के 25% से अधिक पर एक विक्रेता को अनुमति नहीं देगी। अतः इसकी सीमा का निर्धारण किया गया है। हालाँकि संघ लोक सेवा आयोग ने कथन-2 को भी सही नहीं माना है।

अतः विकल्प (d) सही है।

2021

1. निम्नलिखित पर विचार कीजिये-

1. विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉण्ड

2. कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश

3. वैश्विक निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) प्राप्तियाँ

4. अनिवासी विदेशी जमा

उपर्युक्त में से किसे/किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है/किये जा सकते हैं?

(a) 1, 2 और 3 **(b) केवल 3**

(c) 2 और 4 **(d) 1 और 4**

सही उत्तर: **(a)**

व्याख्याः समेकित एफडीआई नीति, 2020 के अनुसार विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉण्ड (Foreign Currency Convertible Bonds) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल किये जाते हैं। अतः कथन (1) सही है।

- विदेशी संस्थागत निवेश को विदेश प्रत्यक्ष निवेश में शामिल किया जाता है। उल्लेखनीय है कि विदेशी संस्थागत निवेश 24 प्रतिशत की समग्र सीमा की शर्त के अधीन हैं। अतः कथन (2) सही है।
- इसी तरह वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें (GDR) भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का साधन हैं। अतः कथन (3) सही है।
- अनिवासी विदेशी जमा भुगतान संतुलन खाते में एक ऋण सृजन प्रवाह है। अतः कथन (4) सही नहीं है। **अतः विकल्प (a) सही होगा।**

2020

1. यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है, तो निम्नलिखित में से कौन-से कार्य/नीतियाँ, भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ, कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है/हैं?

1. अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना
2. कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना
3. पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 1 और 2**
(c) केवल 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तरः (a)

व्याख्याः वित्तीय संकट निम्न स्वरूप में उभर कर सामने आता है-

- व्यावसायिक क्रियाकलापों में कम-से-कम लगातार दो तिमाहियों तक गिरावट हो।
- वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन में गिरावट आना।
- सकल घरेलू उत्पाद, रोज़गार, निवेश व्यय, क्षमता-उपयोग, पारिवारिक आय तथा व्यापारिक लाभ आदि सभी में गिरावट आती है।
- सरकार की नीतियों को भी वित्तीय संकट का कारण माना जाता है। यदि सरकार बचत का बजट बनाती है, भारी टैक्स लगाती है, कठोर लाइसेंस नीति अपनाती है, निर्यातों पर रोक लगाती है, विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करती है या फिर उद्योग-धंधों को बढ़ावा देने की नीति नहीं अपनाती तो निश्चित तौर पर वित्तीय संकट की स्थिति को आमंत्रित करती है।

वित्तीय संकट से उन्मुक्ति हेतु निम्नलिखित उपाय हैं-

- अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना क्योंकि अल्पकालीन ऋण हमें संकट की ओर ले जाती है।
- विदेशी बैंकों की स्थापना से बचना चाहिये।
- भारत में पर्याप्त मात्रा में आधारभूत संरचना का अभाव है, जो कि विदेशी निवेशकों द्वारा स्थायी रूप से भारत में निवेश करने की राह में एक बाधा है। पूंजी खाते के संदर्भ में मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाने से संकट के समय में विदेशी पूंजी का उत्प्रवाह या बहिर्प्रवाह तेज़ी से होगा अतः हमारी वित्तीय स्थिति संकट में पड़ जाएगी।
- हमें संरक्षणवादी प्रवृत्तियों को अनुमति नहीं देनी चाहिये, चाहे वे सामानों के व्यापार का संरक्षणवाद हो, लोगों की मुफ्त आवाजाही संबंधी संरक्षणवाद हो, वित्तीय सेवाओं में संरक्षणवाद हो अथवा गैर-टैरिफ बाधाओं से संबंधित संरक्षणवाद हो। **अतः विकल्प (a) सही है।**

2. 'स्वर्ण-ट्रांश' (रिज़र्व ट्रांश) निर्दिष्ट करता हैः

(a) विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था
(b) केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को
(c) WTO द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को
(d) IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को

सही उत्तरः (d)

व्याख्याः

- 'स्वर्ण-ट्रान्श' (रिज़र्व ट्रान्श) मुद्रा के आवश्यक कोटा का एक हिस्सा है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के प्रत्येक सदस्य देश के पास होना चाहिये जिसे आईएमएफ द्वारा प्रदान किया जाता है।
- बिना सेवा शुल्क दिये अपने उद्देश्य के लिये आईएमएफ के सदस्य देश इसका उपयोग कर सकते हैं। अतः विकल्प (d) सही है।

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. पिछले दशक में भारत-श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है।
2. भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में 'कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों' का व्यापार प्रमुख है।
3. पिछले पाँच वर्षों में, दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

सही उत्तरः (b)

व्याख्याः

- भारत और श्रीलंका के बीच एक ठोस व्यापार और निवेश संबंध हैं तथा पिछले दशक के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई है, लेकिन सतत वृद्धि नहीं हुई है। अतः कथन (1) सही नहीं है।
- भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में "कपड़े और कपड़े से बनी चीजों" का व्यापार प्रमुख है। अतः कथन (2) सही है। इसे निम्न चित्र से समझ सकते हैं।

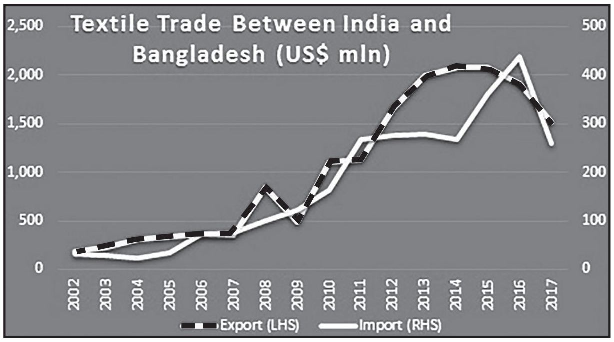

- पिछले 5 वर्षों में, दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार बांग्लादेश (2016-17 के आंकड़े के अनुसार) रहा है। अत: कथन (3) सही नहीं है। अत: विकल्प (b) सही है।

4. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है?

(a) यह मूलत: किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है।

(b) यह मुख्यत: ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है।

(c) यह ऐसा निवेश है जिससे ऋण-समाशोधन अपेक्षित होता है।

(d) यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है।

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: कोई भी कंपनी घरेलू स्रोतों के अलावा शेष विश्व से संसाधन ऋण के रूप में या निवेश के रूप में जुटाती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) भारत के बाहर के व्यक्तियों द्वारा गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की पूंजीगत लिखतों के माध्यम से किया गया निवेश अथवा सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पूर्णत: डाइल्यूटेड आधार पर जारी प्रदत्त इक्विटि के 10 प्रतिशत तक अथवा उससे अधिक निवेश है। अत: विकल्प (b) सही है।

5. वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं।

1. भारत के माल का निर्यात, माल के आयात से कम है।

2. भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है।

3. भारत की सेवाओं का निर्यात, सेवाओं के आयात से अधिक है।

4. भारत को कुल मिलाकर व्यापार/चालू खाते का घाटा हो रहा है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 2 और 4**

(c) केवल 3 **(d) केवल 1, 3 और 4**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: भारत से अप्रैल-मार्च 2019-20 में भारत के माल का निर्यात (314.31 अरब यूएस डॉलर) आयात (467.19 अरब यूएस डॉलर) की अपेक्षा कम है। वहीं भारत की सेवाओं का निर्यात (214.14 अरब यूएस डॉलर) आयात (131.41 अरब यूएस डॉलर) की अपेक्षा अधिक रहा है। इस दौरान लौह अयस्क को छोड़कर जिसने 58.43% की वृद्धि दर्ज की, अन्य सभी जिन्सों/जिन्स समूहों ने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। वहीं इस अवधि में कुल मिलाकर व्यापार/चालू खाते का घाटा (70.16 अरब यूएस डॉलर) रहा है। **अत: विकल्प (d) सही है।**

नोट: ध्यातव्य है कि संघ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर रखा है।

6. 'व्यापार-संबंधित निवेश उपायों' (TRIMS) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. विदेशी निवेशकों द्वारा किये जाने वाले आयात पर 'परिमाणात्मक निर्बंधन' निषिद्ध होते हैं।

2. ये वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं।

3. ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं हैं।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 2**

(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: व्यापार संबंधित निवेश उपायों (TRIMS) से संबंधित अनुच्छेद-2 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि विदेशी निवेशकों द्वारा किये जाने वाले आयात पर 'परिमाणात्मक निर्बंधन' निषिद्ध होते हैं। यह सिर्फ वस्तुओं के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। सेवाओं के व्यापार से संबंधित निवेश पर यह लागू नहीं होता है। ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं हैं। अत: कथन (2) सही नहीं है। **अत: विकल्प (c) सही है।**

2019

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्वों के ऋणी होने के द्वारा है।

2. भारत का सारा विदेशी ऋण US डॉलर के मूल्यवर्ग में है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1, न ही 2**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी नहीं बल्कि गैर-सरकारी सत्वों (Non-governmental entities) के ऋणी होने के द्वारा है। मार्च 2019 में जारी भारत के विदेश ऋण संबंधी नवीनतम आँकड़ों के

अनुसार दिसंबर 2018 के अंत तक भारत का कुल विदेशी ऋण भार 521.2 बिलियन डॉलर था, जिसमें सरकारी ऋण 104.5 बिलियन डॉलर और गैर-सरकारी ऋण 416.7 बिलियन डॉलर था। अत: कथन 1 गलत है।

वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2018 के अंत तक भारत के कुल विदेशी ऋण स्टॉक में अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित ऋण का हिस्सा 45.9 प्रतिशत था, जिसके बाद क्रमश: भारतीय रुपया (24.8 प्रतिशत), एसडीआर (5.1 प्रतिशत), जापानी येन (4.9 प्रतिशत) और यूरो (3.1 प्रतिशत) का स्थान था।

जबकि कथन (2) में दिया गया है कि भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर के मूल्य वर्ग में है। अत: कथन 2 गलत है।

विदेशी ऋण क्या है?

किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र या संगठन से ली गई उधारी जो उसे ब्याज सहित या ब्याज रहित लौटानी होती है, विदेशी ऋण कहलाता है। यह अल्पावधि एवं दीर्घावधि ऋणों का संयोजन होता है। ये ऋण जिस मुद्रा में प्राप्त किये जाते हैं, ब्याज सहित उसी मुद्रा में चुकाये जाते हैं।

2. भारत के संदर्भ में, मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस/किन कारक/कारकों का योगदान है?

1. भारत के IT सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का

2. सरकारी व्यय के बढ़ने का

3. विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 1 और 3**

(c) केवल 2 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: **(b)**

व्याख्या: भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित कारकों का योगदान है-

- भारत के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक (IT Sector) का विदेशी मुद्रा अर्जन।
- विदेशस्थ भारतीयों (Indians abroad) द्वारा भेजा गया धन।

ध्यातव्य है कि IT सेक्टर द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजा गया धन देश में विदेशी मुद्रा अंतर्वाह (Foreign Currency Inflow) को बढ़ाकर विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने के साथ भुगतान संतुलन (Balance of Payment) के घाटे को कम करता है जिससे मुद्रा संकट का जोखिम कम होता है।

- जबकि सरकारी व्यय के बढ़ने से यदि रुपये की आपूर्ति बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में रुपये का मूल्य गिरने से मुद्रा संकट का जोखिम और बढ़ सकता है। अत: दिये गए विकल्पों में विकल्प (b) सही उत्तर है।

3. पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को, जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाज़ार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है?

(a) जमा प्रमाण-पत्र

(b) वाणिज्यिक पत्र

(c) वचन-पत्र (प्रॉमिसरी नोट)

(d) सहभागिता पत्र (पार्टिसिपेटरी नोट)

सही उत्तर: **(d)**

व्याख्या: पार्टिसिपेटरी नोट्स (Participatory Notes) एक वित्तीय उपकरण है जो SEBI में पंजीकृत नहीं किये गए निवेशकों या विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश के लिये जारी किया जाता है। भारतीय प्रतिभूतियों के रूप में इक्विटी प्रतिभूति, ऋण प्रतिभूति या डेरिवेटिव शामिल होते हैं।

पार्टिसिपेटरी नोट्स में निवेश करने वाला निवेशक भारतीय प्रतिभूति का स्वामी नहीं होता है। इसका धारक वह विदेशी निवेशक होता है जो पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी करता है। इस प्रकार पार्टिसिपेटरी नोट्स में निवेश करने वाले निवेश का आर्थिक लाभ इसके धारक हुए बिना ही प्राप्त करते हैं।

2017

1. कभी-कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले 'घरेलू अंश आवश्यकता (डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट)' पद का संबंध किससे है?

(a) हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से

(b) हमारे देश में विदेशी टी.वी चैनलों को अनुज्ञप्ति प्रदान करने से

(c) हमारे देश के खाद्य उत्पादों को अन्य देशों को निर्यात करने से

(d) विदेशी शिक्षा संस्थाओं को हमारे देश में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति देने से

सही उत्तर: **(a)**

व्याख्या: घरेलू अंश आवश्यकता (डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट) का संबंध भारत में सौर शक्ति उत्पादन के विकास से संबंधित है। यह शब्द चर्चा में तब आया जब अमेरिका ने 2013 में WTO में भारत के ख़िलाफ़ यह शिकायत की कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के लिये भारत की सब्सिडी सौर घटक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के ख़िलाफ़ भेदभाव करती है।

2. 'राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति (नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइटस पॉलिसी)' के संदभ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यह दोहा विकास एजेंडा और TRIPS समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है।

2. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिये, केंद्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2 *सही उत्तर:* (c)

व्याख्या: राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति एक विज़न दस्तावेज़ है जिससे समस्त बौद्धिक संपदाओं के बीच सहयोग संभव बनाया जाएगा। इसके तहत इस बात पर बल दिया गया है कि भारत बौद्धिक संपदा कानूनों को मानता है तथा भारत में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिये प्रशासनिक एवं न्यायिक ढाँचा मौजूद है। अत: इसके द्वारा भारत दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स (TRIPS) समझौते के प्रति प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित करता है।

औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक विभाग है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिये केंद्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) है।

3. 'व्यापक-आधारयुक्त व्यापार और निवेश करार (ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड ऐंड इन्वेस्टमेंट ऐग्रीमेंट/ BTIA)' कभी-कभी समाचारों में भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है?

(a) यूरोपीय संघ

(b) खाड़ी सहयोग परिषद्

(c) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन

(d) शंघाई सहयोग संगठन *सही उत्तर:* (a)

व्याख्या: BTIA समझौता व्यापार और निवेश से संबंधित यूरोपीय देशों का एक समझौता है जिसके तहत यूरोपीय संघ के देश व्यापार और निवेश को मज़बूती प्रदान करते हैं।

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारत ने WTO के व्यापार सुकर बनाने के करार (TFA) का अनुसमर्थन किया है।

2. TFA, WTO के बाली मंत्रिस्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है।

3. TFA, जनवरी 2016 में प्रवृत्त हुआ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 1 और 3**

(c) केवल 2 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: विश्व व्यापार संगठन विभिन्न देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठित एक संस्था है जो सदस्य देशों के बीच व्यापार से संबंधित विवादों का समाधान निकालती है। इसी क्रम में WTO की बाली मंत्रिस्तरीय बैठक-2013 में व्यापारिक सुविधा समझौता (TFA) का प्रावधान किया गया। यह समझौता फरवरी 2017 में प्रवृत्त हुआ है। **इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प (a) है।**

2016

1. निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी-कभी समाचारों में 'एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स' शब्द देखने को मिलते हैं?

(a) WTO मामला **(b) SAARC मामला**

(c) UNFCCC मामला **(d) FTA पर भारत-EU वार्ता**

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: विश्व व्यापार संगठन के उरुग्वे दौर (1986–1994) में कृषि सब्सिडी के उत्पादन और व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर उन्हें ग्रीन, ब्लू और अंबर बॉक्स में वर्गीकृत किया जाता है।

ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत वे सब्सिडी आती हैं जो व्यापार को विरूपित (Distort) नहीं करती हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण और अनुसंधान इत्यादि पर दी गई सब्सिडी। यह सब्सिडी व्यापार को विरूपित नहीं करती है, अत: WTO द्वारा इस तरह की सब्सिडी देने पर कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अंबर बॉक्स के अंतर्गत वे सब्सिडी आती हैं जो कि किसी देश के उत्पाद को सस्ता करती हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विरूपित होता है। अत: WTO द्वारा इस तरह की सब्सिडी को कम करने की बात की जाती है। ब्लू बॉक्स के अंतर्गत की सब्सिडी भी उत्पादन को प्रभावित कर व्यापार को विरूपित करती है।

2. कभी-कभी समाचारों में दिखने वाले 'आई.एफ.सी. मसाला बॉण्ड (IFC Masala Bonds)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन), जो इन बॉण्ड्स को प्रस्तावित करता है, विश्व बैंक की एक शाखा है।

2. ये रुपया अंकित मूल्य वाले बॉण्ड (rupee-denominated bonds) हैं और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक के ऋण वित्तीयन के स्रोत हैं।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1 और न ही 2**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: आई.एफ.सी. मसाला बॉण्ड्स को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम प्रस्तावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक की एक शाखा है। रुपया अंकित मूल्य वाले बॉण्ड निजी और सार्वजनिक क्षेत्रक के वित्तीयन के स्रोत हैं।

नवंबर 2016 में आर.बी.आई ने टियर 1 और टियर 2 श्रेणी के बैंको को मसाला बॉण्ड जारी करने की अनुमति प्रदान की गई।

आई.एफ.सी. मसाला बॉण्ड के फायदे और नुकसान-

अपतटीय बॉण्ड, दोनों जारीकर्त्ता और निवेशक के लिये फायदे और नुकसान दोनों रूप में अर्थव्यवस्था की बेहतरी हेतु है। अपतटीय बाज़ारों

से प्रतियोगिता में इस तरह के घरेलू बाज़ार में सुधार देखा जा सकता है, जैसे– घरेलू बाज़ार की संरचना, निवेशक की सुरक्षा और कर दिक्कतों को दूर करना आदि। इन लाभों के रास्ते में कुछ हानियाँ भी हैं, जैसे– आर्थिक खुलेपन के साथ कुछ जोखिम भी विद्यमान रहता है। मसाला बॉण्ड्स का उपयोग सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ कर संरचना एवं रुपये के क्षेत्र में भी किया जा सकता है।

3. निम्नलिखित में से कौन-सा, कभी-कभी समाचारों में दिखने वाले पद 'आयात आवरण (इम्पोर्ट कवर)' का सर्वोत्तम वर्णन करता है?

(a) यह किसी देश के आयात मूल्य एवं सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को बताता है।

(b) यह किसी देश के एक वर्ष में आयात के कुल मूल्य को बताता है।

(c) यह दो देशों के बीच निर्यात एवं आयात के मूल्यों के अनुपात को बताता है।

(d) यह उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीनों के आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिज़र्व द्वारा किया जा सकता है। *सही उत्तर:* (d)

व्याख्या: 'आयात आवरण' (इम्पोर्ट कवर) देशों द्वारा अपने देश को बाह्य संकट से सुरक्षा प्रदान करने के लिये बनाया जाता है। 'आयात आवरण' मूलत: 'विदेशी मुद्रा भंडार' की किसी देश के पास उपलब्धता है।

4. सरकार की 'सम्प्रभु स्वर्ण बॉण्ड योजना (Sovereign Gold Bond Scheme)' एवं 'स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetization Scheme)' का/के उद्देश्य क्या है/हैं?

1. भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना

2. स्वर्ण एवं आभूषण के क्षेत्र में एफ.डी.आई. (FDI) को प्रोत्साहित करना

3. स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 2 और 3**

(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: 'सम्प्रभु स्वर्ण बॉण्ड योजना' केवल भारत में निवास करने वाले नागरिकों के लिये है। इस योजना के उद्देश्यों में भारतीयों के पास पड़े निष्क्रिय सोने को अर्थव्यवस्था में लाना तथा सोने के आयात को हतोत्साहित करना है।

5. समाचारों में कभी-कभी देखा जाने वाला 'यूरोपीय स्थिरता तंत्र (European Stability Mechanism)' क्या है?

(a) मध्य-पूर्व से लाखों शरणार्थियों के आने के प्रभाव से निपटने के लिये EU द्वारा बनाई गई एक एजेंसी

(b) EU की एक एजेंसी, जो यूरोक्षेत्र (यूरोज़ोन) के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है

(c) सभी द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को सुलझाने के लिये EU की एक एजेंसी

(d) सदस्य राष्ट्रों के बीच मतभेद सुलझाने के लिये EU की एक एजेंसी *सही उत्तर:* (b)

व्याख्या: यूरोपीय स्थिरता तंत्र, यूरोपीय यूनियन की एजेंसी है जो कि यूरोज़ोन के देशों को लोन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका मुख्यालय लक्ज़मबर्ग में है। यह एक स्थायी संस्था है जो कि पूर्ववर्ती संस्था यूरोपीय वित्तीय स्थिरता सुविधा (European Financial Stability Facility) की जगह 2010 में स्थापित हुई है।

2015

1. 'एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर (Agreement on Agriculture)', 'एग्रीमेंट ऑन दि ऐप्लिकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures)' और 'पीस क्लॉज़ (Peace Clause)' शब्द प्राय: समाचारों में किसके मामलों के संदर्भ में आते हैं?

(a) खाद्य और कृषि संगठन

(b) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का रूपरेखा सम्मेलन

(c) विश्व व्यापार संगठन

(d) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम *सही उत्तर:* (c)

व्याख्या: 'एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर' विश्व व्यापार संगठन की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। उरुग्वे दौर की वार्ता के दौरान इस पर चर्चा हुई। 'एग्रीमेंट ऑन दि ऐप्लिकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स' 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व में आने के साथ ही आया। यह समझौता खाद्य सुरक्षा और पशु तथा वनस्पति स्वास्थ्य विनियमनों के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करता है। विश्व व्यापार संगठन की कार्यप्रणाली से जुड़ी हुई एक अन्य शब्दावली 'पीस क्लॉज़' है जो विभिन्न देशों में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों व उन पर दी जाने वाली सब्सिडी से संबंधित है। 'पीस क्लॉज़' शब्द विश्व व्यापार संगठन के 9वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (बाली) में अस्तित्व में आया था।

2. रुपये की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है?

(a) रुपये के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना।

(b) रुपये के मूल्य को बाज़ार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना।

(c) रुपये को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपये में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना।

(d) भारत में मुद्राओं के लिये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार विकसित करना। *सही उत्तर:* (c)

व्याख्या: रुपये की परिवर्तनीयता से आशय है- रुपये को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपये में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। अत: विकल्प (c) सही है। भारत में चालू खाते पर रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता तो है लेकिन पूंजी खाते पर अभी पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं है। भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य निम्नवत् हैं:

- भारत सरकार ने फरवरी 1994 में भुगतान शेष के चालू खाते पर रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषणा की थी लेकिन पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता न होने के कारण रुपये की परिवर्तनीयता आंशिक है।
- पूंजी खाता पर परिवर्तनीयता के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा एस.एस. तारापोर की अध्यक्षता में गठित समिति ने जून 1997 में कुछ निश्चित दशाओं की पूर्ति पर क्रमिक ढंग से पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता की संस्तुति की थी।
- 2006 में गठित तारापोर-II समिति ने पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिये राजकोषीय सुदृढ़ीकरण तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार जैसी पूर्व शर्तें रखी थीं।

3. अंतर्राष्ट्रीय नकदी (लिक्विडिटी) की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है?

(a) वस्तुएँ और सेवाएँ

(b) सोना और चांदी

(c) डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएँ (हार्ड करेंसीज़)

(d) निर्यात-योग्य बेशी (सरप्लस)

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: भुगतान घाटे को वित्तपोषित करने के लिये राष्ट्रीय मौद्रिक प्राधिकारी के पास उपलब्ध संसाधनों में अंतर्राष्ट्रीय तरलता का होना आवश्यक रूप से शामिल है। वर्तमान में विदेशी मुद्राओं के संबंध में इसे मुख्य रूप से कार्यरूप दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के सदस्य राष्ट्र भुगतान संतुलन के लिये विदेशी मुद्रा में ऋण ले सकते हैं जिसे उन्हें आवश्यक रूप से ब्याज के साथ भुगतान करना होता है। प्रत्येक सदस्य इस प्रकार से अपने कोटे का 25 प्रतिशत तुरंत ऋण ले सकता है। खरीद के लिये उपलब्ध राशि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में वर्णित है जिसका मूल्य पाँच मुद्राओं अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पौंड स्टर्लिंग तथा चाइनीज रेनमिनबी (RMB) (1 अक्तूबर, 2016 से शामिल) के भारित औसत पर प्रतिदिन आगणित किया जाता है। इसमें सर्वाधिक मान्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर है जिसे अन्य मुद्राओं के साथ हार्ड करेन्सी माना जाता है। इन्हीं की अनुपलब्धता से अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या संबंधित है।

2014

1. भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे/किनसे चालू खाता बनता है?

1. व्यापार संतुलन
2. विदेशी परिसंपत्तियाँ
3. अदृश्यों का संतुलन
4. विशेष आहरण अधिकार

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) 2 और 3**
(c) 1 और 3 **(d) 1, 2 और 4**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: भुगतान संतुलन (BOP) एक निर्धारित समयावधि में एक देश की अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ होने वाले आर्थिक लेनदेनों (Economic transactions) का दस्तावेज़ होता है। भुगतान संतुलन चालू व पूंजी खातों से मिलकर बनता है। भुगतान संतुलन के संदर्भ में चालू खाता निम्न से बनता है:

- व्यापार संतुलन – इसमें किसी देश के आयात एवं निर्यात के मूल्यों का अंतर सम्मिलित किया जाता है।
- अदृश्य (कुल) – इसमें सेवाएँ, अंतरण एवं आय को सम्मिलित किया जाता है।

भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता निम्न से बनता है:

- बाह्य सहायता
- बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)
- अल्पकालिक ऋण
- बैंकिंग पूंजी जिसमें अनिवासी जमा भी शामिल है
- विदेशी निवेश जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश शामिल हैं
- अन्य प्रवाह (other flows)

2013

1. किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है?

(a) किसी निर्धारित समय के दौरान, सामान्यत: एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन-देन।

(b) किसी वर्ष में एक देश द्वारा निर्यात की गई वस्तुएँ।

(c) एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच आर्थिक लेन-देन।

(d) एक देश से दूसरे देश को पूंजी का संचलन।

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: भुगतान संतुलन आँकड़े व्यवस्थित रूप से एक निश्चित समयावधि में एक अर्थव्यवस्था के पूरे विश्व के साथ आर्थिक लेन-देनों को दर्शाते हैं। अत: विकल्प (a) सही है। भारत का रिज़र्व बैंक इन आँकड़ों को संगृहीत और प्रसारित करने के लिये ज़िम्मेदार है। भारत में भुगतान संतुलन में मुख्यत: चालू खाता और पूंजी खाता शामिल होते हैं। चालू खाता में व्यापार संतुलन (आयात एवं निर्यात का अंतर) तथा अदृश्य मदें (सेवाएँ, आय एवं नगर अंतरण) शामिल किये जाते हैं जबकि पूंजी खाता में बाह्य सहायता, बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ (ECBs), विदेशी निवेश (FDI, FPI), अल्पकालिक ऋण, बैंकिंग पूंजी (जिसमें अनिवासी जमाएँ भी शामिल हैं) आदि शामिल किये जाते हैं।

2. निम्नलिखित में से कौन-से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं?

1. विदेशी ऋण
2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
3. निजी प्रेषित धन
4. पोर्टफोलियो निवेश

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) 1, 2 और 3 **(b) 1, 2 और 4**

(c) 2, 3 और 4 **(d) 1, 3 और 4**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: पूंजीगत लेखा (Capital Account) भुगतान संतुलन के अभिलेख का महत्त्वपूर्ण भाग होता है। जो घटक पूंजीगत लेखा अथवा खाता की रचना करते हैं, वे निम्नवत् हैं:

- विदेशी सहायता (External assistance)
- विदेशी वाणिज्यिक उधार (ECB)
- अल्पावधिक विदेशी ऋण
- बैंकिंग पूंजी जिसमें अनिवासी जमाएँ भी शामिल हैं
- विदेशी निवेश जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश दोनों शामिल हैं।
- अन्य प्रवाह।

निजी प्रेषित आय (Private Remittances) चालू खाते की मद है।

3. भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन-सा एक मद समूह सम्मिलित है?

(a) विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.) तथा विदेशों से ऋण

(b) विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.)

(c) विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, विश्व बैंक से ऋण तथा विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर)

(d) विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विश्व बैंक से ऋण

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.) एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की आरक्षित अवस्थिति शामिल हैं। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि को आरबीआई द्वारा रखा और प्रबंधित किया जाता है।

यहाँ यह भी ध्यान रखने योग्य है कि यद्यपि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति प्रमुख मुद्राओं- डॉलर, यूरो, पौंड स्टर्लिंग और जापानी येन में रखी जाती है लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार की गणना एवं अभिव्यक्ति केवल अमेरिकी डॉलर में होती है। कुल विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश और अन्य निवेश के रूप में प्राप्त होती है।

2012

1. निम्नलिखित में से किस/किन परिस्थिति/परिस्थितियों में 'पूंजीगत लाभ' हो सकता है?

1. जब किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि हो

2. जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो

3. जब आप कोई रंगचित्र खरीदें और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 2 और 3**

(c) केवल 2 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: पूंजी से आशय मनुष्य द्वारा निर्मित उन सभी वस्तुओं से है जो उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं; ये उत्पादन क्रिया में समाप्त नहीं होती, जैसे- मशीन, प्लांट, भवन आदि। पूंजीगत लाभ ऐसा लाभ है जो एक व्यक्ति या कंपनी अपनी पूंजीगत परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त करता है। चूँकि इन परिसंपत्तियों से लाभ प्राप्त होता है, अत: इन पर सरकार को कर देना होता है जिसे पूंजीगत लाभ कर कहते हैं। पूंजीगत परिसंपत्तियाँ जिनसे पूंजीगत लाभ होता है, वे हैं:

- भूमि (कृषि भूमि को छोड़कर)।
- भवन, फैक्ट्री, प्लांट और मशीनरी (कच्चे पदार्थों अथवा अंतिम उत्पादों को छोड़कर)।
- शेयर, डिबेन्चर, म्यूचुअल फंड आदि।
- आभूषण, पेन्टिंग, मूर्ति और अन्य पुरातात्त्विक संग्रहण आदि।

उल्लेखनीय है कि पूंजीगत लाभ कर, एक प्रत्यक्ष कर है क्योंकि यह व्यक्ति की आय और संपदा पर लगाया जाता है।

2. निम्नलिखित में से कौन-सी बातें भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगी?

1. भारत में विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियाँ

2. भारतीय कम्पनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण

3. विदेशी कम्पनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्तपोषित कंपनियाँ

4. पोर्टफोलियो निवेश

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये-

(a) 1, 2, 3 और 4

(b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1 और 3

(d) केवल 1, 2 और 3

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में निम्नांकित समाविष्ट हैं:

- एक अनिवासी इकाई भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर सकती है। बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के नागरिक व इकाई केवल सरकारी मार्ग से ही निवेश कर सकते हैं।
- अनिवासी भारतीय, नेपाल व भूटान में निवासित और नेपाल तथा भूटान के नागरिक एफडीआई स्कीम के तहत भारतीय कंपनियों के शेयरों व परिवर्तनीय डिबेन्चर्स में निवेश कर सकते हैं।

- ओवरसीज़ कॉर्पोरेट निकाय 2003 से भारत में FDI रास्ते से निवेश नहीं कर सकते हैं।
- भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियाँ।
- भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारक।
- विदेशी कम्पनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्तपोषित कंपनियाँ।
- लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 के तहत गठित व पंजीकृत लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) सरकारी अनुमति मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकार करने के योग्य बनाए गए हैं।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) में भी कुछ निश्चित-शर्तों के अधीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मूल्य

1. विश्व बैंक निर्धारित करता है
2. संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं/सेवाओं की कितनी मांग है, से निर्धारित होता है
3. संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है।
4. संबंधित देश की आर्थिक सम्भाव्यता से निर्धारित होता है

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) 1, 2, 3 और 4 **(b) केवल 2 और 3**
(c) केवल 3 और 4 **(d) केवल 1 और 4**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: किसी एक मुद्रा की ताकत इस बात से मापी जाती है कि उस मुद्रा का अन्य मुद्राओं के सापेक्ष कितना मूल्य है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मुद्रा की कीमत उसी तरह निर्धारित होती है जिस प्रकार बाज़ार में किसी अन्य वस्तु की। इसका आशय है कि मांग और आपूर्ति कारक ही मुद्रा का मूल्य निर्धारित करते हैं। डॉलर की मांग अधिक होने के कारण ही उसका मूल्य ऊँचा है। इसकी मांग के कारण ही इसका मूल्य निर्धारित होता है। विश्व बैंक की इस कार्य में भूमिका नहीं होती है।

उल्लेखनीय है कि किसी देश की मुद्रा की मांग दो बातों पर निर्भर करती है-

(क) देश का निर्यात जिसे अन्य देश खरीदने की इच्छा रखते हैं।
(ख) उस मुद्रा अथवा परिसंपत्ति जिसमें उस मुद्रा को डिनॉमिनेट किया गया है, में लोगों के निवेश की इच्छा। निर्यात में वृद्धि मुद्रा की मांग में वृद्धि करती है और मुद्रा मज़बूत होती है।

2011

1. आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में XIX राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिये विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन

(a) निर्यात था **(b) आयात था**
(c) उत्पादन था **(d) उपभोग था**

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में XIX राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिये विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन निर्यात था। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि भुगतान संतुलन की धारणा के अंतर्गत चालू खाता और पूंजी खाते की बात की जाती है। चालू खाते के अंतर्गत एक मद अदृश्य निर्यात की होती है। विदेशियों द्वारा भारत में किया गया पर्यटन व उसकी प्राप्तियाँ इन्हीं अदृश्य सेवाओं के रूप में निर्यात का भाग होती हैं।

2. निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें जो सरकार द्वारा लिये जा सकते है-

1. घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन
2. निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती
3. उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक FDI आए तथा FIIs से अधिक निधि आए

उपर्युक्त में से कौन-सी क्रिया/क्रियाएँ चालू खाते के घाटे को घटाने में सहायक साबित हो सकती है/हैं?

(a) 1 और 2 **(b) 2 और 3**
(c) केवल 3 **(d) 1 और 3**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: भुगतान संतुलन की धारणा के तहत चालू खाते के घटकों में शामिल हैं: निर्यात-आयात, व्यापार संतुलन, अदृश्य (सकल) मद, जैसे- सेवाएँ, हस्तांतरण और आय। चालू खाता घाटा एक ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का मूल्य आयातित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य से कम होता है। सरल शब्दों में कहें तो आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी।

3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) तथा संस्थागत विदेशी निवेशक (FII) दोनों ही, किसी देश में निवेश से संबद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन दोनों के बीच की एक महत्त्वपूर्ण भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है?

(a) FII बेहतर प्रबंधन कुशलताएँ तथा प्रौद्योगिकी अंतरण को लाने में सहायक है, जबकि FDI केवल पूंजी लेकर आता है
(b) FII व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, जबकि FDI का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है
(c) FDI केवल द्वितीयक बाज़ार में चलित होता है, जबकि FII का लक्ष्य प्राथमिक बाज़ार होता है
(d) FDI की तुलना में FII अधिक स्थायी माना जाता है

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आशय विदेशी कम्पनियों द्वारा एक देश की कंपनी में भौतिक पूंजी सम्पत्तियों, प्लान्ट, मशीनरी, भूमि, भवन, इन्वेन्ट्री आदि में निवेश करने से है।

- पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत निवेशक द्वारा शुद्ध रूप से वित्तीय संपत्तियों, जैसे- शेयर, ऋणपत्र, बॉण्ड आदि का क्रय किया जाता है तथा इस प्रकार के क्रय की व्यवस्था बैंक, विनियोग फंड या डिपॉज़िटरी के माध्यम से होती है।
- विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) को भारत के संदर्भ में बाहरी कंपनियों तथा संस्थाओं के रूप में लिया जाता है जो भारत के वित्तीय बाज़ार में वर्तमान में प्राइमरी तथा सेकेण्डरी बाज़ार में निवेश करते हैं। इन वित्तीय बाज़ारों में हेज फंड, बीमा कंपनी, पेंशन फंड तथा म्यूचुअल फंड शामिल हैं। पहले ये केवल द्वितीयक बाज़ार में निवेश करने के लिये स्वीकृत थे।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों को वित्तीय बाज़ार में भाग लेने के लिये सेबी से पंजीकृत होना आवश्यक है।
- FII व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, जबकि FDI का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है।
- FDI को FII की तुलना में अधिक लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह उत्पादन में वृद्धि करता है, बेहतर वस्तुओं व सेवाओं को लाता है, रोज़गार अवसरों का सृजन करता है और करों के ज़रिये सरकार के लिये राजस्व के अवसरों का भी सृजन करता है।
- FII केवल स्टॉक एक्सचेंजों को विस्तृत करता है और उन्हें मज़बूती देता है।
- FII के स्टॉक मार्केट में तेज़ी से निवेश करने और तेज़ी से निवेश वापस खींचने की स्वतंत्रता के चलते यह FDI की तुलना में अधिक जोखिम भरा होता है।

अवसंरचना

2025

1. 'पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

I. इसका लक्ष्य आवासीय सेक्टर में एक करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना है।

II. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य छतों पर सौर पैनल लगाने, उनके प्रचालन, अनुरक्षण और मरम्मत करने के विषय में आधार-स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना है।

III. इसका लक्ष्य, क्षमता निर्माण के स्कीम घटक के अंतर्गत, नए कौशल सिखाकर और कौशल का उन्नयन कर तीन लाख से अधिक कुशल जनशक्ति सृजित करना है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-कौन से सही हैं?

(a) केवल I और II **(b) केवल I और III**

(c) केवल II और III **(d) I, II और III**

सही उत्तर: **(d)**

व्याख्या:

पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत के ऊर्जा सुरक्षा और हरित भविष्य के दृष्टिकोण से एक महत्त्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है। इसका उद्देश्य मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करना है। **अतः कथन I सही है।**

- योजना के दिशा-निर्देशों एवं आधिकारिक दस्तावेज़ों के अनुसार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) सोलर रूफटॉप सिस्टम की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण और मरम्मत के लिये स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। **अतः कथन II भी सही है।**
- इस योजना के तहत 3 लाख से अधिक प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कम-से-कम 1 लाख व्यक्तियों को सोलर पीवी टेक्नीशियन के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह न केवल हरित ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि युवाओं के लिये विनिर्माण, स्थापना और सेवा क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर भी सृजित करेगा। **अतः कथन III भी सही है।**

अतः विकल्प (d) सही है।

2024

1. निम्नलिखित पर विचार कीजिये:

1. बैटरी भंडारण

2. बायोमास जेनरेटर

3. ईंधन सेल

4. रूफटॉप सौर प्रकाश-वोल्टीय यूनिट

उपर्युक्त में से कितने "वितरित ऊर्जा संसाधन" माने जाते हैं?

(a) केवल एक **(b) केवल दो**

(c) केवल तीन **(d) सभी चार**

सही उत्तर: **(d)**

व्याख्या: वितरित ऊर्जा संसाधन (DER) सामान्यतः छोटे पैमाने की बिजली उत्पादन या भंडारण इकाइयाँ होती है, जो उपभोक्ता के पास या स्थानीय स्तर पर ग्रिड से जुड़ी होती हैं।

- वितरित ऊर्जा संसाधनों के **उदाहरणों में** निम्नलिखित शामिल हैं:
- **बैटरी भंडारण**
- **बायोमास जनरेटर**, जो अपशिष्ट गैस या औद्योगिक और कृषि उप-उत्पादों से ईंधन प्राप्त करते हैं।
- **ईंधन सेल**
- **रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक इकाइयाँ।**
- DER के अन्य उदाहरणों में **पवन उत्पादन इकाइयाँ, खुले और बंद चक्र वाले गैस टर्बाइन, हाइड्रो एवं मिनी-हाइड्रो स्कीम आदि शामिल** हैं। **अतः विकल्प (d) सही है।**

2. निम्नलिखित विमानपत्तनों पर विचार कीजिये:

1. डोनी पोलो विमानपत्तन

2. कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

3. विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

हाल ही में, उपर्युक्त में से किनका निर्माण नवीन (ग्रीनफील्ड) परियोजनाओं के रूप में किया गया है?

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 2 और 3**

(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: ग्रीनफील्ड परियोजना का अर्थ है कि अवसंरचना निर्माण बिल्कुल शून्य से यानी खाली ज़मीन पर किया गया है जहाँ पहले कोई बुनियादी ढाँचा मौजूद नहीं था।

- **डोनी पोलो विमानपत्तन एक ग्रीनफील्ड विमानपत्तन** है जो राजधानी ईटानगर में स्थित है। यह **सूर्य (डोनी)** और **चंद्रमा (पोलो)** के प्रति लोगों की श्रद्धा को दर्शाता है तथा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।
- **उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले** में कुशीनगर विमानपत्तन एक ग्रीनफील्ड विमानपत्तन है।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा हवाई अड्डे का विकास/विस्तार किया है। यह ब्राउनफिल्ड परियोजना का हिस्सा है। **अतः विकल्प (a) सही है।**

2023

1. निम्नलिखित आधारिक संरचना क्षेत्रकों पर विचार कीजिये:

1. किफायती आवास

2. सर्वसाधारण द्रुत परिवहन (मास रैपिड ट्रांसपोर्ट)

3. स्वास्थ्य देखभाल

4. पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा

उपर्युक्त में से कितनों पर यू.एन.ओ.पी.एस. आधारिक संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल [सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन (S3i)] अपने निवेशों के लिये ध्यान केंद्रित करता है।

(a) केवल एक **(b) केवल दो**

(c) केवल तीन **(d) सभी चार**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन (S3i) संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख है जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के निवेश को उन बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की ओर मोड़ना है जो सीधे सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में मदद करती है। S3i का लक्ष्य रणनीतिक और संस्थागत निवेशकों के साथ सहयोग करते हुए विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में निवेश करना है, जो किफायती आवास, नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्वास्थ्य के अपने अनिवार्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। **अतः विकल्प (c) सही है।**

2021

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

कथन-I : आधारिक संरचना निवेश न्यासों (InvITs) में जमा (डिपॉजिट) से हुई ब्याज की आय, जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त है, किंतु लाभांश करयोग्य है।

कथन-II : 'वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002' के अधीन InvITs को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।

(b) कथन-1 और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(c) कथन-I सही है किंतु कथन-II गलत है

(d) कथन-I गलत है किंतु कथन-II सही है

सही उत्तर: (d)

व्याख्या:

- ब्याज आय जो InvIT अपने अंतर्निहित SPVs से प्राप्त करती है तथा यूनिटधारकों को हस्तांतरित करती है, उस पर कर लगाया जाता है। InvIT जो लाभांश प्रदान करता है उस पर भी टैक्स लगता है। ब्याज और लाभांश दोनों पर आयकर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाता है। यह वहाँ लागू होता है जहाँ InvIT ने अधिनियम की धारा 115BAA के तहत कराधान का विकल्प चुना है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- InvITs को सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम 2002 के तहत उधारकर्त्ताओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। सरफेसी अधिनियम और ऋण वसूली अधिनियम में संशोधन किया गया है। अब, इन कानूनों के तहत एक पूल निवेश वाहन को उधारकर्त्ता माना जा सकता है। इसका मतलब है कि InvIT या REIT द्वारा जारी सूचीबद्ध सुरक्षित ऋण प्रतिभूतियों हेतु एक डिबेंचर ट्रस्टी SARFAESI अधिनियम के तहत सुरक्षा और प्रवर्तन तंत्र का उपयोग कर सकता है। **अतः कथन 2 सही है।**

2017

1. 'राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. यह नीति (NITI) आयोग का एक अंग है।

2. वर्तमान में इसकी कॉर्पस ₹ 4,00,000 करोड़ है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1, न ही 2**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: सभी के लिये विकास के सपने को साकार करने के लिये भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के प्रमुख चालकों में से एक के रूप में बुनियादी ढाँचे में निवेश किया है। चूँकि बुनियादी ढाँचे के निवेश में दीर्घकालिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है अत: सरकार ने 'राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि' की स्थापना का प्रस्ताव एक अर्द्ध-सार्वभौमिक संपदा निधि के रूप में 2015 के बजट में किया था। यह नीति आयोग से संबंधित नहीं है। अत: कथन 1 गलत है। वर्तमान में इसकी कॉर्पस ₹ 40,000 करोड़ है, अत: कथन 2 भी गलत है।

2. सार्वभौम अवसंरचना सुविधा (ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी)

(a) एशिया में अवसंरचना के उन्नयन के लिये ASEAN का उपक्रमण है, जो एशियाई विकास बैंक द्वारा दिये गए साख (क्रेडिट) से वित्तपोषित है।

(b) गैर-सरकारी क्षेत्रक और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिये विश्व बैंक का सहयोग है, जो जटिल अवसंरचना सरकारी-गैर-सरकारी भागीदारियों (PPPs) की तैयारी और संरचना-निर्माण को सुकर बनाता है।

(c) OECD के साथ कार्य करने वाले विश्व के प्रमुख बैंकों का सहयोग है, जो उन अवसंरचना परियोजनाओं को विस्तारित करने पर केंद्रित है जिनमें गैर-सरकारी विनिवेश संग्रहीत करने की क्षमता है।

(d) UNCTAD द्वारा वित्तपोषित उपक्रमण है जो विश्व में अवसंरचना के विकास को वित्तपोषित करने और सुकर बनाने का प्रयास करता है।

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: सार्वभौमिक अवसंरचना सुविधा (ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी) सरकारों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्र के निवेशकों और फाइनेंसरों के बीच एक साझेदारी है। यह जटिल परियोजनाओं को तैयार करने, संरचित करने और कार्यान्वित करने में सहयोग करने का एक नया तरीका प्रदान करने के लिये डिज़ाइन की गई है।

इसे विश्व बैंक द्वारा उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों की बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये आरंभ किया गया है।

2016

1. निम्नलिखित में से कौन-सा, सरकार की योजना 'UDAY' का एक प्रयोजन है?

(a) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में नव-प्रयासी (स्टार्ट-अप) उद्यमियों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना

(b) 2018 तक देश में हर घर में बिजली उपलब्ध कराना

(c) एक समयावधि के अंदर कोयला आधारित शक्ति संयंत्रों के स्थान पर प्राकृतिक गैस, नाभिकीय, सौर, वायु एवं ज्वारीय शक्ति संयंत्र स्थापित करना

(d) विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय कायापलट और पुनरुत्थान का प्रबंध करना

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: 5 नवंबर, 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (Ujjwal DISCOM Assurance Yojana) या उदय (UDAY) को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का लक्ष्य विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय कायापलट और उनके पुनरुत्थान का प्रबंध करना है। इस योजना द्वारा सभी लोगों को 24 घंटे किफायती एवं सुविधाजनक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। **अत: कथन (d) सत्य है।**

उदय (Uday) की प्रमुख विशेषताएँ–

- केंद्र सरकार द्वारा वितरण कम्पनियों को ऋण के दबाव से मुक्त करने के लिये उदय योजना चलाई गई है।
- उदय योजना में शामिल होने वाला प्रथम राज्य झारखंड है।
- उदय योजना की वर्तमान स्थिति–
  - अभी तक इस योजना से 15 राज्य जुड़ चुके हैं।
  - अगर ये सभी 15 राज्य योजना लागू कर देते हैं तो बिजली कम्पनियों पर बकाया ₹4.50 लाख करोड़ के कर्ज़ के भुगतान का रास्ता साफ हो जाएगा।
  - राज्य सरकारें अब ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत पहुँचाने का कार्य तेज़ी से लागू कर सकेंगी। वर्ष 2019–20 तक उन सभी गाँवों को बिजली से जोड़ दिया जाएगा जहाँ अभी-तक बिजली नहीं पहुँची है।
- उदय योजना के अंतर्गत:
  - राज्य की सरकारी कम्पनियों के सभी बकाए का भुगतान राज्य सरकार करेगी।
  - कर्ज़ देने वाले बैंक व वित्तीय संस्थान बकाए कर्ज़ पर अब नया ब्याज नहीं लगाएंगे।
  - वितरण कम्पनी की बकाया राशि के बराबर बॉण्ड जारी होंगे।
  - कोयला मंत्रालय, राज्य के बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयला देंगे।
  - अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन लाइन का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा।

2015

1. भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कम्पनी है।

2. यह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1 और न ही 2**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है, जो नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिये ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करती है। इस एजेंसी से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य निम्नवत् हैं-

- भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2015 में मिनी रत्न (श्रेणी 1) का दर्जा प्रदान किया गया है।
- इरेडा एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेन्ट कंपनी भी है जिसे 1987 में एनबीएफसी के रूप में गठित किया गया था। इसका आदर्श वाक्य है: 'शाश्वत ऊर्जा' (Energy Forever)।

मानव संसाधन विकास

2024

1. किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप से परिभाषित किया जाता है?

(a) एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या

(b) किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपति के जीवन-काल में उनसे जन्मे बच्चों की संख्या

(c) जन्म दर घटा मृत्यु दर

(d) एक महिला की गर्भधारण आयु (चाइल्ड-बेअरिंग एज) के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: कुल प्रजनन दर (TFR): सामान्य शब्दों में कुल प्रजनन दर (TFR) का तात्पर्य उन बच्चों की कुल संख्या से है जो किसी महिला के अपने जीवनकाल में पैदा होते हैं या होने की संभावना होती है। दूसरे शब्दों में प्रति महिला (उसके प्रजनन काल में) पर कुल बच्चों की औसत संख्या TFR कहलाती है। सरकारें सामान्यत: स्वास्थ्य और शिक्षा बजट तय करने के लिये TFR का उपयोग करती हैं।

अत: विकल्प (d) सही है।

2. 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसवपूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिये न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर छह महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करती है।

2. इस योजना के अंतर्गत, कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) का शुभारंभ प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं **(दूसरी और तीसरी तिमाही में)** को निश्चित दिन पर सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करने के लिये किया गया था।

- इस अभियान के एक भाग के रूप में, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं (PHC/CHC, DH/शहरी स्वास्थ्य सुविधाएँ आदि) में गर्भवती महिलाओं को उनकी **दूसरी/तीसरी तिमाही में प्रसवपूर्व देखभाल सेवाओं** का एक न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाता है।
- लेकिन यह योजना किसी भी सरकारी सुविधा में प्रसव के छह माह बाद स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान नहीं करती है। **अत: कथन 1 सही नहीं है।**
- निजी/स्वैच्छिक क्षेत्र के डॉक्टरों की सहभागिता को सुविधाजनक बनाने हेतु PMSMA के लिये एक राष्ट्रीय पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है।
- निजी क्षेत्र के OBGY विशेषज्ञों/रेडियोलॉजिस्ट/चिकित्सकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर स्वैच्छिक सेवाएँ प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा जहाँ सरकारी क्षेत्र के चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं या अपर्याप्त हैं। **अत: कथन 2 सही है। अत: विकल्प (b) सही है।**

2023

1. निम्नलिखित पर विचार कीजिये:

1. जनांकिकीय निष्पादन

2. वन और पारिस्थितिकी

3. शासन सुधार

4. स्थिर सरकार

5. कर एवं राजकोषीय प्रयास

समस्तर कर-अवक्रमण के लिये पंद्रहवें वित्त आयोग ने उपर्युक्त में से कितने को जनसंख्या क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया?

(a) केवल दो **(b) केवल तीन**

(c) केवल चार **(d) सभी पाँच**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: समस्तर कर-अवक्रमण हेतु पंद्रहवें वित्त आयोग ने मानदंड (निकष) के रूप में निम्नलिखित का उपयोग किया:

- जनसंख्या
- आय अंतराल
- क्षेत्रफल
- कर एवं राजकोषीय प्रयास
- वन और पारिस्थितिकी
- जनांकिकीय निष्पादन

Criteria	Weight (%)
Population	15.0
Area	15.0
Forest & Ecology	10.0
Income distance	45.0
Tax & fiscal efforts	2.5
Demographic performance	12.5
Total	**100**

अतः विकल्प (b) सही है।

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

कथन-I: भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित निरोधक, वर्धक और पुनःस्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित करती है।

कथन-II : भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत, राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिये उत्तरदायी हैं।

उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(c) कथन-I सही है किंतु कथन-II गलत है।

(d) कथन-I गलत है किंतु कथन-II सही है।

सही उत्तर: (b)

व्याख्या:

- भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित निरोधक, वर्धक और पुनःस्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। **अतः कथन I सही है।**
- आयुष्मान भारत में उप स्वास्थ्य केंद्र (SHC) स्तर पर स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को बहुउद्देशीय कार्यकर्त्ता (पुरुष एवं महिला) एवं आशा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र / शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, **लेकिन तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में केंद्र सरकार भी एक प्रमुख हितधारक है। अतः कथन II सही है।**
- **किंतु कथन II, कथन I की व्याख्या नहीं करता है।**

2019

1. अटल नवप्रवर्तन (इनोवेशन) मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है?

(a) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

(b) श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

(c) नीति (NITI) आयोग

(d) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: अटल नवप्रवर्तन (इनोवेशन) मिशन, नीति आयोग (NITI Aayog) की एक प्रमुख पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह देश की नवाचार और उद्यमशीलता से संबंधित भावी ज़रूरतों पर विस्तृत अध्ययन व विचार-विमर्श पर आधारित है।

2018

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है, जिसके द्वारा

1. किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं।

2. देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है।

3. गोचर धन का संचय हो पाता है।

4. अगोचर धन का संचय हो पाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2 **(b) केवल 2**

(c) 2 और 4 **(d) 1, 3 और 4**

सही उत्तर: **(c)**

व्याख्या: देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर व क्षमता में वृद्धि बेरोज़गारी की दर को कम करने में प्रभावी होती है, जो प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है, इससे निवेश बढ़ता है और बेहतर उत्पादन पूंजी निर्माण में सहायक होता है।

वहीं, अगोचर धन हमारे स्वयं व समाज के अदृश्य मूल्यवान गुणों (एकता, ईमानदारी, ज्ञान आदि) के विकास से संबंधित है जो हमारी संपत्ति व ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि के लिये आवश्यक है।

अत: कथन 2 एवं 4 सही हैं।

2017

1. स्मार्ट इण्डिया हैकथॉन 2017 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह हमारे देश के प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिये केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है।

2. यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिये नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तनों के अभिज्ञान की एक पहल है।

3. यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन-देनों को पूरी तरह से डिजिटल करना है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 और 3 **(b) केवल 2**

(c) केवल 3 **(d) केवल 2 और 3**

सही उत्तर: **(b)**

व्याख्या: 'स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017' एक नॉनस्टॉप डिजिटल प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता है जिसका आयोजन लगातार 36 घंटों तक हुआ। इसमें एक साथ भारत के 33 स्थानों से विभिन्न टीमों ने भागीदारी की, जिसमें देश की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के लिये डिजिटल और टिकाऊ नवाचारी समाधान उपलब्ध कराए गए।

2. निम्नलिखित में से कौन-से 'राष्ट्रीय पोषण मिशन (नेशनल न्यूट्रिशन मिशन)' के उद्देश्य हैं?

1. गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना।

2. छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना।

3. बाजरा, मोटा अनाज तथा अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना।

4. मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये–

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 1, 2 और 3**

(c) केवल 1, 2 और 4 **(d) केवल 3 और 4**

सही उत्तर: **(a)**

व्याख्या: 'राष्ट्रीय पोषण मिशन' गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने एवं छोटे बच्चों, किशोरियों व महिलाओं में रक्ताल्पता को कम करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था।

3. 'राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. NSQF के अधीन, शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाणपत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है।

2. NSQF के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1, न ही 2**

सही उत्तर: **(b)**

व्याख्या:

- राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) दिसंबर 2013 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था।
- NSQF के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता प्रमाण-पत्र औपचारिक अनौपचारिक या गैर-औपचारिक सभी शिक्षा माध्यमों से प्राप्त कर सकता है। अत: कथन 1 असत्य है।
- NSQF के अपेक्षित परिणामों में हैं–
  - व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण
  - कौशल प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय मानकों के रूप में
  - NSQF के अंतर्राष्ट्रीय तुल्यता के माध्यम से भारत से कुशल कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता आदि।

उल्लेखनीय है कि इस फ्रेमवर्क का संचालन राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (National Skill Development Agency–NSDA) द्वारा किया जाता है जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।

4. 'विद्यांजलि योजना' का क्या प्रयोजन है?

1. प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थाओं को भारत में अपने कैंपस खोलने में सहायता करना।

2. निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना।

3. प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की आधारिक संरचना सुविधाओं के संवर्धन के लिये निजी व्यक्तियों और संगठनों से ऐच्छिक वित्तीय योगदान को प्रोत्साहित करना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 2 **(b) केवल 3**

(c) केवल 1 और 2 **(d) केवल 2 और 3**

सही उत्तरः (a)

व्याख्याः मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 'विद्यांजलि योजना' की शुरुआत की। इसका उद्देश्य युवाओं को किसी भी नज़दीकी सरकारी स्कूल (कक्षा 1 से 8) में अपनी सेवाएँ देने को प्रोत्साहित करना है। अतः केवल कथन 2 सही है।

5. 'उन्नत भारत अभियान' कार्यक्रम का ध्येय क्या है?

(a) स्वैच्छिक संगठनों ओर सरकारी शिक्षा तंत्र तथा स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग का प्रोन्नयन कर 100 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करना।

(b) उच्च शिक्षा संस्थाओं को स्थानीय समुदायों से जोड़ना जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके।

(c) भारत को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक शक्ति बनाने के लिये भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं को सशक्त करना।

(d) ग्रामीण और नगरीय निर्धन व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिये विशेष निधियों का विनिधान कर मानव पूंजी विकसित करना और उनके लिये कौशल विकास कार्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करना। **सही उत्तरः (b)**

व्याख्याः उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का प्रमुख ध्येय उच्च शिक्षण संस्थाओं को स्थानीय समुदायों से जोड़ना है जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालयों के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के प्रति सहमति व्यक्त की। **अतः विकल्प (b) सही है।**

6. 'नेशनल करियर सर्विस' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. नेशनल करियर सर्विस, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, का एक उपक्रमण है।

2. नेशनल करियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर के संवर्धन के लिये मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1, न ही 2**

सही उत्तरः (d)

व्याख्याः

- 'नेशनल करियर सर्विस' (NCS) परियोजना एक मिशन मोड परियोजना के रूप में भारत के श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है।
- यह पोर्टल मुख्य रूप से युवाओं की आकांक्षाओं के साथ अवसरों को जोड़ने के लिये विकसित किया गया है। साथ ही, यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों, नौकरी प्रदाताओं, कौशल प्रदाताओं, कॅरियर सलाहकारों आदि के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है।

इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं। **अतः विकल्प (d) सही है।**

2016

1. निम्नलिखित में से कौन-सा/से वह/वे सूचक है/हैं, जिसका/जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया गया है?

1. अल्प-पोषण

2. शिशु वृद्धिरोधन

3. शिशु मृत्यु-दर

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 2 और 3**

(c) 1, 2 और 3 **(d) केवल 1 और 3**

सही उत्तरः (c)

व्याख्याः वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएचआई) रिपोर्ट को विश्व स्तर पर भुखमरी को मापने एवं ट्रेक करने के लिये तैयार किया जाता है। जीएचआई की रिपोर्ट वैश्विक स्तर के साथ-साथ देशों और क्षेत्रीय हिस्सों को भी दायरे में लेती है। इस सूचकांक की गणना प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) द्वारा की जाती है। जीएचआई के माध्यम से भुखमरी खत्म करने एवं पोषण का स्तर बढ़ाने का सन्देश विश्व स्तर पर दिया जाता है। 2016 की ग्लोबल हंगर इण्डेक्स में 118 देशों में भारत का 97वाँ स्थान है।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएचआई) रिपोर्ट तैयार करने में निम्नलिखित चार सूचकों का उपयोग किया जाता है-

(a) अल्प-पोषण (b) शिशु-वृद्धिरोधन

(c) शिशु-मृत्यु दर (d) लंबाई के अनुपात में कम वज़न

2. भारत सरकार की एक पहल 'SWAYAM' का लक्ष्य क्या है?

(a) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना

(b) युवा नव-प्रयासी (स्टार्ट-अप) उद्यमियों को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना

(c) किशोरियों की शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य का संवर्धन करना

(d) नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना *सही उत्तर:* (d)

व्याख्या: 'स्वयं' या 'स्टर्डी वेब ऑफ एक्टीव-लर्निंग फॉर यंग अस्पाइरिंग माइंडस' योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत केंद्रीय वित्त पोषित संस्थाओं जैसे- आई.आई.टी., आई.आई.एम. एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपने विषय से संबंधित ऑनलाइन व्याख्यान देते हैं।

इसके अंतर्गत कई सौ पाठ्यक्रम शामिल किये गए हैं। जैसे- वे सभी प्रकार के पाठ्यक्रम जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ाये जाते है। अत: सीखने वाला व्यक्ति (लर्नर) किसी भी पाठ्यक्रम का ज्ञान या किसी भी प्रकार की शिक्षा इसके माध्यम से ग्रहण कर सकता है। यह जीवनभर सीखने का अवसर प्रदान कर आत्म-वास्तविकीकरण (Self-Actualisation) हेतु एक उपकरण साबित होगा।

यहाँ सभी प्रकार के पाठ्यक्रम निःशुल्क प्रदान किये जाएंगे परंतु सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले लर्नर को शुल्क अदा करना पड़ेगा।

इसके प्रथम चरण में आई.आई.टी.-मुंबई, आई.आई.टी.-मद्रास, आई.आई.टी.-कानपुर, आई.आई.टी.-गुवाहाटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, जे.एन.यू., आई.आई.एम.-बंगलूरू इत्यादि अपने माध्यम से तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की सहायता से प्रौद्योगिकी क्षेत्र, सामाजिक विज्ञान, ऊर्जा, मैनेजमेंट, दैनिक विज्ञान इत्यादि में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आगामी 2-3 वर्षों में इस योजना के तहत कम-से-कम 1 करोड़ लोगों के लाभान्वित होने का अनुमान है।

2013

1. जनांकिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिये भारत को क्या करना चाहिये?

(a) कुशलता विकास का प्रोत्साहन

(b) और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रारंभ

(c) शिशु मृत्यु दर में कमी

(d) उच्च शिक्षा का निजीकरण *सही उत्तर:* (a)

व्याख्या: जनांकिकीय लाभांश से आशय भारत जैसे देश में 15-64 वर्ष आयु वर्ग की कार्यशील जनसंख्या की अधिकता से है, किंतु यह जनांकिकीय लाभांश सही अर्थों में तभी सार्थक हो पाएगा जब इस विशाल जनसंख्या समूह को रोज़गार प्राप्त हो। अधिकांश कार्यशील जनसंख्या आज भी कृषि पर आश्रित है। इसे कृषि से उद्योग व सेवा क्षेत्र की तरफ मोड़ने के लिये आवश्यक है कि इन्हें संबंधित कौशल से युक्त किया जाए। चीन जैसा देश इसका अच्छा उदाहरण है।

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कार्यशील जनसंख्या वर्तमान में कुल जनसंख्या का 63.4 प्रतिशत है जबकि वर्ष 2001 की जनगणना में यह 60 प्रतिशत थी।

2012

1. 'जननी सुरक्षा योजना' कार्यक्रम का प्रयास है-

1. संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना

2. प्रसूति की लागत वहन करने हेतु माँ को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना

3. गर्भावस्था और प्रसूति से हुई वेतन-हानि की आपूर्ति करना

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 2**

(c) केवल 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: 'जननी सुरक्षा योजना' राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व के लिये किया गया प्रयास है। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना में बदलाव करते हुए 12 अप्रैल, 2005 को जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। यह शत-प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके प्रयास निम्नांकित उद्देश्यों से प्रेरित हैं-

- निर्धन गर्भवती महिलाओं के मध्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृत्व और नवजात शिशु मृत्यु में कमी लाना।
- संस्थागत प्रसव के लिये नकद सहायता (प्रसव पश्चात् देख-रेख के लिये भी)।
- सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता 'आशा' को इस योजना से जोड़ना।
- संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती स्त्री को ₹1400 और आशा को ₹600 तथा शहरी क्षेत्रों में गर्भवती महिला को ₹1000 व आशा को ₹200 की नकद सहायता देना।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता 'आशा' (ASHA) के कार्य निम्नलिखित में से कौन-से हैं?

1. स्त्रियों को प्रसव-पूर्व देखभाल जाँच के लिये स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना

2. गर्भावस्था के प्रारम्भिक संसूचन के लिये गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना

3. पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना

4. बच्चे का प्रसव कराना

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1, 2 और 3 **(b) केवल 2 और 4**

(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2, 3 और 4**

सही उत्तर: (a)

व्याख्याः बच्चे का प्रसव कराना 'आशा' के कार्यों में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005) के तहत प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता 'आशा' अथवा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ASHA) के कार्यों में शामिल हैं:

- स्वास्थ्य के निर्धारकों, जैसे- पोषण, बुनियादी स्वच्छता (Sanitation), साफ-सफाई (Hygiene), स्वस्थ जीवन व कार्यदशाएँ।
- प्रसव की तैयारी (Birth Preparedness) पर महिलाओं को परामर्श (Counselling) देना, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान, अनुपूरक आहार, टीकाकरण, गर्भनिरोध और महिलाओं को सामान्य संक्रमणों, जैसे- प्रजनन मार्ग संक्रमण/यौन संचरित संक्रमण (RTIs/STIs) की जानकारी देना और बच्चों की देख-रेख के बारे में महिलाओं की काउन्सलिंग करना।
- आशा महिलाएँ आँगनवाड़ी/उप-केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं, जैसे- टीकाकरण, (Immunization) प्रसव पूर्व देखभाल जाँच (ANC), प्रसव पश्चात् देखभाल जाँच, अनुपूरक पोषण, स्वच्छता (Sanitation) और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अन्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने का कार्य करती हैं।
- आशा द्वारा गर्भावस्था के प्रारम्भिक संसूचन (Detection) के लिये गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करने का कार्य भी किया जाता है।

3. UNDP के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित 'बहुआयामी निर्धनता सूचकांक' में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सम्मिलित है/हैं?

1. पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति तथा सेवाओं से वंचन

2. राष्ट्रीय स्तर पर क्रय-शक्ति समता

3. राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और GDP की विकास दर

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 2 और 3**

(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तरः (a)

व्याख्याः बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एक अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता मापक उपकरण है, जिसे ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा यूएनडीपी की फ्लैगशिप मानव विकास रिपोर्ट के लिये विकसित किया गया है। इस सूचकांक को 2010 में विकसित किया गया था और इसे यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट, 2010 में शामिल किया गया था। इस सूचकांक में कुल 10 संकेतक सम्मिलित हैं:

- शिक्षा, जिसमें **स्कूलिंग का वर्ष** और **विद्यालय में उपस्थिति** शामिल हैं।
- स्वास्थ्य, जिसमें **बाल मृत्यु** व **कुपोषण** शामिल हैं।
- जीवन स्तर, जिसमें शामिल हैं:
  - **विद्युत सुविधा का अभाव**
  - **पेयजल का अभाव**
  - **स्वच्छता (Sanitation) का अभाव**
  - **अस्वच्छ फर्श (Flooring)**
  - **खाना पकाने के ईंधन का अभाव**
  - **परिसंपत्तियों (Assets), जैसे- टीवी टेलीफोन, बाइक, मोटरबाइक, रेफ्रिजरेटर, कार अथवा ट्रैक्टर का अभाव।**

इस प्रकार कुल तीन श्रेणियों- शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के तहत कुल 10 संकेतकों के आधार पर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को मापा जाता है।

2011

1. भारत की गिनती 'जनांकिकीय लाभांश' (डेमोग्राफिक डिविडेंड) वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिये है, क्योंकि

(a) यहाँ 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है

(b) यहाँ 15-64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है

(c) यहाँ 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है

(d) यहाँ की कुल जनसंख्या अधिक है *सही उत्तरः* (b)

व्याख्याः भारत की गिनती जनांकिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) वाले देश के रूप में इसलिये की जाती है क्योंकि यहाँ 15–64 वर्ष आयु वर्ग की कार्यशील जनसंख्या अधिक है। आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस कार्यशील जनसंख्या को 15–64 आयु वर्ग के रूप में निरूपित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय संगठन/सम्मेलन

2025

1. BIMSTEC **के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजियेः**

I. यह जनवरी 2025 तक सात सदस्य देशों से मिलकर बना एक क्षेत्रीय संगठन है।

II. यह ढाका घोषणा, 1999 पर हस्ताक्षर होने के साथ अस्तित्व में आया।

III. बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाइलैंड और नेपाल BIMSTEC के संस्थापक सदस्य देश हैं।

IV. BIMSTEC में 'पर्यटन' उपक्षेत्र का नेतृत्व भारत कर रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल I और II **(b) केवल II और III**

(c) केवल I और IV **(d) केवल I**

सही उत्तरः (d)

व्याख्या: (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC):

- BIMSTEC एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच बहुआयामी तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
- **BIMSTEC से संबंधित प्रमुख तथ्य:** इसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं - बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्याँमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड (जनवरी 2026 तक)। **अतः कथन I सही है।**
- यह संगठन बैंकॉक घोषणा, 1997 को अपनाने के बाद अस्तित्व में आया। **अतः कथन II सही नहीं है।**
- बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड BIMSTEC के संस्थापक सदस्य देश थे, उस समय इस समूह को BIST-EC (इकोनॉमिक कोऑपरेशन) के नाम से जाना जाता था।
    - वर्ष 1997 में म्याँमार के शामिल होने पर इसका नाम BIMST-EC किया गया।
    - वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान के शामिल होने के बाद इसका नाम BIMSTEC रखा गया। **अतः कथन III सही नहीं है।**
- BIMSTEC में 'पर्यटन' उपक्षेत्र का नेतृत्व भारत द्वारा नहीं, बल्कि नेपाल द्वारा किया जाता है। **अतः कथन IV भी सही नहीं है।**

देश	क्षेत्र	उप-क्षेत्र
बांग्लादेश	व्यापार, निवेश और विकास	नीली अर्थव्यवस्था
भूटान	पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	पर्वतीय अर्थव्यवस्था
भारत	सुरक्षा	आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध विरोध, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा
म्यांमार	कृषि एवं खाद्य सुरक्षा	कृषि, मत्स्य पालन और पशुधन
नेपाल	लोगों से लोगों का संपर्क	संस्कृति, पर्यटन, गरीबी उन्मूलन, लोगों से लोगों के बीच संपर्क (थिंक टैंक, मीडिया आदि के मंच)
श्रीलंका	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार	प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास
थाईलैंड	कनेक्टिविटी	–

अतः विकल्प (d) सही है।

2. BRICS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

I. 16वाँ BRICS शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कज़ान में संपन्न हुआ था।

II. इंडोनेशिया BRICS का पूर्ण सदस्य बन गया है।

III. 16वाँ BRICS शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिये बहुसंस्कृतिवाद को सशक्त करना था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल I और II **(b) केवल II और III**

(c) केवल I और III **(d) केवल I**

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: 16वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन:

- 16वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अक्तूबर 2024 में रूस की अध्यक्षता में कज़ान में आयोजित हुआ। कज़ान घोषणा 2024 में गाज़ा में मानवीय संकट पर चिंता व्यक्त की गई, पश्चिमी देशों द्वारा लगाये गए एकतरफा प्रतिबंधों की आलोचना की गई, ब्रिक्स अनाज विनिमय (Grain Exchange) का प्रस्ताव रखा गया तथा सदस्य देशों के बीच वित्तीय एकीकरण को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया। **अतः कथन I सही है।**
- जनवरी 2025 को ब्राज़ील के विदेश मंत्रालय (जो वर्ष 2025 के लिये ब्रिक्स अध्यक्ष देश है) ने घोषणा की कि इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह में पूर्ण सदस्य (10वें सदस्य) के रूप में शामिल हो गया है। **अतः कथन II भी सही है।**
- 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम थी: "न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिये बहुपक्षीयता को सुदृढ़ बनाना", जो वैश्विक चुनौतियों से निपटने के प्रति इस समूह की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। **अतः कथन संख्या III सही नहीं है।**

अतः विकल्प (a) सही है।

3. अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

I. यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है।

II. यह गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिये अकेले ही कार्य करता है।

II. इसकी स्थापना द्वितीय विश्व-युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में कौन-कौन से सही हैं?

(a) केवल I और II

(b) केवल II और III

(c) केवल I और III

(d) I, II और III

सही उत्तर: (c)

व्याख्या:

- अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (जिसे विश्व बैंक का मुख्य ऋणदाता अंग माना जाता है) प्रमुख रूप से मध्यम आय वाले देशों और निम्न-आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। **अतः कथन I सही है।**

- **IBRD, विश्व बैंक समूह (World Bank Group) का एक भाग है, जिसमें निम्नलिखित संस्थाएँ शामिल हैं:**
  - अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD)
  - अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)
  - अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)
  - बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA)
  - अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र (ICSID)। ये सभी संस्थाएँ मिलकर कार्य करती हैं।
  - IBRD विशेष रूप से IDA के साथ मिलकर कार्य करती है, जिसे सामूहिक रूप से विश्व बैंक कहा जाता है।

  अतः कथन II सही नहीं है।
- IBRD की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। इसका प्रारंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध से क्षतिग्रस्त हुए यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण हेतु वित्तपोषण करना था। **अतः कथन III सही है।**

  अतः विकल्प (c) सही है।

2023

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

कथन-I: हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) और यूरोपीय संघ (ई.यू.) ने 'व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद्' प्रारंभ की है।

कथन-II: संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं।

उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।

(c) कथन-I सही है किंतु कथन-II गलत है।

(d) कथन-I गलत है किंतु कथन-II सही है।

सही उत्तर: **(c)**

व्याख्या: जून 2021 में, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और यूरोपीय संघ (EU) ने 'व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद्' (TTC) का गठन किया था।

- यूरोपीय संघ-अमेरिका व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद् संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ के लिये प्रमुख वैश्विक व्यापार, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी मुद्दों के दृष्टिकोण का समन्वय करने और साझा मूल्यों के आधार पर ट्रांस-अटलांटिक व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को मज़बूत करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 15 जून, 2021 को ब्रूसेल्स में यूरोपीय संघ-अमेरिका शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। **अतः कथन I सही है।**
- अमेरिका और यूरोपीय संघ ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्द्धचालक और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं जैसे मुद्दों पर ध्यान देने के साथ TTC के कार्यों पर चर्चा की।
- परिषद के माध्यम से यूरोपीय संघ और अमेरिका एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं:
  - व्यापार एवं प्रौद्योगिकी के सामान्य मूल्यों को बनाए रखते हुए समाज और अर्थव्यवस्था की सेवा सुनिश्चित करना
  - तकनीकी एवं औद्योगिक नेतृत्त्व को मज़बूत करना
  - द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार करना
  - **अतः कथन II सही नहीं है।**

  इसलिये विकल्प (c) सही उत्तर है।

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

यूरोपीय संघ का 'स्थिरता एवं संवृद्धि समझौता (स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट)' ऐसी संधि है, जो

1. यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है।

2. यूरोपीय संघ के देशों के लिये अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बाँटना सुकर बनाती है।

3. यूरोपीय संघ के देशों के लिये अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बाँटना सुकर बनाती है

उपर्युक्त में से कितने कथन सही है?

(a) केवल एक **(b) केवल दो**

(c) सभी तीन **(d) कोई भी नहीं**

सही उत्तर: **(a)**

व्याख्या: यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं संवृद्धि समझौता एक राजनीतिक समझौता है जो यूरोपीय मौद्रिक संघ (EMU) के सदस्य राज्यों के राजकोषीय घाटे तथा सार्वजनिक ऋण की सीमा निर्धारित करता है। **अतः कथन 1 सही है।**

- इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य किसी सदस्य राज्य की गैर-ज़िम्मेदार बजटीय नीतियों द्वारा पूरे यूरो क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता को असंतुलित होने से रोकने तथा EMU के अंतर्गत सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन को सुनिश्चित करना है।
- यूरोपीय संघ स्थिरता एवं संवृद्धि समझौता आधारिक संरचना सुविधाओं और प्रौद्योगिकियों को साझा करने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं करता है। यह समझौता केवल आँकड़ों और बजट के अनुशासन से संबंधित हैं। **अतः कथन 2 और 3 सही नहीं हैं।**

  इसलिये विकल्प (a) सही है।

2022

1. निम्नलिखित पर विचार कीजिये:

1. एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक)

2. प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम)

3. शंघाई सहयोग संगठन (शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाईज़ेशन)

भारत उपर्युक्त में से किसका/किनका सदस्य है?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: **(d)**

व्याख्या:

- AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करना है। AIIB की सदस्यता विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक के सभी सदस्यों के लिये खुली है, इसे क्षेत्रीय और गैर-क्षेत्रीय सदस्यों में विभाजित किया गया है।
- भारत AIIB का संस्थापक सदस्य है तथा इसका दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, जिसने $8.4 बिलियन का योगदान दिया है। **अत: कथन 1 सही है।**
- मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी (जो 300 किमी से अधिक दूरी के लिये 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम) के प्रसार को रोकने के लिये 35 देशों के बीच एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक साझेदारी है।
- भारत को वर्ष 2016 में 35वें सदस्य के रूप में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) में शामिल किया गया था। **अत: कथन 2 भी सही है।**
- SCO एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है, जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता को बनाए रखना है।
- भारत और पाकिस्तान 9 जून, 2017 को पूर्ण सदस्य के रूप में SCO में शामिल हुए। **इसलिये कथन 3 सही है।**

अत: विकल्प (d) सही है।

2. "त्वरित वित्तीयन प्रपत्र (Rapid Financing Instrument)" और "त्वरित ऋण सुविधा (Rapid Credit Facility)", निम्नलिखित में किस एक के द्वारा उधार दिये जाने के उपबंधों से संबंधित हैं?

(a) एशियाई विकास बैंक
(b) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(c) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल
(d) विश्व बैंक

सही उत्तर: **(b)**

व्याख्या: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) अपने सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की समस्याओं से निपटने के लिये विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। त्वरित वित्तीयन प्रपत्र (RFI) और त्वरित ऋण सुविधा (RCF) इसी का हिस्सा है।

त्वरित वित्तीयन प्रपत्र (Rapid Financing Instrument-RFI)

त्वरित वित्तीयन प्रपत्र त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो भुगतान संतुलन की तत्काल आवश्यकता का सामना करने वाले सभी सदस्य देशों के लिये उपलब्ध है। सदस्य देशों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये IMF की वित्तीय सहायता को और अधिक लचीला बनाने हेतु RFI को व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में बनाया गया था। RFI ने IMF की पिछली आपातकालीन सहायता नीति को प्रतिस्थापित किया है और इसका उपयोग कई तरह की परिस्थितियों में किया जा सकता है।

त्वरित ऋण सुविधा (Rapid Credit Facility-RCF)

त्वरित ऋण सुविधा निम्न आय वाले देशों (LIC) को तत्काल भुगतान संतुलन (BoP) की आवश्यकता प्रदान करती है, जिसमें कोई पूर्व-पोस्ट शर्त नहीं है, जहाँ एक पूर्ण आर्थिक कार्यक्रम न तो आवश्यक है और न ही व्यवहार्य। RCF की स्थापना एक व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में की गई थी ताकि फंड की वित्तीय सहायता को अधिक लचीला बनाया जा सके।

- RCF के तहत तीन क्षेत्र हैं:
  - घरेलू अस्थिरता, आपात स्थिति और नाजुकता जैसे स्रोतों की एक विस्तृत शृंखला के कारण तत्काल BoP ज़रूरतों के लिये एक 'नियमित खिड़की'
  - अचानक, बहिर्जात झटके की वजह से तत्काल BoP ज़रूरतों के लिये एक 'बहिर्जात शॉक विंडो' और
  - प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली तत्काल BoP ज़रूरतों के लिये एक 'बड़ी प्राकृतिक आपदा खिड़की' जहाँ क्षति सदस्य के सकल घरेलू उत्पाद के 20% के बराबर या उससे अधिक होने का अनुमान है। **अत: विकल्प (b) सही है।**

3. "G20 कॉमन फ्रेमवर्क" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है।

2. यह अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

सही उत्तर: **(c)**

व्याख्या: G20 कॉमन फ्रेमवर्क G20 देशों और पेरिस क्लब की संयुक्त पहल है। इस फ्रेमवर्क की खास बात यह है कि इसमें पहली बार G20 के सदस्य देशों को पेरिस क्लब के साथ मिलकर ऋण पुनर्गठन के लिये एक मंच पर लाया गया है। इसका उद्देश्य संरचनात्मक तरीके से, कम आय वाले देशों को अस्थिर (Unsustainable) ऋण के साथ समर्थन करना है। यह उन देशों पर केंद्रित है, जो ऋण सेवा निलंबन पहल (DSSI) के लिये पात्र थे। **इसलिये कथन (1) और (2) सही है।**

अतः विकल्प (c) सही है।

2020

1. निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं?

(a) अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की

(b) ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एवं न्यूज़ीलैंड

(c) ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब एवं वियतनाम

(d) इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: 'G-20' अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है, इसमें वित्तीय और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिये दुनिया की सबसे बड़ी विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं। 'G-20' की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के निर्माण के लिये औद्योगिक देशों और उभरते हुए बड़े बाज़ारों के मध्य नीतिगत मुद्दों की समीक्षा तथा अध्ययन के उद्देश्य से की गई थी।

'G-20' में शामिल सदस्य देश हैं- अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाड़ा, चीन, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ। **अतः विकल्प (a) सही है।**

2019

1. एशियाई आधारिक-संरचना निवेश बैंक [एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (AIIB)] के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं।

2. AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है।

3. AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2 और 3**

(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जिसका मुख्य उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अवसंरचना विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है।

- वर्तमान में जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार बैंक में कुल मेंबरशिप 103 है, जिनमें 46 रीजनल, 41 नॉन-रीज़नल मेंबर्स, 16 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स शामिल हैं। अतः कथन 1 सही है।
- बैंक की अधिकृत पूंजी (Authorized Capital) 100 बिलियन डॉलर है। चीन, भारत एवं रूस क्रमशः बैंक के तीन सबसे बड़े शेयरधारक एवं मताधिकार वाले देश हैं। अतः कथन 2 गलत है।
- अमेरिका एवं जापान को छोड़कर विश्व के लगभग सभी विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश बैंक में शामिल हैं। अतः तीसरा कथन भी गलत है।

संबंधित तथ्य

- एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) की स्थापना का प्रस्ताव पहली बार 'चाइना सेंटर फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स' नामक चीनी थिंक टैंक के उपाध्यक्ष द्वारा अप्रैल 2009 में बोआवो फोरम (Boao Forum) में प्रस्तुत किया गया।
- AIIB का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है।
- बैंक के पहले अध्यक्ष के रूप में चीन के पूर्व वित्त मंत्री जिन लिकुन (Jin Liqun) को नियुक्त किया गया था।

2. निम्नलिखित में से कौन-सा एक विश्व बैंक के 'कारोबार सुगमता सूचकांक (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स)' का उप-सूचकांक नहीं है?

(a) कानून और व्यवस्था बनाए रखना

(b) करों का भुगतान कराना

(c) संपत्ति का पंजीकरण करना

(d) निर्माण परमिट संबंधी कार्य कराना

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: डूइंग बिज़नेस, व्यापार के 11 क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले नियमों की समीक्षा करता है। इन क्षेत्रों में से 10 को ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स रैंकिंग-2019 में शामिल किया गया है। ये 10 क्षेत्र हैं-

1. बिज़नेस शुरुआत करने का माहौल
2. कंस्ट्रक्शन परमिट में सुगमता
3. बिज़नेस के लिये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन
4. रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोपर्टी
5. बिज़नेस के लिये क्रेडिट उपलब्ध कराने के मामले में
6. अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा करने के मामले में
7. टैक्स भरने में
8. सीमा पार व्यापार के मामले में
9. कॉन्ट्रैक्ट्स लागू करने के मामले में
10. दिवालिया मामलों का समाधान

नोट: ध्यातव्य है कि डूइंग बिज़नेस में 'लेबर मार्केट रेग्यूलेशन' की भी माप की जाती है, लेकिन इस वर्ष की रैंकिंग में इसे शामिल नहीं किया गया है। वर्ष 2018 से 2020 की इन रिपोर्ट्स में पाई गईं अनियमितताओं के कारण विश्व बैंक ने इसे आगे जारी नहीं रखने का निर्णय लिया है।

अतः प्रश्नानुसार, विकल्प (a) सही उत्तर है।

2018

1. भारत में माल के भौगोलिक संकेत (रजिस्ट्रेशन और संरक्षण) अधिनियम, 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिये लागू किया गया?

(a) आई.एल.ओ. **(b) आई.एम.एफ.**
(c) यू.एन.सी.टी.ए.डी. **(d) डब्ल्यू.टी.ओ.**

सही उत्तर: **(d)**

व्याख्या: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI का विनियमन WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (TRIPS)पर समझौते के तहत किया जाता है।

2. भारत के संदर्भ में 'अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.)' के 'अतिरिक्त नयाचार (एडीशनल प्रोटोकॉल)' का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है?

(a) असैनिक परमाणु रिऐक्टर आई.ए.ई.ए. के रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं।
(b) सैनिक परमाणु अधिष्ठान आई.ए.ई.ए. के निरीक्षण के अधीन आ जाते हैं।
(c) देश के पास नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह (एन.एस.जी.) से यूरेनियम के क्रय का विशेषाधिकार हो जाएगा।
(d) देश स्वतः एन.एस.जी. का सदस्य बन जाता है।

सही उत्तर: **(a)**

व्याख्या: भारत ने असैनिक परमाणु संयंत्रों में सुरक्षा उपाय लागू करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) के साथ अतिरिक्त नयाचार (एडीशनल प्रोटोकॉल) का अनुसमर्थन करने का निर्णय लिया और भारत सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच 2009 में अतिरिक्त नयाचार पर हस्ताक्षर किये गए। 25 जुलाई, 2014 को भारत सरकार और आई.ए.ई.ए. के बीच सुरक्षा उपायों के लिये एक अतिरिक्त नयाचार लागू हुआ। इसके अनुसार भारत के असैनिक परमाणु रिएक्टर आई.ए.ई.ए. के रक्षोपायों के अधीन आ गए हैं। अतः कथन **(a)** सही है, जबकि **(b), (c)** और **(d)** सही नहीं हैं।

3. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिये-

1. ऑस्ट्रेलिया **2. कनाडा**
3. चीन **4. भारत**
5. जापान **6. यू.एस.ए.**

उपर्युक्त में से कौन-कौन आसियान (ए.एस.इ.ए.एन.) के 'मुक्त व्यापार भागीदारों' में से हैं?

(a) 1, 2, 4 और 5 **(b) 3, 4, 5 और 6**
(c) 1, 3, 4 और 5 **(d) 2, 3, 4 और 6**

सही उत्तर: **(c)**

व्याख्या: आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारी वाले देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत एवं जापान हैं। इसलिये, 1, 3, 4 और 5 सही हैं, जबकि 2 और 6 सही नहीं हैं क्योंकि कनाडा एवं यू.एस.ए. आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारी वाले देश नहीं हैं। आसियान की स्थापना 8 अगस्त, 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। वर्तमान में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके दस सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। आसियान डिक्लेरेशन के अनुसार, आसियान का लक्ष्य दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेज़ी लाने हेतु निरंतर प्रयास करना है।

4. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभिसमय किससे संबंधित हैं?

(a) बाल श्रम
(b) कृषि के तरीकों का वैश्विक जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन
(c) खाद्य कीमतों एवं खाद्य सुरक्षा का विनियमन
(d) कार्यस्थल पर लैंगिक समानता

सही उत्तर: **(a)**

व्याख्या: भारत ने जून 2017 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जेनेवा सम्मेलन में बालश्रम संबंधी दो प्रमुख अभिसमयों (अभिसमय 138 और अभिसमय 182) की पुष्टि कर दी। इसी के साथ भारत 'बाल मज़दूरी के सबसे खराब स्वरूप को समाप्त करने की वैश्विक प्रतिबद्धता' (अभिसमय 182) और 'बच्चों को न्यूनतम बुनियादी शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने (अभिसमय 138) संबंधी ILO के अभिसमयों की पुष्टि करने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया। इन दो अभिसमयों की पुष्टि के बाद भारत ILO के कुल 8 कोर अभिसमयों में से 6 की पुष्टि करने वाला देश बन गया है।

5. किसी देश के 'नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह' के सदस्य बनने का/के क्या परिणाम है/हैं?

1. इसकी पहुँच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी।
2. यह स्वमेव "नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि" (एन.पी.टी.) का सदस्य बन जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**
(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1, न ही 2**

सही उत्तर: **(a)**

व्याख्या: नाभिकीय आपूर्तिकर्त्ता समूह 48 देशों का समूह है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्राँस, चीन एवं रूस परमाणु क्षमता से संपन्न राष्ट्र हैं जिन्होंने एन.पी.टी. (नाभिकीय अप्रसार संधि) पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

- नाभिकीय आपूर्तिकर्त्ता समूह का सदस्य बनने के पश्चात् संबंधित देश की नवीनतम एवं कुशल परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुँच सुनिश्चित हो जाती है। इसलिये कथन 1 सही है।
- हालाँकि एन.पी.टी. पर हस्ताक्षर न करने के आधार पर इस समूह की सदस्यता का विरोध किया जाता है किंतु इसके आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि वह राष्ट्र NSG का सदस्य बनने के उपरांत स्वमेव NPT का सदस्य बन जाएगा। इसलिये कथन 2 सही नहीं है।

6. "विधि का नियम सूचकांक" (रूल ऑफ लॉ इंडेक्स) को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है?

(a) एमनेस्टी इंटरनेशनल
(b) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
(c) संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयुक्त कार्यालय
(d) विश्व न्याय परियोजना

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: 'रूल ऑफ लॉ इंडेक्स' अमेरिका के एक बहुविषयक संगठन 'वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट' द्वारा जारी किया जाता है।

2017

1. निम्नलिखित में से कौन, विश्व के देशों के लिये 'सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक (ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स)' का श्रेणीकरण प्रदान करता है?

(a) विश्व आर्थिक मंच
(b) UN मानव अधिकार परिषद्
(c) UN वूमन
(d) विश्व स्वास्थ्य संगठन

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पहली बार 2006 में विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा प्रकाशित की गई थी। 2016 की रिपोर्ट में 144 प्रमुख और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स लैंगिक समानता को मापने के लिये डिज़ाइन किया गया सूचकांक है।

2. समाचारों में आने वाला 'डिजिटल एकल बाज़ार कार्यनीति (डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी)' पद किस निर्दिष्ट करता है?

(a) ASEAN को **(b) BRICS को**
(c) EU को **(d) G20 को**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: 'डिजिटल एकल बाज़ार कार्यनीति' यूरोपीय संघ के एकल बाज़ार क्षेत्र से संबंधित है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और दूरसंचार को शामिल किया जाता है। इसकी घोषणा जून 2015 में यूरोपीय आयोग द्वारा की गई थी। **अत: विकल्प (c) सही है।**

2016

1. 'रीजनल कॉम्प्रिहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (Regional Comprehensive Economic Partnership)' पद प्राय: समाचारों में देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में आता है। देशों के उस समूह को क्या कहा जाता है?

(a) G20 **(b) ASEAN**
(c) SCO **(d) SAARC**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का संबंध आसियान (ASEAN) देशों से है।

इस पार्टनरशिप का उद्देश्य आसियान देशों के मध्य मुक्त व्यापार (free Trade) समझौते से है। इसकी घोषणा आसियान सम्मेलन पेन्ह (कंबोडिया) में 20 नवंबर, 2012 को की गई। आसियान सदस्य देश इस प्रकार हैं- ब्रुनेई, म्याँमार, कंबोडिया, इण्डोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। साथ ही यह मुक्त व्यापार समझौता छ: अन्य देशों के साथ भी आसियान समूह ने किया है। ये छ: देश हैं- ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडिया, जापान, दक्षिणी कोरिया और न्यूज़ीलैण्ड।

2. हाल ही में IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है?

(a) रूबल **(b) रैंड**
(c) भारतीय रुपया **(d) रेनमिनबी**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: हाल में IMF के SDR बास्केट में चीन की मुद्रा युआन जिसे रेनमिनबी भी कहा जाता है, को जोड़ा गया। डॉलर, यूरो, येन, पाउंड स्टर्लिंग पहले ही इस बास्केट से सम्बद्ध हैं।

3. अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति [International Monetary and Financial Committee (IMFC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. IMFC विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को उसके कार्य की दिशा पर सलाह देता है।
2. IMFC की बैठकों में विश्व बैंक प्रेक्षक की भाँति भाग लेता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: आईएमएफसी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नीति निर्धारक फोरम है। इसकी स्थापना 30 सितंबर, 1999 को 'आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नेन्स' के द्वारा की गई। यह 'आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नेन्स' को अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय प्रणाली के प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण पर सलाह और रिपोर्ट देता है। इसके साथ सिस्टम को बाधित करने वाले कुछ अनफोल्डिंग इवेंट्स (Unfolding Events) की जानकारियाँ भी प्रदान करता है। कार्यकारी बोर्ड द्वारा किसी समझौते में संशोधन के लिये मांगे गए प्रस्ताव पर आईएमएफसी अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है तथा उन अन्य मामलों पर भी सलाह दे सकता है जिन पर 'बोर्ड ऑफ गवर्नेन्स' द्वारा सुझाव मांगा गया हो। यद्यपि, आईएमएफसी के पास औपचारिक निर्णय लेने की शक्ति नहीं है परंतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य एवं नीतियों के लिये रणनीतिक दिशा प्रदान करने हेतु यह एक महत्त्वपूर्ण साधन बन गया है।

आईएमएफसी में 24 सदस्य हैं जो केंद्रीय बैंकों के गवर्नर या मंत्री या इनके तुलनीय रैंक के अधिकारी होते हैं। आमतौर पर ये सदस्य आईएमएफ के 190 सदस्य देशों के गवर्नर होते हैं। प्रत्येक सदस्य देश कार्यकारी निदेशक नियुक्त करते हैं तथा सदस्य देशों का प्रत्येक समूह एक कार्यकारी निदेशक का चुनाव करता है। वर्तमान में 'Banco de Maxico' की गवर्नर आगस्टीन कार्सटेन्स (Agustin Carstens) इन समूहों की अध्यक्ष हैं। आईएमएफसी का अध्यक्ष सर्व-सहमति से बनाया जाता है तथा यह समिति आम सहमति द्वारा संचालित होती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति तीन वर्षों के लिये होती है। इसके संचालन के लिये शब्द सीमा (Term Limits) का कोई औपचारिक नियम नहीं है। यहाँ तक कि कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ एवं विश्व बैंक भी आईएमएफसी की बैठकों में प्रेक्षक के रूप में भाग लेते हैं।

अत: अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करती है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उसके कार्य की दिशा पर सलाह भी देती है। इसकी बैठकों में विश्व बैंक प्रेक्षक के रूप में भाग लेता है।

4. 'व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक (Ease of Doing Business Index)' में भारत की रैंकिंग समाचार-पत्रों में कभी-कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है?

(a) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)
(b) विश्व आर्थिक मंच
(c) विश्व बैंक
(d) विश्व व्यापार संगठन (WTO)

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: व्यापार करने में सुविधा का सूचकांक (Ease of Doing Business) की घोषणा वर्ल्ड बैंक द्वारा की जाती है। व्यापार करने में सुविधा का सूचकांक 2016 में 190 देशों की सूची में भारत का स्थान 130वाँ रहा जो पूर्व में 142वाँ था।

'व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक (Ease of Doing Business Index)' किसी भी देश में व्यापार या व्यवसाय करने योग्य स्थितियों एवं सुविधाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि किसी देश में व्यवसाय करने के लिये नियम कितने सरल या कठिन हैं, कितना जोखिम है, व्यवसाय से बाहर निकलने की प्रक्रिया, अवसंरचना या सरकार की नीतियाँ कैसी हैं? इन सभी पहलुओं को देखकर ही सूचकांक का निर्धारण किया जाता है। इस मामले में भारत में सुधार देखा गया है।

5. 'वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Global Financial Stability Report)' किसके द्वारा तैयार की जाती है?

(a) यूरोपीय केंद्रीय बैंक
(b) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(c) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक
(d) आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (Organization for Economic Cooperation and Development)

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तैयार की जाती है।

'वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' वैश्विक स्तर पर वित्तीय व्यवस्था और उभरते बाज़ारों की स्थिति का आकलन प्रस्तुत करती है। मुख्यत: यह रिपोर्ट समसामयिक आर्थिक गतिविधियों पर नज़र रखकर वहाँ आर्थिक व्यापार व समावेशन हेतु स्थितियों का जायज़ा लेती है। साथ ही वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्वानुमानों पर भी गौर किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था से सम्बधित सभी गतिविधियों पर ध्यान देकर ही रिपोर्ट तैयार की जाती है।

2015

1. 'विश्व आर्थिक सम्भावना (ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स)' रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है?

(a) एशिया विकास बैंक
(b) यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट)
(c) यू.एस. फेडरल रिज़र्व बैंक
(d) विश्व बैंक

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: विश्व आर्थिक संभावना (ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स) रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। इसके अलावा विश्व बैंक जिन प्रमुख रिपोर्टों को जारी करता है, वे हैं- कमोडिटी मार्केट आउटलुक, विश्व विकास रिपोर्ट, ग्लोबल मॉनीटरिंग रिपोर्ट, डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेब्ट (Debt) स्टेटिस्टिक्स।

2014

1. निम्नलिखित में से कौन-सा संगठन 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है?

(a) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

(b) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
(c) विश्व आर्थिक फोरम
(d) विश्व बैंक

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' एक महत्त्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक प्रकाशन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रत्येक वर्ष अप्रैल और सितंबर/अक्तूबर माह में जारी किया जाता है। इसमें वैश्विक स्तर पर आर्थिक घटनाओं व स्थितियों के बारे में आकलन किया जाता है और समष्टि आर्थिक आँकड़े (Macro Economic Data) प्रस्तुत किये जाते हैं। आईएमएफ की तरफ से ये आँकड़े 1980 से अब तक जारी किये जा रहे हैं। कुछ अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रकाशन व उनको जारी करने वाले संस्थान/संगठन निम्नवत् हैं-

- ग्लोबल फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट : आई.एम.एफ.
- फिस्कल मॉनिटर : आई.एम.एफ.
- ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट : विश्व आर्थिक फोरम
- ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट : विश्व आर्थिक फोरम
- वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट : विश्व बैंक
- ग्लोबल ट्रेंड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी : यूनेप (UNEP)
- अवर प्लैनेट : यूनेप
- ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक : यूनेप व सीबीडी
- ग्रीन इकोनॉमी रिपोर्ट : यूनेप
- वर्ल्ड इनवेस्टमेंट रिपोर्ट : अंकटाड (1991 से)
- ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट : विश्व बैंक
- ग्लोबल मॉनीटरिंग रिपोर्ट : विश्व बैंक
- वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट : डब्ल्यू.टी.ओ.
- इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स : डब्ल्यू.टी.ओ.
- ग्लोबल इनवायरनमेंट आउटलुक : यूनेप
- वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक : अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग
- मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट : यूएनडीपी
- ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट : यूएनडीपी
- ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट : यू.एन. हैबिटेट

2011

1. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(a) यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है
(b) यह केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान कर सकता है
(c) यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है
(d) यह किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान कर सकता है

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में अमेरिका में ब्रेटनवुड्स के 1944 के समझौते के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या से निपटना और स्थिर विनिमय दरों को कायम करने से सम्बन्धित था। यह अल्पकालीन भुगतान शेष की समस्याओं से निपटने आदि का कार्य करता है।

उद्योग

2025

1. भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये:

(संगठन)		(संघ का मंत्रालय)
I. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड	:	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
II. कॉयर बोर्ड	:	भारी उद्योग मंत्रालय
III. राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र	:	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक **(b) केवल दो**
(c) सभी तीन **(d) कोई भी नहीं**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या:

- राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड (NAB) भारत में ऑटोमोटिव क्षेत्र के विकास, अनुसंधान, नवाचार, परीक्षण और मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिये गठित एक स्वायत्त निकाय है जो भारी उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। यह ऑटोमोटिव क्षेत्र विशेष रूप से FAME इंडिया स्कीम जैसी पहलों के परीक्षण, प्रमाणन और कार्यान्वयन से संबंधित कार्य करता है। **अतः युग्म I सही सुमेलित नहीं है।**
- कॉयर बोर्ड भारत सरकार द्वारा कॉयर उद्योग अधिनियम, 1953 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो नारियल रेशा उद्योग के विकास और प्रचार-प्रसार के लिये उत्तरदायी है। यह वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। **अतः युग्म II सही सुमेलित नहीं है।**
- राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (NCTI) की स्थापना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा व्यापार संबंधी आँकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार तथा व्यापार संबंधी सूचना सेवाओं में सुधार हेतु की गई है। **इसलिये युग्म III सही सुमेलित नहीं है।**

अतः विकल्प (d) सही है।

2023

1. निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिये:

1. ब्रांड पहचान **2. माल-सूची**
3. बौद्धिक संपदा **4. ग्राहकों की डाक सूची**

उपर्युक्त में से कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं?

(a) केवल एक **(b) केवल दो**
(c) केवल तीन **(d) सभी चार**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या:

- अमूर्त निवेश (Intangible Investments) से तात्पर्य उन संपत्तियों में निवेश करने में जिन्हें भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता परंतु वे किसी भी अर्थव्यवस्था या व्यवसाय के मूल्यवर्द्धन में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
- वे प्रकृति में गैर-भौतिक हैं और एक वर्ष या उससे अधिक हेतु उपयोग किये जा सकते हैं, इसमें ब्रांड मूल्य, सद्भावना और बौद्धिक संपदा जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, संगठनात्मक पूंजी आदि शामिल हैं।
- मूर्त निवेश (Tangible Investment) से तात्पर्य ऐसे संपत्तियों में निवेश करने से है, जिन्हें भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। इसके उदाहरणों में सूची, भवन, रोलिंग स्टॉक, निर्माण उपकरण या मशीनरी और कार्यालय फर्नीचर शामिल हैं। **अतः विकल्प (c) सही है।**

2. भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एम.एस.एम.ई.डी.) अधिनियम 2006' के अनुसार, 'जिनके संयंत्र और मशीन में निवेश 15 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये के बीच हैं, वे मध्यम उद्यम हैं'।

2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिये गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्रक के अधीन अर्ह हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/है?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**
(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1 और न ही 2**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: 2006 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार (2006) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण इन उद्योगों में संयंत्र और मशीनरी में निवेश के आधार पर किया जाता था।

वर्गीकरण	विनिर्माण उद्यम	सेवा उद्यम
सूक्ष्म	₹25 लाख तक	₹10 लाख तक
लघु	₹25 लाख से ₹5 करोड़ तक	₹10 लाख से ₹2 करोड़ तक
मध्यम	₹5 करोड़ से ₹10 करोड़ तक	₹2 करोड़ से ₹5 करोड़ तक

अतः कथन 1 सही नहीं हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की नई परिभाषा और मानदंड 1 जुलाई, 2020 से लागू हुई जो नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

Further Revised MSME Classification (Announced by Union Minister Prakash Javdekar			
Composite Criteria : Investment and Annual Turnover			
Classification	Micro	Small	Medium
Manufracturing & Services	Investment < ₹1 Cr. and Turnover < ₹5 Cr.	Investment < ₹10 Cr. and Turnover < ₹50 Cr.	Investment < ₹50 Cr. and Turnover < ₹250 Cr.

नोट: भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) की नई परिभाषा को संशोधित किया है, जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी है। जिसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है–

NEW Classification of MSME				
Type	Investment		Turnover	
	Current	Revised	Current	Revised
Micro Enterprise	₹1Cr	₹2.5Cr	₹5Cr	₹10Cr
Small Enterprise	₹10Cr	₹25Cr	₹50Cr	₹100Cr
Medium Enterprise	₹50Cr	₹125Cr	₹250Cr	₹500Cr
Source: *Budget 2025-2026, Speech of Nirmala Sitharaman, Union Minister of Finance Feburary 1, 2025*				

- **प्राथमिकता क्षेत्रक को ऋण दिशा-निर्देश:** 4 सितंबर, 2020 के 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण (PSL)- लक्ष्य और वर्गीकरण' पर प्रमुख निर्देशों के अनुसार, निर्धारित शर्तों के अनुरूप **MSME को दिये गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्रक के अधीन अहर्ता रखते हैं।**
- MSME अधिनियम, 2006 के तहत उपकरणों में निवेश के संदर्भ में परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के लिये) को बैंक ऋण, ऋण सीमा के बावजूद, ऋण प्राथमिकता क्षेत्रक के अधीन अर्हता रखते हैं, जो कि 1 मार्च, 2018 से प्रभावी हैं। **अतः कथन 2 सही है।**

2022

1. भारत में, निम्नलिखित में कौन एक, उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं, औद्योगिक विवादों, समापनों, छँटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है?

(a) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
(b) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
(c) श्रम ब्यूरो
(d) राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: भारत में औद्योगिक विवादों, बंदियों, छँटनी और छँटनी पर सांख्यिकी श्रम ब्यूरो का एक वार्षिक प्रकाशन है जो श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है। **अतः विकल्प (c) सही है।**

श्रम ब्यूरो

- श्रम और रोज़गार मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय के रूप में श्रम ब्यूरो की स्थापना 1 अक्तूबर, 1946 को की गई थी।
- श्रम ब्यूरो मज़दूरी, कमाई, उत्पादकता, अनुपस्थिति, श्रम कारोबार, औद्योगिक संबंध, काम करने और रहने की स्थिति तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों के कामकाज के मूल्यांकन आदि के संबंध में आँकड़े एवं संबंधित जानकारी एकत्रित व प्रकाशित करता है। उद्योगों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या जैसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों के अलावा, कृषि और ग्रामीण मज़दूर; मज़दूरी दर सूचकांक और औद्योगिक संबंधों पर आँकड़े, संगठित और असंगठित क्षेत्र में उद्योगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति आदि भी कार्यालय द्वारा जारी किये जाते हैं।

2020

1. भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाज़ार-संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है।

2. अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है, वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है।

3. सल्फर, जो फॉस्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिये कच्चा माल है, वह तेल शोधन कारखानों का उपोत्पाद है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 2

(d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: **(b)**

व्याख्या: रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन एक पोषक तत्त्व या कई पोषक तत्त्वों वाले रासायनिक रूपों में किया जाता है। एक पोषक तत्त्व वाले उर्वरकों को 'सीधे उर्वरक' तथा बहु-पोषक तत्त्वों वाले उर्वरकों को 'मिश्रित उर्वरक' कहा जाता है। यूरिया को छोड़कर अधिकांश उर्वरक बहु-पोषक तत्त्वों वाले होते हैं। यूरिया पानी में घुलनशील एक कार्बनिक रसायन है, जिसका निर्माण अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से एक उच्च दबाव और तापमान वाली औद्योगिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। अमोनिया का उत्सर्जन प्राकृतिक गैस से होता है। इसके अतिरिक्त सल्फर तेल शोधन और गैस प्रसंस्करण का एक प्रमुख उपोत्पाद है।

अधिकांश कच्चे तेल ग्रेड में कुछ सल्फर होते हैं, जिनमें से अधिकांश को परिष्कृत उत्पादों में कठोर सल्फर को शोधन प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है।

वर्तमान में किसानों को वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर यूरिया प्रदान किया जा रहा है। सरकार के नियंत्रण में यूरिया निर्माता/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। **अतः विकल्प (b) सही है।**

2017

1. 'पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम (रिकग्निशन ऑफ़ प्रायर लर्निंग स्कीम)' का कभी-कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है?

(a) निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन

(b) दूरस्थ अधिगम कार्यक्रमों के लिये विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों को पंजीकृत करना।

(c) सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में ग्रामीण और नगरीय निर्धन लोगों के लिये कुछ कुशल कार्य आरक्षित करना

(d) राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाणन

सही उत्तर: **(a)**

व्याख्या: यह योजना देश के कई राज्यों मे चल रही है जिसमें निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों द्वारा पारंपरिक शिक्षण माध्यमों से अर्जित कौशल को प्रमाणित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय तथा कौशल विकास मंत्रालय ने इन राज्यों में 200 से अधिक श्रमिकों वाले निर्माण स्थलों पर ध्यान केंद्रित किया है।

2. 'भारतीय गुणता परिषद् (QCI)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. QCI का गठन, भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

2. QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति, उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर, प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

सही उत्तर: **(c)**

व्याख्या: QCI का गठन 1997 में भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। मुख्यतः तीन संगठनों ASSOCHAM, FICCI एवं CII ने भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व किया था। इस काउंसिल का मुख्य उद्देश्य देश भर में किसी उत्पाद की गुणवत्ता के लिये मानक निर्धारित कर अच्छी-से-अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। भारत सरकार का 'औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग' QCI के लिये नोडल एजेंसी है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को दी गई संस्तुतियों के आधार पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

2016

1. 'स्टैंड अप इंडिया स्कीम (Stand Up India Scheme)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. इसका प्रयोजन SC/ST एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है।

2. यह SIDBI के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: प्रधानमंत्री द्वारा 5 अप्रैल, 2016 को लॉन्च की गई 'स्टैंड अप इंडिया स्कीम' के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। 'स्टैंड अप इंडिया स्कीम' अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के वित्तीयन हेतु शुरू की गई है। 'स्टैंड अप इंडिया' योजना का उद्देश्य युवाओं व पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमशीलता व वित्तीयन को बढ़ाना है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम-से-कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्त्ता और एक महिला उधारकर्त्ता को नई (ग्रीनफील्ड) परियोजना की स्थापना हेतु ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का बैंक ऋण प्रदान करना है। ये उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। गैर-व्यक्ति उद्यम के मामले में 51% शेयरधारिता व नियंत्रक हिस्सेदारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिये।

SIDBI के माध्यम से पुनर्वित्त (refinance) का प्रावधान है। SIDBI के माध्यम से ₹ 10 हज़ार करोड़ की प्रारम्भिक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

2. प्रधानमंत्री MUDRA योजना का लक्ष्य क्या है?

(a) लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना

(b) निर्धन कृषकों को विशेष फसलों की कृषि के लिये ऋण उपलब्ध कराना

(c) वृद्ध एवं निस्सहाय लोगों को पेंशन देना

(d) कौशल विकास एवं रोज़गार सृजन में लगे स्वयंसेवी संगठनों का निधीयन (फंडिंग) करना

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) योजना का लक्ष्य लघु उद्यमियों को ऋण प्रदान करके औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है।

मुद्रा (MUDRA) योजना का उद्देश्य:

- मुद्रा बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे उद्योगों को साहूकारों की सूदखोरी से बचाना है। इस योजना के तहत कुटीर व्यवसाय शुरू करने वाले आसानी से लोन ले सकेंगे।
- मुद्रा योजना के तहत उद्योग सम्बन्धी प्रशिक्षण एवं व्यापार की छोटी-मोटी बातें भी बताई जाएंगी जिससे व्यवसायी अपने व्यापार को बढ़ा सके।
- यह ज़रूरतमंदों के लिये सहायता और वित्तीय मदद जल्दी से मुहैया कराएगी ताकि सही समय पर व्यवसाय प्रारंभ हो सके।

2015

1. 'आठ मूल उद्योगों के सूचकांक (इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज़)' में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है?

(a) कोयला उत्पादन **(b) विद्युत उत्पादन**

(c) उर्वरक उत्पादन **(d) इस्पात उत्पादन**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: आठ मूल उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक महत्त्व विद्युत उत्पादन (भारांश: 10.32 प्रतिशत) को दिया गया है। इसके अलावा अन्य उद्योगों का महत्त्व उनके भारांश के रूप में जून 2015 तक के आँकड़ों के अनुसार निम्नवत् है:

- कोयला उत्पादन (4.38 प्रतिशत)
- कच्चा तेल उत्पादन (5.22 प्रतिशत)
- प्राकृतिक गैस उत्पादन (1.71 प्रतिशत)
- रिफाइनरी उत्पाद (5.94 प्रतिशत)
- उर्वरक उत्पादन (1.25 प्रतिशत)
- इस्पात उत्पादन (6.68 प्रतिशत)
- सीमेंट उत्पादन (2.41 प्रतिशत)
- इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल मदों में आठ मूल उद्योगों (Core Industries) की भागीदारी लगभग 38% है।

2014

1. जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है?

(a) उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालीन पूंजी।

(b) नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी।

(c) उद्योगों को हानि उठाते समय उपलब्ध कराई गई निधियाँ।

(d) उद्योगों के प्रतिस्थापन एवं नवीकरण के लिये उपलब्ध कराई गई निधियाँ

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: समृद्ध निवेशक दीर्घकालिक संवृद्धि परिप्रेक्ष्य वाले व्यवसायों (growth perspective) को ध्यान में रखकर अपनी पूंजी का निवेश करना पसंद करते हैं। नए उद्यमी जो नई कंपनियों (Start-ups) की शुरुआत कर रहे हों और जिनमें विकास की संभावना विद्यमान रहती है, इनमें

निवेशित पूंजी को जोखिम पूंजी कहते हैं। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह अच्छा लाभ दिला सकती है अन्यथा यह असुरक्षा, जोखिम भरा परिणाम दे सकती है।

2013

1. भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन-सा एक, पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है?

(a) अभियांत्रिकी **(b) कागज़ एवं लुगदी**
(c) वस्त्रोद्योग **(d) तापशक्ति**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: वर्ष 2004 में 'सेन्टर फॉर साइंस एंड इनवायरमेन्ट' ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा **भारत में जल गुणवत्ता स्थिति एवं प्रवृत्ति (1990–2001)** में प्रकाशित **वेस्टवाटर डिस्चार्ज डाटा** के हवाले से स्पष्ट किया था कि भारत में पानी के सबसे बड़े उपभोक्ता उद्योगों की स्थिति निम्नवत् है:

स्थान		**उद्योग**
पहला	–	तापीय ऊर्जा संयंत्र (88%)
दूसरा	–	अभियांत्रिकी (5.05%)
तीसरा	–	पल्प एंड पेपर (2.26%)
चौथा	–	वस्त्रोद्योग (2.07%)
पाँचवा	–	इस्पात (1.29%)
छठा	–	गन्ना (0.49%)
सातवाँ	–	उर्वरक (0.18%)

इन रिपोर्टों के अनुसार, तापीय ऊर्जा संयंत्र का वार्षिक जल उपभोग 35157.4 मिलियन क्यूबिक मीटर था, जबकि अन्यों का क्रमश: 2019.9, 905.8, 829.8, 516.6, 194.9, 73.5 मिलियन क्यूबिक मीटर था। **अत: विकल्प (d) सही है।**

2012

1. विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार ने कौन-सी नई नीतिगत पहल/पहलें की है/हैं?

1. राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना
2. एकल खिड़की मंजूरी (सिंगल विंडो क्लीयरेंस) की सुविधा प्रदान करना
3. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 2 और 3**
(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये शुरू की गई थी, इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में योगदान एक दशक के भीतर (2022 तक) 25 प्रतिशत करना और 100 मिलियन अतिरिक्त रोज़गारों का सृजन करना।
- विनिर्माण क्षेत्र में अवसंरचनाओं के विकास के लिये पीपीपी मॉडल अपनाना।
- राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों का गठन।
- एकल खिड़की मंजूरी का प्रावधान।
- प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष का गठन।
- हरित विनिर्माण प्रोत्साहन जिसमें पर्यावरण संगणना, जल संरक्षण तथा व्यर्थ जल का उपचार शामिल हैं।
- औद्योगिक प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन प्रयास।

2011

1. भारत सरकार 'मेगा फूड पार्क' की अवधारणा को किन-किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है?

1. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिये उत्तम अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु।
2. खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु।
3. उद्यमियों के लिये उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध कराने हेतु।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 1 और 2**
(c) केवल 2 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: भारत सरकार 'मेगा फूड पार्क' की अवधारणा को निम्न उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है:

- देश में एक सुदृढ़ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना।
- प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिये प्रभावी आपूर्ति शृंखला का गठन।
- संग्रहण केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों और कोल्ड चेन अवसंरचनाओं के रूप में खाद्य प्रसंस्करण के लिये आधुनिक अवसंरचनाओं का गठन।
- खाद्य अपशिष्टों का न्यूनीकरण करते हुए कृषकों की आजीविका में सुधार।
- एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के साथ कृषि क्षेत्र से बाज़ार तक एक मूल्य शृंखला तैयार करना।
- हब और स्पोक मॉडल के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास।

कृषि एवं ग्रामीण विकास

2025

1. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:**

कथन I: भारत में, ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट-पालन और ऊन उत्पादन जैसे संवर्गी कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है।

कथन II: भारत में, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता है।

उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I की व्याख्या करता है।
(b) कथन I और कथन II दोनों सही हैं किंतु कथन II, कथन I की व्याख्या नहीं करता है।
(c) कथन I सही है किंतु कथन II सही नहीं है।
(d) कथन I सही नहीं है किंतु कथन II सही है।

सही उत्तर: (d)

व्याख्या:

- आयकर अधिनियम के अनुसार, केवल वही आयकर-मुक्त मानी जाती है जो प्रत्यक्ष तौर पर कृषि गतिविधियों (जैसे कि फसल कृषि) से प्राप्त होती है। सामान्यतया कृषि आय में केवल वे गतिविधियाँ शामिल हैं जो सीधे भूमि, पौधों की खेती और मृदा से जुड़ी हैं।
- कुक्कुट पालन (पोल्ट्री फार्मिंग), डेयरी उत्पादन, ऊन पालन जैसे संवर्गी कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय की कृषि आय नहीं माना जाता है और इस पर कर (Tax) लगाया जाता है। **अतः कथन I सही नहीं है।**
- आयकर अधिनियम की धारा 2(14) के अनुसार, ग्रामीण कृषि भूमि (Rural Agricultural Land) को पूंजीगत परिसंपत्ति (Capital Asset) की परिभाषा से बाहर रखा गया है। इसलिये यदि ऐसी भूमि को बेचा जाता है, तो उस पर होने वाला लाभ पूंजीगत लाभ कर के दायरे में नहीं आता है। **अतः कथन II सही है।**

अतः विकल्प (d) सही है।

2. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:**

I. यह ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादकता वाले देशज पशु छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के पास होते हैं।

II. इसे वैज्ञानिक रूप में और साकल्यवादी रूप में देशज गोपशु और भैंस के पालन और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिये आरंभ किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल I **(b) केवल II**
(c) I और II दोनों **(d) न तो I और न ही II**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या:

- राष्ट्रीय गोकुल मिशन (Rashtriya Gokul Mission - RGM) का क्रियान्वयन देशी गोवंशीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिये किया जा रहा है। यह योजना ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि 80% से अधिक न्यून उत्पादकता वाले देशज पशु छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के पास हैं। यह मिशन पशुओं की आनुवंशिक गुणवत्ता सुधार कर किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है जिससे ग्रामीण निर्धनों का आर्थिक उत्थान होता है। **अतः कथन I सही है।**
- यह योजना दुग्ध उत्पादन तथा गोवंशियों की उत्पादकता को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण है, जिससे दुग्ध की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके तथा ग्रामीण कृषकों के लिये डेयरी को अधिक लाभदायक बनाया जा सके।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की योजना है। यह मिशन दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देशज नस्लों का वैज्ञानिक तरीकों से संरक्षण और विकास करना है। इसमें केवल दुग्ध बढ़ाना ही शामिल नहीं है, बल्कि उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले पशुओं का संरक्षण, कृत्रिम समाधान की कवरेज बढ़ाना शामिल हैं। **इसलिये कथन II भी सही है।**

अतः विकल्प (c) सही है।

2024

1. **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:**

1. इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये, केंद्र सरकार 100% वित्त-पोषण करती है।
2. इस योजना के अंतर्गत, भूसंपत्ति (कैडस्ट्रल) मानचित्र डिजिटलीकृत किये जाते हैं।
3. स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: केंद्र सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (जिसे पहले राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था) को 1 अप्रैल, 2016 को पूर्णत: पुन: डिज़ाइन किया गया और साथ ही इसे केंद्रीय क्षेत्रक योजना बना दिया गया। **अत: कथन (1) सही है।**

- भूसंपत्ति (कैडस्ट्रल) मानचित्रों का डिजिटलीकरण DILRMP के प्रमुख घटकों एवं गतिविधियों में से एक है। **अत: कथन 2 सही है।**

क्र.सं.	घटक	गतिविधियाँ
1	भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण	**(i) अधिकारों के रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण; (ii)भूकर मानचित्रों का डिजिटलीकरण; (iii) अधिकारों के रिकॉर्ड (पाठ्य) और भूकर मानचित्र (स्थानिक) का एकीकरण; (iv) राज्य स्तर पर डाटा केंद्र।**
2	पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण	**(i) उप रजिस्ट्रार कार्यालयों (SRO) का कंप्यूटरीकरण; (ii) उप-पंजीयक कार्यालयों और तहसीलों के बीच कनेक्टिविटी; और (iii) पंजीकरण और भूमि अभिलेखों का एकीकरण।**
3	सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण	सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण और सर्वेक्षण एवं निपटान रिकॉर्ड को अद्यतन करना।
4	आधुनिक रिकार्ड रूम	तहसील स्तर पर आधुनिक रिकॉर्ड रूम/ भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन केंद्र।
5	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और/या राज्यों के सर्वेक्षण/राजस्व/पटवारी प्रशिक्षण संस्थानों में DILRMP कक्षों का निर्माण
6	परियोजना प्रबंधन इकाई	DILRMP के विभिन्न घटकों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सहायता प्रदान करने के लिये मानव संसाधन और अन्य बुनियादी ढाँचा प्रदान करना।
7	राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली का कंप्यूटरीकरण	देश के सभी राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण और भूमि अभिलेखों के साथ उनका एकीकरण।
8	स्वैच्छिक आधार पर भूमि रिकॉर्ड डाटाबेस के साथ आधार संख्या का एकीकरण	आधार नंबर को रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स (ROR) से जोड़ने के लिये।

- भूमि प्रशासन में भाषाई बाधाओं की समस्या का समाधान करने के लिये, सरकार ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) पुणे के तकनीकी सहयोग से, स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकारों के अभिलेखों को संविधान की अनुसूची VIII की 22 भाषाओं में से किसी एक में लिप्यंतरित (Transliterate) करने की पहल की है। **इसलिये कथन 3 सही है।**

अत: विकल्प (d) सही है।

2. निम्नलिखित में से कौन-सा "100 मिलियन किसानों" का सही विवरण है?

(a) यह नेट-शून्य (कार्बन), प्रकृति-सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज़ करने के लिये एक मंच है जिसका लक्ष्य किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है।

(b) यह जैविक पशुपालन के विकास को सहायता देने एवं सशक्त करने में इच्छुक व्यक्तियों और कृषि संगठनों का एक नेटवर्क और एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है।

(c) यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से सेवा प्रदाताओं के साथ एकीकृत है और ब्लॉक-चेन पर निर्मित है, जो क्रेताओं, विक्रेताओं तथा तीसरे पक्षकारों को शीघ्र एवं सुरक्षित रूप से उर्वरकों का व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है।

(d) यह एक मंच है जिसका ध्येय किसानों को कृषक उत्पाद संगठनों अथवा कृषि-व्यवसाय संघ बनाने के लिये प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें उनके उत्पादों को बेचने के लिये वैश्विक खुले बाज़ारों में पहुँच प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। *सही उत्तर:* (a)

व्याख्या:

- 100 मिलियन किसान (100 Million Farmers) विश्व आर्थिक मंच (WEF) की एक प्रमुख पहल है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर के 100 मिलियन किसानों को नेट ज़ीरो (Net-Zero) प्रकृति-सकारात्मक खाद्य प्रणालियों और पुनर्योजी कृषि की ओर संक्रमण को गति देने के लिये वित्तपोषण और सहयोग करना है।
- इसमें खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज़ करने के साहसिक उद्देश्य शामिल हैं जो **शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के साथ प्रकृति एवं कृषकों** के अनुकूल हो।
- **विश्व की कृषक आबादी** के **पाँचवें हिस्से** को लक्षित करते हुए, इस पहल का उद्देश्य एक सौ मिलियन किसानों तक पहुँचना है ताकि एक ऐसे महत्त्वपूर्ण पड़ाव तक पहुँचा जा सके जो **खाद्य और जल प्रणालियों के भविष्य को आकार** दे सके। **अत: विकल्प (a) सही है।**

2023

1. निम्नलिखित में से कौन-सा एक, 'लघु कृषक बड़े खेत' की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है?

(a) युद्ध के कारण अपने देशों से बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का, एक बड़ी खेतीयोग्य ज़मीन देकर, जिसमें वे सामूहिक खेती कर उपज को आपस में बाँटते हैं, पुनःस्थापन करना

(b) किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आपको समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समकालन और संगति लाते हैं

(c) किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक मिलकर किसी निगमित निकाय के साथ संविदा कर अपनी ज़मीन उस निगमित निकाय को किसी नियत अवधि के लिये दे देते हैं, जिसके लिये वह निगमित निकाय कृषकों को एक सहमत राशि का भुगतान करता है

(d) कोई कंपनी किसी क्षेत्र के कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण, तकनीकी जानकारियाँ और सामग्री की निविष्टियाँ प्रदान करती है, ताकि वे कंपनी की विनिर्माण प्रक्रिया और वाणिज्यिक उत्पादन के लिये उसकी ज़रूरत के कृषि-पण्य का उत्पादन करें

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: 'लघु कृषक बड़े खेत (Small Farms, Large Fields-SFLF)' एक ऐसा कृषि मॉडल है जिसे लाखों लघु एवं सीमांत किसानों को आपूर्ति शृंखला में होने वाली विसंगतियों एवं सौदेबाज़ी की शक्ति की कमी के कारण होने वाली क्षति को दूर करने के लिये लाया गया है। यह मॉडल सहभागी और लचीला है जिसके तहत किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक स्वयं को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि कार्यों में समक्रमिक (समकालन) और संगति लाते हैं। इसमें समूह के सभी किसान एक समय पर एक ही किस्म की फसल बोते हैं और समान कृषि पद्धतियों का पालन करते हैं। इससे छोटे-छोटे खेत मिलकर एक बड़े खेत की तरह व्यवहार करते है। **अतः विकल्प (b) सही है।**

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत सरकार काले तिल [नाइजर (गुइज़ोटिया एबिसिनिका)] के बीजों के लिये न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है।

2. काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है।

3. भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिये प्रयोग में लाते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक **(b) केवल दो**
(c) सभी तीन **(d) कोई भी नहीं**

सही उत्तर: (c)

- भारत सरकार काले तिल **[नाइजर (गुइज़ोटिया एबिसिनिका)]** के बीजों के लिये **न्यूनतम समर्थन कीमत** प्रदान करती है। **अतः कथन 1 सही है।**
- काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। **अतः कथन 2 सही है।**
- भारत में कुछ जनजातियाँ काले तिल के तेल का उपयोग खाना पकाने के लिये करती हैं इसके साथ ही तेल निकालने के उपरांत पशुओं के चारे के लिये खल तथा मसाले के रूप में भी इन बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। **अतः कथन 3 सही है।**

2022

1. भारत में "चाय बोर्ड" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है।

2. यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है।

3. चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बंगलूरू में स्थित है।

4. इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) 1 और 3 **(b) 2 और 4**
(c) 3 और 4 **(d) 1 और 4**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या:

- भारत में चाय बोर्ड की स्थापना चाय अधिनियम, 1953 के तहत की गई थी। चूँकि इसकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी। इसलिये यह एक सांविधिक निकाय है। **अतः कथन 1 सही है।**
- यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**
- इसका मुख्यालय कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में स्थित है। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**
- **विदेशों में कार्यालय:** वर्तमान में चाय बोर्ड के दो विदेशी कार्यालय (दुबई और मॉस्को में) हैं। बोर्ड के इन सभी विदेशी कार्यालयों को भारतीय चाय के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रचार उपायों के लिये डिज़ाइन किया गया है। ये कार्यालय संबंधित क्षेत्रों में भारतीय चाय के आयातकों के साथ-साथ भारतीय निर्यातकों के बीच बातचीत के लिये एक संपर्क कार्यालय के रूप में भी कार्य करते हैं। **इसलिये कथन 4 सही है।**

अतः विकल्प (d) सही है।

2020

1. भारत में, निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है।

1. सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना

2. प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण

3. सामाजिक पूंजी विकास

4. कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति

5. बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी

6. सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1, 2 और 5

(b) केवल 1, 3, 4 और 5

(c) केवल 2, 3 और 6

(d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत बुनियादी ढाँचा या अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में सरकार द्वारा निवेश किया जाता है। सरकार बुनियादी ढाँचे में निवेश करके देश की जनता को बेहतर सुविधाएँ और सेवाएँ प्रदान करती है। कृषि में किसी भी तरह की सब्सिडी सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत नहीं आती है। प्रश्नगत विकल्पों में कृषि में सार्वजनिक निवेश के तहत प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सरकार द्वारा शीतागार सुविधाओं की स्थापना तथा सामाजिक पूंजी विकास यानी कृषि व इससे संबंधित संस्थाओं के मध्य बेहतर समन्वय दीर्घकाल में कृषि के विकास को ही सुनिश्चित करेंगे। **अतः विकल्प (c) सही है।**

2. हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन-से कारक/कौन-सी नीतियाँ भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थीं?

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य

2. सरकार द्वारा व्यापार करना

3. सरकार द्वारा भंडारण करना

4. उपभोक्ता सहायिकियाँ (subsidies)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1, 2 और 4 **(b) केवल 1, 3 और 4**

(c) केवल 2 और 3 **(d) 1, 2, 3 और 4**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: प्रश्नगत सभी कारक किसी न किसी तरह (सकारात्मक अथवा नकारात्मक) चावल के मूल्य को प्रभावित करते हैं। उदाहरणस्वरूप सरकार द्वारा उपभोक्ता सहायिकी में बढ़ोतरी से उपभोक्ता कम कीमत पर चावल का क्रय कर सकते हैं, वहीं चावल का अधिक भंडारण इसकी कीमत को बढ़ा सकता है। **अतः विकल्प (d) सही है।**

3. 'किसान क्रेडिट कार्ड' योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किन-किन उद्देश्यों के लिये कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है?

1. फार्म परिसंपत्तियों के रख-रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिये

2. कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रकों के क्रय के लिये

3. फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिये

4. फसल कटाई के बाद खर्चों के लिये

5. परिवार के लिये घर निर्माण तथा गाँव में शीतागार सुविधा की स्थापना के लिये।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये

(a) केवल 1, 2 और 5 **(b) केवल 1, 3 और 4**

(c) केवल 2, 3, 4 और 5 **(d) 1, 2, 3, 4 और 5**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: किसान क्रेडिट कार्ड संस्थानिक ऋण तक किसानों की पहुँच सुनिश्चित करने की एक महत्त्वपूर्ण और प्रभावी पहल है। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को बहुत ही कम ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली से एकल खिड़की के तहत किसानों को लचीली और सरलीकृत क्रियाविधि से उनकी खेती और अन्य ज़रूरतों के लिये पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत निम्न उद्देश्यों के लिये ऋण उपलब्ध कराया जाता है–

- फसलों की खेती के लिये अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना
- फसलोत्तर खर्च
- कृषि उपज विपणन ऋण
- किसान की घरेलू खपत आवश्यकताएँ
- फार्म आस्तियों और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के रखरखाव के लिये कार्यशील पूंजी
- कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिये निवेश क्रेडिट की आवश्यकता अतः विकल्प (b) सही है।

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) पर प्रापण (खरीद) भारत के किसी भी राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश (यू.टी.) में असीमित होता है

2. अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाज़ार मूल्य कभी नहीं पहुँच पाते।

उपर्युक्त कथनों में से कौन/सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1, न ही 2**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह मूल्य होता है, जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिये तैयार रहती है। जब बाज़ार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है। सरकार इसकी घोषणा फसल बुवाई से पहले करती है। ध्यातव्य है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है। इस आयोग के द्वारा 22 कृषि फसलों (सभी फसलों के लिये नहीं) के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किये जाते हैं। चूँकि बाज़ार मूल्य का निर्धारण मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर निर्भर करता है इसलिये वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम या अधिक दोनों हो सकता है। **अतः विकल्प (d) सही है।**

2019

1. **स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?**

(a) हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर।

(b) भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था।

(c) इसके परिणामस्वरूप नकदी फसलों की खेती, कृषि का प्रमुख रूप बन गई।

(d) भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी।

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: स्वतंत्रता उपरांत भारत में कृषि के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया। इसमें काश्तकारी कानून को अधिनियमित करने व ज़मींदारी प्रथा को समाप्त करने से भूमिहीन किसानों को भी भूमि प्राप्त हो सकी, जिससे वे अपनी आजीविका चलाने में सक्षम हुए।

नोट: भूमि राज्य सूची का विषय है।

2. **भारतीय खाद्य निगम के लिये खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किये गए बोनस (यदि कुछ है) के साथ-साथ और क्या शामिल है/हैं?**

(a) केवल परिवहन लागत

(b) केवल ब्याज लागत

(c) प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत

(d) प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा गोदामों के प्रभार

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: भारतीय खाद्य निगम (FCI) के लिये खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और किसानों को भुगतान किये गए बोनस के साथ-साथ प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स और डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट शामिल हैं।

आर्थिक लागत = किसानों को देय न्यूनतम समर्थन मूल्य + खरीद संबंधी सहायक खर्च + वितरण लागत

3. **भारत द्वारा आयातित कृषि जिंसों में, पिछले पाँच वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है?**

(a) मसाले

(b) ताज़े फल

(c) दलहन

(d) वनस्पति तेल

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, मूल्य के आधार पर वनस्पति तेल पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक आयातित कृषि वस्तु है।

2018

1. **निम्नलिखित पर विचार कीजिये-**

1. सुपारी **2. जौ**

3. कॉफी **4. रागी**

5. मूंगफली **6. तिल**

7. हल्दी

उपर्युक्त में से किनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की है?

(a) केवल 1, 2, 3 और 7 **(b) केवल 2, 4, 5 और 6**

(c) केवल 1, 3, 4, 5 और 6 **(d) 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: वर्ष 2018–19 के लिये आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। इनमें जौ, चना, मसूर, रैपसीड तथा गेहूँ जैसी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले से 1.5 गुना अधिक है। वहीं, रागी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 54% (2931.2 रुपये/क्विंटल) की वृद्धि होगी।

मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 17.10% की वृद्धि के साथ 4975.4 रुपये/क्विंटल, जबकि तिल (सीसमम) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 23.20% की वृद्धि के साथ 6405.5 रुपये/क्विंटल रहने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि ज्वार, रागी तथा तिल कुछ ऐसी फसलें हैं, जिनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में केवल लागत को कवर किया जाता है। न्यूनतम

समर्थन मूल्य (MSP), वह न्यूनतम मूल्य होता है, जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिये तैयार रहती है। इसके अंतर्गत जब बाज़ार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा होता है, तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीदकर उनके हितों की रक्षा करती है। सरकार इस न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बोने से पूर्व करती है। कृषि लागत व मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है।

- वर्तमान में 22 फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, जिसमें-
  - सात अनाज (धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का व रागी)
  - पाँच दालें (अरहर, मूंग, चना, उड़द और मसूर)
  - सात तिलहन (सरसों/तोरिया, मूंगफली, सोयाबीन के बीज, सूरजमुखी, काला तिल, कुसुम, नाइजर सीड); तीन अन्य फसलें कोपरा (सूखा नारियल), कपास तथा कच्चा पटसन सम्मिलित हैं।

2. भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. 'जैविक उत्पादन के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम' (एन.पी.ओ.पी.) केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निदेश के अधीन कार्य करता है।

2. एन.पी.ओ.पी. के क्रियान्वयन के लिये 'कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण' (APEDA) सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

3. सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: **(b)**

व्याख्या: जैविक कृषि (ऑर्गेनिक फार्मिंग), कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिये फसल चक्र, हरी खाद, कम्पोस्ट आदि का प्रयोग करती है। सन् 1990 के बाद से विश्व में जैविक उत्पादों का बाज़ार वर्तमान में काफी बढ़ गया है। प्रश्न में दिया गया कथन-1 सही नहीं है क्योंकि जैविक उत्पादन के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी.) केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य नहीं करता है बल्कि यह वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जैविक कृषि के केंद्रीय व सुव्यवस्थित विकास हेतु भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सन् 2001 में अपने उपक्रम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिये एन.पी.ओ.पी. (NPOP) की शुरुआत की गई। इस प्रमाणीकरण व्यवस्था के तहत एन.पी.ओ.पी. द्वारा सफल प्रसंस्करण इकाइयों, भंडारों और खेतों को इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो प्रदान कराया जाता है। वर्ष 2016 में सिक्किम देश का पहला पूर्णत: जैविक राज्य बन गया है। अत: प्रश्न में दिये गए कथन 2 एवं 3 सही हैं।

2017

1. 'राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट)' स्कीम को क्रियान्वित करने का/के क्या लाभ है/हैं?

1. यह कृषि वस्तुओं के लिये सर्व-भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है।

2. यह कृषकों के लिये राष्ट्रव्यापी बाज़ार सुलभ कराता है जिसमें उनके उत्पाद की गुणता के अनुरूप कीमत मिलती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**
(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1, न ही 2**

सही उत्तर: **(c)**

व्याख्या:

- राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) एक सर्व-भारतीय (पैन-इंडिया) इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण करने के लिये मौजूदा ए.पी.एम.सी. मंडी का एक प्रसार है।
- राष्ट्रीय कृषि बाज़ार कृषकों को बाज़ार सुलभ कराता है तथा उपज की गुणवत्ता के अनुरूप मूल्यों को तय करने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म भी सुनिश्चित करता है ताकि उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों को उचित मूल्य पर उत्पादन उपलब्ध हो सके।

2016

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर दो प्रतिशत की एकसमान दर से बीमा किश्त का भुगतान करना होगा।

2. यह योजना, चक्रवात एवं गैर-मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई-उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**
(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1 और न ही 2**

सही उत्तर: **(b)**

व्याख्या: सभी किसानों को खरीफ फसलों के लिये 2% की एक समान दर से प्रीमियम भुगतान करना होगा तथा सभी रबी फसलों के लिये 1.5% की दर से। वाणिज्यिक और बागानी फसलों के लिये यह दर 5% रहेगी। इसलिये सही उत्तर (b) है।

इस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किसानों का उनकी फसल के लिये बीमा करवाया जाएगा जिसमें प्रीमियम दर बहुत कम कर दी गई है। इससे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा तथा आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति पर अंकुश लग सकेगा। इस योजना में किसानों द्वारा कम प्रीमियम राशि देने के बावजूद फसल नुकसान पर उचित हर्ज़ाना दिया जाएगा और पहले की तुलना में आपदा सूची अथवा श्रेणियों का भी विस्तार कर दिया गया है।

2. 'गहन कदन्न संवर्द्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल (Initiative for Nutritional Security through Intensive Millets Promotion)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई-उपरांत प्रौद्योगिकियों को निदर्शित करना है एवं समूह उपागम (क्लस्टर अप्रोच) के साथ एकीकृत रीति से मूल्य वर्द्धन तकनीकों को निदर्शित करना है।

2. इस योजना में निर्धन, लघु, सीमांत एवं जनजातीय किसानों की बड़ी हितधारिता (स्टेक) है।

3. इस योजना का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को, पोषकों के अत्यावश्यक निवेशों के और लघु सिंचाई उपकरणों के नि:शुल्क किट प्रदान कर, कदन्न की खेती की ओर प्रोत्साहित करना है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 2

(d) 1, 2 और 3 *सही उत्तर:* (c)

व्याख्या: 'गहन कदन्न संवर्द्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल' 2011–12 में राष्ट्रीय कृषि विकास के तहत मोटे अनाज के विकास हेतु 300 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ हुई। ज्ञात है कि मोटा अनाज, यथा जौ, चना आदि मानव की उत्पत्ति के समय जैसे ही पुराने है और पोषण से युक्त हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य नवीन अनुसंधान एवं तकनीकी विकास के माध्यम से मोटे अनाजों का विकास करना तथा भोज्य पदार्थ के रूप में आम जीवनशैली में शामिल करना है। साथ ही सरकार का प्रयास है कि मोटे अनाज उत्पादन को व्यावसायिक दृष्टि से लाभप्रद बनाया जाए।

इस योजना में किसानों को पोषक तत्त्वों के संरक्षण, जैव उर्वरकों, यूरिया इत्यादि के लिये सहायता प्रदान की जाएगी। किंतु इस योजना में लघु सिंचाई उपकरणों के लिये नि:शुल्क सहायता का प्रावधान नहीं है। अत: कथन 3 गलत है।

2015

1. गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत (FRP) को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता/करती है?

(a) आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति

(b) कृषि लागत और कीमत आयोग

(c) कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय

(d) कृषि उत्पाद विपणन समिति *सही उत्तर:* (a)

व्याख्या: गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत (FRP) की सिफारिश कृषि लागत और कीमत आयोग (CACP) द्वारा की जाती है, लेकिन इसका अनुमोदन केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है।

- गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में 22 अक्तूबर, 2009 को संशोधन कर गन्ने के लिये सांविधिक न्यूनतम कीमत (SMP) के स्थान पर 'गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत' पद्धति की शुरुआत की गई, जिसकी उद्घोषणा और निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ही करती है। औद्योगिक कच्चे पदार्थों व उत्पादों का मूल्य नियंत्रण, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, संयुक्त क्षेत्र उपक्रम के गठन के लिये औद्योगिक लाइसेंसिंग के मामले, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निष्पादनों की समीक्षा, उनके संरचनात्मक व वित्तीय पुनर्संरचना से जुड़े मामले इस समिति की निगरानी के अंतर्गत आते हैं।

2. भारत में कृषि उत्पादों के बाज़ार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है?

(a) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

(b) राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम

(c) कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) अधिनियम, 1937

(d) खाद्य उत्पाद आदेश, 1956 एवं माँस तथा खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 *सही उत्तर:* (b)

व्याख्या: भारत में कृषि उत्पादों के बाज़ार को राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम (APMC Act) के अधीन विनियमित किया जाता है। अत: विकल्प (b) सही है। एपीएमसी कानून के तहत कृषि को राज्य सूची के प्रमुख मुद्दे के रूप में अपनाया गया है। यह एक्ट राज्य सरकारों को वस्तुओं को अधिसूचित करने हेतु सशक्त करता है एवं APMC बाज़ारों (मंडियों) के गठन का अधिकार देता है।

3. कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है?

(a) श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकीय (टेक्नोलॉजिकल) प्रगति

(b) पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकीय प्रगति

(c) पूंजी घटाने वाली प्रौद्योगिकीय प्रगति

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं। *सही उत्तर:* (b)

व्याख्या: प्रारंभिक उपकरण से उन्नत उपकरण की ओर अंतरण प्रौद्योगिकीय प्रगति का उदाहरण है। इसके साथ-साथ नई तकनीकों को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तथा यह श्रम का स्थानापन्न है। अत: कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों के स्थान पर इस्पात के हल का उपयोग पूंजी संवर्द्धनकारी प्रौद्योगिक प्रगति का एक उदाहरण है।

2014

1. भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की 'बीज प्रतिस्थापन दरों' को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े/विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता है/बाध्यताएँ हैं?

1. कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है।

2. निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की, उद्यान-कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है।

3. निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणता वाले बीजों के बारे में मांग-पूर्ति अंतराल है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) 1 और 2 **(b) केवल 3**

(c) 2 और 3 **(d) कोई नहीं**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: राष्ट्रीय बीज नीति, 2002 स्पष्ट रूप से बीजों के उत्पादन के बारे में मानकों का निर्धारण करती है। अत: कथन (1) गलत है।

राष्ट्रीय बीज नीति, 2002 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन व आपूर्ति में निजी क्षेत्र के बीज उद्योग अथवा बीज कंपनियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसी के अनुरूप निजी क्षेत्र की बीज कंपनियाँ आज उच्च मूल्य और निम्न परिमाण (High Value and Low Volume) वाली फसलों, जैसे- **सब्जियाँ, फूल, उद्यान कृषि फसल (Horticulture Crops)**, कुछ अनाजों तथा नकदी फसलों के हाइब्रिड और आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलों के मामले में बीजों की पूर्ति में महत्त्वपूर्ण रूप से सहभागिता कर नेतृत्वकारी भूमिका निभा रही हैं। अत: कथन (2) गलत है।

कथन (3) सही है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणता वाले बीजों के विकास, उत्पादन और वितरण प्रणाली में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है। भारत में निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणता वाले बीजों के बारे में मांग-पूर्ति अंतराल है। प्रमाणित (Certified) व गुणता वाले बीजों (Quality seeds) के मांग-आपूर्ति अंतराल के चलते भारत में बीज प्रतिस्थापन दर निम्न बनी हुई है। निम्न मूल्य व उच्च परिमाण वाली फसलों, जैसे- चावल व गेहूँ के मामले में भारत में प्रमाणित व गुणता वाले बीजों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाई है। फलों, सब्जियों व फूलों के संदर्भ में ऐसा नहीं है।

2012

1. 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है?

1. ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करके

2. 'स्वयं सहायता समूहों' को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएँ प्रदान करके

3. कृषकों को नि:शुल्क बीज, उर्वरक, डीजल पम्पसेट तथा लघु सिंचाई संयंत्र देकर

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 2**

(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का शुभारंभ ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जून 2011 में विश्व बैंक के सहयोग से किया गया। मिशन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- ग्रामीण निर्धनों के लिये सक्षम और प्रभावी संस्थागत प्लेटफॉर्म तैयार करना ताकि वे सतत् आजीविका बढ़ोतरी और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में सुधार का उपयोग अपनी हाउसहोल्ड आय में वृद्धि के लिये कर सकें।
- मिशन में कौशल विकास की सुविधा उपलब्ध कराना ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने के लिये आवश्यक माना गया है। इस मिशन का नया नाम 'आजीविका' है।

2. भारत में 'औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक' में आठ मूल उद्योगों के सूचकांकों का संयुक्त भार 37.90% है। निम्नलिखित में से कौन-से उद्योग उन आठ मूल उद्योगों में सम्मिलित हैं?

1. सीमेंट **2. उर्वरक**

3. प्राकृतिक गैस **4. रिफाइनरी उत्पाद**

5. वस्त्रोद्योग

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 और 5 **(b) केवल 2, 3 और 4**

(c) केवल 1, 2, 3 और 4 **(d) 1, 2, 3, 4 और 5**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं के माप का तरीका है। इसमें खनन-उत्खनन, विनिर्माण तथा विद्युत क्षेत्र से संबंधित मदों को शामिल किया जाता है। 10 जून, 2011 को केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने 1993-94 आधार वर्ष के स्थान पर 2004-05 को नया आधार वर्ष मानते हुए नया औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया था। इसके तहत 8 मूल उद्योगों को सम्मिलित किया गया है। हालाँकि वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है।

मूल उद्योग

विद्युत, इस्पात (धातु एवं गैर-धातु), पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, क्रूड ऑयल (अशोधित तेल), कोयला, सीमेंट, उर्वरक, प्राकृतिक गैस।

3. ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDAs) भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करते हैं?

1. DRDAs देश के कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं।

2. DRDAs विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उनके समाधान के विस्तृत उपाय तैयार करते हैं।

3. DRDAs निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतरक्षेत्रीय (इंटर-सेक्टोरल) तथा अंतरविभागीय समन्वय और सहयोग सुरक्षित करते हैं।

4. DRDAs निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों के लिये मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 **(b) केवल 3 और 4**

(c) केवल 4 **(d) 1, 2, 3 और 4**

सही उत्तर: **(b)**

व्याख्या: ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण का गठन मूल रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) के क्रियान्वयन के लिये किया गया था। ये अभिकरण निम्नांकित रूपों में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में मदद करते हैं:

- निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करके।
- विभिन्न अन्य अभिकरणों व विभागों, जैसे- पंचायती राज संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ प्रभावी तरीके से समन्वय स्थापित करना ताकि ज़िला स्तर पर निर्धनता उन्मूलन के लिये आवश्यक संसाधन व समर्थन प्राप्त किया जा सके।
- यह केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है।
- निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों के लिये मिले कोष के प्रभावी और निष्पक्ष उपयोग पर निगरानी तथा पारदर्शिता।
- ग्रामीण विकास व निर्धनता उन्मूलन के संबंध में जागरूकता स्तर में सुधार को सुनिश्चित करना।
- रिपोर्टिंग व क्षेत्र भ्रमणों (field visits) के ज़रिये कार्यक्रमों पर सुदृढ़ निगरानी रखते हैं। ये अभिकरण ज़िला परिषद, केंद्र व राज्य सरकार को निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में निश्चित अवधि पर सूचना देकर अवगत कराते रहते हैं।
- ज़िले के लिये निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों हेतु हस्तांतरित सभी कोषों की प्रभावी उपयोगिता सुनिश्चित करना।

2011

1. निम्नलिखित में से कौन 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम' के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है?

(a) केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के वयस्क सदस्य

(b) गरीबी रेखा से नीचे के (BPL) परिवारों के वयस्क सदस्य

(c) सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य

(d) किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य *सही उत्तर:* **(d)**

व्याख्या: 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम' को यह नाम 2 अक्तूबर, 2009 को मिला। इसके पूर्व यह नरेगा के नाम से जाना जाता था जिसकी शुरुआत 2 फरवरी, 2006 को की गई थी। यह योजना भारत में बिना वर्गीय भेदभाव किये प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिवसों की गारण्टीशुदा मज़दूरी/रोज़गार प्रदान करती है।

2. भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है?

(a) वाणिज्यिक बैंकों की

(b) सहकारी बैंकों की

(c) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की

(d) सूक्ष्म-वित्त (माइक्रोफाइनेंस) संस्थाओं की

सही उत्तर: **(a)**

व्याख्या: वर्ष 2009-10 की समयावधि से ही कृषि क्षेत्र को संस्थागत ऋणों के प्रवाह में निरंतर वृद्धि होती रही है। कृषि को ऋण प्रवाह का एजेंसीवार हिस्सा यह दर्शाता है कि 2011-12 में वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा सर्वाधिक (72.13 प्रतिशत) रहा है, उसके बाद सहकारी बैंकों (17.2 प्रतिशत) और ग्रामीण बैंक (10.65 प्रतिशत) का स्थान आता है। पिछले वर्षों के दौरान संस्थागत क्रेडिट प्रवाह में सहकारी बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों के हिस्से में वृद्धि हुई है जो इन बैंकों की पुनर्संरचना और सुधार की आवश्यकता की ओर संकेत करता है।

मुद्रास्फीति

2022

1. भारत में, निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिये उत्तरदायी है?

(a) उपभोक्ता मामले विभाग

(b) व्यय प्रबंधन आयोग

(c) वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद्

(d) भारतीय रिज़र्व बैंक

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: भारत में कीमतों में स्थिरता बनाए रखना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना प्राथमिक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक की ज़िम्मेदारी है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) में मौद्रिक नीति के संचालन की ज़िम्मेदारी निहित है। यह ज़िम्मेदारी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत अनिवार्य है।
- मई 2016 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 को लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे (Flexible Inflation Targeting Framework) के कार्यान्वयन के लिये एक वैधानिक आधार प्रदान करने हेतु संशोधित किया गया था। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये निर्णय लेने का कार्य मौद्रिक नीति समीति (MPC) करती है। इसकी अध्यक्षता RBI के गवर्नर करते हैं। **अतः विकल्प (d) सही है।**

2. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद सकता है।

2. यदि रुपये का तेज़ी से मूल्यह्रास हो रहा है, तो RBI बाज़ार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है।

3. यदि USA या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होतीं, तो इससे संभावित रूप से RBI की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 2 और 3**

(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या:

- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये, भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रा बाज़ार में प्रतिभूतियों को बेचता है जो बाज़ार से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करता है। **अतः कथन (1) सही नहीं है।**
- जब रुपये का मूल्य तेज़ी से गिरता है यदि भारतीय रिज़र्व बैंक डॉलर की आपूर्ति को बढ़ा देता है। अर्थात् रुपये को स्थिरता प्रदान करने के लिये RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलरों का विक्रय शुरू कर देता है। **अतः कथन (2) सही है।**
- अमेरिका या यूरोपीय संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जैसी ही ब्याज दरें गिरती है तो उसका प्रभाव भारत जैसे अन्य देशों के बाज़ारों में डॉलर की खरीद पर पड़ता है। इससे भारत में डॉलर का प्रवाह बहुत बढ़ जाएगा, जिससे रुपया अधिक मज़बूत होने लगेगा। **इसलिये कथन (3) सही है।**

अतः विकल्प (b) सही है।

2021

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से

1. विदेशी बाज़ारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है।

2. घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है।

3. व्यापार संतुलन में सुधार लाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) 1 और 2**

(c) केवल 3 **(d) 2 और 3**

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: मुद्रा के अवमूल्यन से घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के मूल्य की तुलना में कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप घरेलू निर्यात सस्ता और आयात महँगा हो जाता है। सस्ता घरेलू निर्यात विदेशी बाज़ार में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करता है। अतः कथन (1) सही है।

- स्थिर विनियम दर प्रणाली (इसके साथ ही प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली) के अंतर्गत, जब किसी सरकारी कार्रवाई द्वारा विनिमय दर बढ़ती है अर्थात् घरेलू मुद्रा, विदेशी मुद्रा की तुलना में सस्ती हो जाती है तो इसे मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है। अतः कथन (2) सही नहीं है।
- व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि में किसी देश की वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के बीच का अंतर है। मुद्रा के अवमूल्यन के साथ निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होता है किंतु व्यापार संतुलन निर्यात और आयात दोनों पर निर्भर करता है और यह अनिवार्य नहीं है कि मुद्रा के अवमूल्यन से व्यापार संतुलन में सुधार हो। अतः कथन (3) सही नहीं है।
- **अतः विकल्प (a) सही है।**

2. निम्नलिखित में से कौन-सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीतिकारक हो सकता है?

(a) सार्वजनिक ऋण की चुकौती

(b) बजट घाटे के वित्तीयन के लिये जनता से उधार लेना

(c) बजट घाटे के वित्तीयन के लिये बैंकों से उधार लेना

(d) बजट घाटे के वित्तीयन के लिये नई मुद्रा का सृजन करना

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: सार्वजनिक ऋण की चुकौती से बाज़ार में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि ज़रूर होती है और इसमें स्फीतिकारी प्रभाव की संभावना भी रहती है किंतु सार्वजनिक ऋण की चुकौती से सरकार की सार्वजनिक व्यय करने की क्षमता कम होने की संभावना रहती है जो स्फीतिकारी प्रभाव को संतुलित भी कर सकता है। अतः विकल्प (a) सही नहीं होगा।

- किसी भी कदम को स्फीतिकारी (inflationary) तब माना जाता है जब उसके परिणामस्वरूप बाज़ार में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है। विकल्प (b) और (c) सही नहीं हैं क्योंकि बजट घाटे के वित्तीयन के लिये जनता से उधार अथवा बैंकों से उधार लेने का अर्थ है बाज़ार से तरलता खींचना, न कि बढ़ाना।
- लेकिन सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की दृष्टि से विकल्प (d) सही है, क्योंकि नई मुद्रा सर्वाधिक तरल होती है एवं यह वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन में कोई वृद्धि किये बिना ही अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि कर देती है।

2020

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. खाद्य वस्तुओं का 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (CPI) में भार (Weightage) उनके 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) में दिये गए भार से अधिक है।

2. WPI, सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता, जैसा कि CPI करता है।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: थोक मूल्य सूचकांक वस्तुओं के थोक मूल्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। उपभोक्त मूल्य सूचकांक उपभोक्ताओं के स्तर पर लोगों द्वारा प्रतिदिन उपभोग में लाई जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का भारांश लगभग 39.1 प्रतिशत है जो कि थोक मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं के भारांश 24.4 प्रतिशत से अधिक है। अतः कथन (1) सही है। थोक मूल्य सूचकांक समूह में सेवाएँ शामिल नहीं की गई हैं जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। अतः कथन (2) सही है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति की गणना के लिये तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। अतः कथन (3) सही नहीं है। **अतः विकल्प (a) सही है।**

2015

1. भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है?

(a) भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है।

(b) मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिज़र्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है।

(c) घटा हुआ मुद्रा परिचलन (मनी सर्कुलेशन) मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है।

(d) बढ़ा हुआ मुद्रा परिचलन, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है।

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: घटा हुआ मुद्रा परिचलन (मनी सर्कुलेशन) मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। विकल्प (a) तथा (b) गलत हैं, क्योंकि सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक दोनों क्रमशः अपनी राजस्व नीति एवं मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का प्रयास करते हैं। विकल्प (d) भी असत्य है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि के बिना मुद्रा प्रसार में वृद्धि से तरलता बढ़ने के चलते स्फीतिकारी दबाव बढ़ जाता है और मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता नहीं मिल पाती। **अतः विकल्प (c) सही है,** क्योंकि मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा आपूर्ति में कमी के प्रयास किये जाते हैं।

2. निम्नलिखित में से कौन 'औद्योगिक कर्मकारों के लिये उपभोक्ता कीमत सूचकांक (कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स नम्बर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स)' निकालता है?

(a) भारतीय रिज़र्व बैंक

(b) आर्थिक कार्य विभाग

(c) श्रम ब्यूरो

(d) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: औद्योगिक कर्मकारों के लिये उपभोक्ता कीमत सूचकांक (कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स) श्रम ब्यूरो द्वारा निकाला जाता है। 1958-59 से श्रम और रोज़गार मंत्रालय के तहत

संलग्न कार्यालय के रूप में श्रम ब्यूरो इस सूचकांक का संकलन करता है। वर्तमान में इसका आधार वर्ष 2016 है। **अत: विकल्प (c) सही है।**

2013

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुँचाती है।

2. मुद्रास्फीति बॉण्डधारकों को लाभ पहुँचाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1 और न ही 2**

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: मुद्रास्फीति के चलते क्रयशक्ति में कमी के कारण ऋणदाता वर्ग (Lender) हानि की स्थिति में होता है जबकि ऋणी (Debtors) को लाभ प्राप्त होता है। क्रयशक्ति में गिरावट के कारण ऋणदाता को जो ब्याज तथा मूलधन के रूप में रुपया मिलता है, उसकी क्रयशक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। इसलिये ऋणदाता को हानि होती है पर ऋणी को लाभ होता है क्योंकि वस्तु के रूप में उन्हें कम ही भुगतान देना पड़ता है।

विकल्प (b) सही नहीं है, क्योंकि मुद्रास्फीति सामान्य बॉण्डधारकों को लाभ नहीं पहुँचाती। बॉण्डधारक से आशय है- जिन्होंने बॉण्ड के एवज़ में रुपया (कोई भी मुद्रा) उधार दे दिया है। मुद्रास्फीति की दशा में ये नुकसान की स्थिति में रहेंगे। अत: विकल्प (b) गलत है। मुद्रास्फीति मुद्रा/धन की क्रय शक्ति को कमज़ोर कर देती है। अधिकांश ऋण उत्पाद (Debt Products), जैसे- सावधि जमा (Fixed deposits) अथवा नियमित बॉण्ड (Regular Bonds) जो रिटर्न प्रदान करते हैं, वे मुद्रास्फीति के संदर्भ में संरक्षित नहीं होते।

2. सामान्य कीमत-स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस/किन कारण/कारणों से हो सकती है/हैं?

1. द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि

2. उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट

3. प्रभावी मांग में वृद्धि

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 1 और 2**

(c) केवल 2 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहते हैं जब वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप मुद्रा की क्रय क्षमता में गिरावट आ जाती है।

- वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी के कारण मूल्य स्तर में वृद्धि आए तो इसे लागतजन्य स्फीति कहते हैं। दूसरे शब्दों में, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट से आपूर्ति शृंखला बाधित होगी, जबकि मांग बनी रहती है, अत: कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में द्रव्य आपूर्ति (Money Supply) में वृद्धि मांगजनित मुद्रास्फीति को प्रेरित करती है। वस्तुत: इस दशा में मुद्रा आधिक्य के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग में वृद्धि हो जाती है, जिससे कीमत स्तर में वृद्धि होती है। अत: कथन 1 सही है।
- उत्पादन स्तर में गिरावट का अर्थ है- वर्तमान मांग को पूरा न कर पाना। ज़ाहिर है, यह स्थिति भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का उदाहरण है। अत: कथन 2 भी सही है।
- प्रभावी मांग, वह वास्तविक मांग है जिसके अंतर्गत क्रेता, वस्तुओं एवं सेवाओं की वर्तमान बाज़ार मूल्यों पर वास्तविक खरीदारी करता है। इस वास्तविक खरीदारी से वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है। अत: कथन 3 सही है।

3. द्रव्य की पूर्ति यथावत् रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है, तो

(a) कीमत-स्तर में गिरावट आ जाएगी

(b) ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी

(c) ब्याज की दर में कमी हो जाएगी

(d) आय और रोज़गार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: सामान्य कीमत दर स्थिर बने रहने के लिये मांग और पूर्ति दोनों पक्षों में संतुलन बना रहना आवश्यक होता है। विचारणीय है कि द्रव्य की पूर्ति यथावत् हो, जबकि मांग आधिक्य हो तो कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती जाती है। **अत: विकल्प (a) गलत है।**

- द्रव्य की मांग में वृद्धि एक ऐसी स्थिति है जो बाज़ार में तरलता (liquidity) के संकट को पैदा कर सकती है, जिससे स्फीतिजन्य प्रभाव (Inflationary Impact) दिखना शुरू हो जाएगा।
- दूसरे शब्दों में, कीमत स्तर में वृद्धि अथवा मुद्रास्फीति की स्थिति सामने आ सकती है। इस स्थिति को न आने देने के लिये केंद्रीय बैंक ब्याज की दर में वृद्धि कर देगा जिससे ऋण महँगा हो जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि द्रव्य की मांग में वृद्धि से ब्याज दर में कमी नहीं होगी क्योंकि ब्याज दर में कमी मुद्रा की मांग को और बढ़ाएगी जिससे तरलता की समस्या आ सकती है। **अत: विकल्प (c) गलत है।**
- द्रव्य की मांग (Money demand) में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंक ब्याज दर इसलिये भी बढ़ा देंगे क्योंकि मुद्रा तो सीमित है लेकिन उसकी मांग करने वाले बहुत हैं। **अत: विकल्प (b) सही है।**

4. निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है?

(a) लोक ऋण की चुकौती

(b) बजट घाटे के वित्तीयन के लिये जनता से ऋणादान

(c) बजट घाटे के वित्तीयन के लिये बैंकों से ऋणादान

(d) बजट घाटे के वित्तीयन के लिये नई मुद्रा का सृजन

सही उत्तर: (d)

व्याख्या:

- कोई भी कदम स्फीतिकारी तब होगा जब उसके परिणामस्वरूप बाज़ार में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती हो। अत: विकल्प (b) और (c) सही नहीं हैं, क्योंकि जनता से ऋणादान अथवा बैंकों से ऋणादान करने का मतलब है बाज़ार से तरलता खींचना, न कि बढ़ाना।
- लोक ऋण की चुकौती से यद्यपि बाज़ार में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है और इसमें स्फीतिकारी प्रभाव की संभावना है लेकिन सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की दृष्टि से विकल्प (d) सही है, क्योंकि नई मुद्रा सर्वाधिक तरल होती है एवं यह वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन में कोई वृद्धि किये बिना ही अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कर देती है।

2012

1. निम्नलिखित उपायों में से किसके/किनके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी?

1. केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय
2. लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी
3. सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण
4. केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 **(b) केवल 2 और 4**
(c) केवल 1 और 3 **(d) 2, 3 और 4**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय से बाज़ार में मुद्रा पूर्ति अथवा तरलता बढ़ेगी क्योंकि प्रतिभूतियों के बदले पैसा दिया जा रहा है जबकि लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई मुद्रा से तरलता अथवा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि नहीं होती क्योंकि मुद्रा बाज़ार में नहीं आ रही है बल्कि जमा की जा रही है। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि में सहायक होगा क्योंकि सरकार इस मुद्रा को विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बाज़ार में व्यय करेगी। अत: मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगी।

2011

1. हाल के वर्षों में भारत निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति से गुज़रा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं?

1. उत्तरोत्तर वाणिज्यिक फसलों की खेती में प्रयुक्त होने के कारण खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र विगत पाँच वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30 प्रतिशत घट गया है।
2. बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूप में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं।
3. आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 2 और 3**
(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: सब्ज़ियों, फलों, दूध, अंडा, मांस और मछली के उपभोग में वृद्धि के चलते खाद्यान्न मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। हाल के वर्षों में भारत में निरंतर उच्च खाद्य स्फीति के निम्नलिखित कारण रहे हैं-

- पिछले कुछ वर्षों में खाद्य मुद्रास्फीति संरचनागत और मौसमी कारकों का परिणाम रही है।
- वितरण चैनलों में मौजूद अक्षमता तथा खाद्य वस्तुओं की बर्बादी व नष्ट होना उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण रहे।
- कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के प्रावधान भी इसके लिये ज़िम्मेदार रहे।
- खाद्य वस्तुओं के वितरण में बिचौलियों के स्तर से समस्या।
- मनरेगा के चलते ग्रामीण मज़दूरी में वृद्धि से हुई आय में वृद्धि ने भी उपभोग प्रतिरूप में बदलाव लाकर खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई तरह की खामियों के चलते आहार की आपूर्ति श्रृंखला में संरचनात्मक अवरोध देखे गए।

2. स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप्य कभी-कभी 'आधार प्रभाव' (Base Effect) पर लगाया जाता है। यह 'आधार प्रभाव' क्या है?

(a) यह फसलों के खराब होने से आपूर्ति में उत्पन्न उग्र अभाव का प्रभाव है
(b) यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेज़ी से बढ़ रही मांग का प्रभाव है
(c) यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है
(d) इस संदर्भ में उपर्युक्त (a), (b) तथा (c) कथनों में से कोई भी सही नहीं है

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: मुद्रास्फीति के संदर्भ में आधार प्रभाव (Base effect) विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आए प्रभाव को दर्शाता है। आधार प्रभाव से मुद्रास्फीति की सटीक तस्वीर सामने नहीं आ पाती। यदि विगत वर्ष में मुद्रास्फीति दर काफी कम भी हो, तो भी मुद्रास्फीति के प्राइस इंडेक्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी होने पर गणितीय ढंग से अगले वर्ष में मुद्रास्फीति का उच्च स्तर सामने आता है। आधार प्रभाव की यही विकृति (distortion) होती है।

3. आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है-

(a) अवस्फीति के साथ **(b) स्फीति के साथ**
(c) स्टैगफ्लेशन के साथ **(d) अतिस्फीति के साथ**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: आर्थिक संवृद्धि सामान्यतया पूंजी निर्माण, बचत, निवेश, मांग और आपूर्ति शृंखला में संतुलन, आयात-निर्यात आदि कारकों से संचालित होती है। संवृद्धि के लिये समस्त आर्थिक गतिविधियाँ बाज़ार में संपन्न की जाती हैं और वो भी मुद्रा के साथ। बाज़ार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि लेकिन आपूर्ति में कमी की स्थिति व कुछ अन्य कारक, वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर महँगाई की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। इस रूप में मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है।

अर्थव्यवस्था से संबंधित विविध विषय

2025

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

कथन I: चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है।

कथन II: चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है।

कथन III: चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) कथन II और कथन III दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन I की व्याख्या करते हैं

(b) कथन II और कथन III दोनों सही हैं किंतु उनमें से केवल एक, कथन I की व्याख्या करता है

(c) कथन II और कथन III में से केवल एक सही है तथा वह कथन I की व्याख्या करता है

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है

सही उत्तर: (a)

व्याख्या:

- चक्रीय अर्थव्यवस्था ऊर्जा-गहन निष्कर्षण और परिशुद्ध सामग्री के उत्पादन पर निर्भरता को कम करके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHG) को कम करती है।
- उदाहरणस्वरूप, पुन: उपयोग किये गए संसाधनों के माध्यम से विनिर्माण करने पर मूल (प्राकृतिक) संसाधनों की अपेक्षा 20 से 90 प्रतिशत तक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आ सकती है। **अतः कथन I सही है।**
- चक्रीय अर्थव्यवस्था का एक मुख्य सिद्धांत पुन: उपयोग, मरम्मत और पुनर्चक्रण के माध्यम से संसाधनों को उपयोग में लाकर अपशिष्ट एवं प्रदूषण का शमन करना है। इससे खनिजों, धातुओं और जीवाश्म ईंधन जैसे परिशुद्ध कच्चे माल की मांग कम हो जाती है। **अत: कथन II सही है।**
- चक्रीय अर्थव्यवस्था स्थायित्व, मरम्मत और पुनर्चक्रण को प्राथमिकता देकर अपशिष्ट का विवेकपूर्ण पुन: उपयोग करती है।
- उदाहरणस्वरूप, उत्पादों का परित्याग करने के स्थान पर उनका पुनर्निर्माण (Refurbishment) करने से सामग्री की हानि को रोका जा सकता है।
- सामग्री चक्रों को बंद करके उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में अपशिष्ट सृजन को न्यूनतम किया जा सकता है। **इसलिये कथन III सही है।**

अत: विकल्प (a) सही है।

2024

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत इंटरनेशनल ग्रेंस काउंसिल का सदस्य है।

2. चावल और गेहूँ के निर्यात या आयात के लिये किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेंस काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1, न ही 2**

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: इंटरनेशनल ग्रेंस काउंसिल (IGC) एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

- अनाज व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना; अनाज क्षेत्र के विस्तार के साथ पारदर्शिता तथा निष्पक्षता को बढ़ावा देना; अनाज बाज़ार की स्थिरता में योगदान देना तथा विश्व खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना।
- भारत इंटरनेशनल ग्रेंस काउंसिल का सदस्य है। **अत: कथन 1 सही है।**
- इसमें प्रत्येक सदस्य को अनाज, चावल एवं तिलहन के उसके औसत व्यापार के आधार पर आयातक या निर्यातक के रूप में नामित किया जाता है।
- चावल और गेहूँ के निर्यात या आयात के लिये किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेंस काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। **इसलिये कथन 2 सही नहीं है।**

अत: विकल्प (a) सही है।

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

कथन-I: भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है।

कथन-II: भारत में, विधि के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवंशिक रूप से रूपांतरित खाद्य (फूड) के आयात पर प्रतिषेध है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की व्याख्या करता है

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, किंतु कथन-II, कथन-I की व्याख्या *नहीं* करता है

(c) कथन-I सही है, किंतु कथन-II सही नहीं है

(d) कथन-I सही नहीं है, किंतु कथन-II सही है

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: सितंबर 2023 में भारत द्वारा अमेरिकी सेब पर **"रिटेलियेटरी आयात शुल्क (Retaliatory Import Duty)"** हटाने के बाद तीन महीनों में अमेरिकी सेबों का आयात 40 गुना बढ़ गया। **अतः कथन (I) सही नहीं है।**

- भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 द्वारा FSSAI की स्वीकृति के बिना GM खाद्य के आयात, उत्पादन, उपयोग या बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। **इसलिये कथन (II) सही है।**

अतः विकल्प (d) सही है।

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

कथन-I: हाल ही में, वेनेज़ुएला अपने आर्थिक संकट से तेज़ी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन/प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है।

कथन-II: वेनेज़ुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की व्याख्या करता है

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, किंतु कथन-II, कथन-I की व्याख्या *नहीं* करता है

(c) कथन-I सही है, किंतु कथन-II सही नहीं है

(d) कथन-I सही नहीं है, किंतु कथन-II सही है

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: वर्ष 2014 से अब तक 7.72 मिलियन से अधिक लोगों के पलायन के साथ, वेनेजुएला में शरणार्थी संकट लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा विस्थापन संकट है और विश्व में सबसे बड़े संकटों में से एक है। 7.72 मिलियन लोगों में से लगभग 84% लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में बस गए एवं उन्हें भोजन, आवास तथा आजीविका के लिये महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। **अतः कथन I सही नहीं है।**

- वर्ष 2021 में वेनेजुएला में कच्चे तेल का भंडार 304 बिलियन बैरल के करीब पहुँच गया, जो विगत दशक की शुरुआत में बताए गए आँकड़े से तीन गुना से भी अधिक है। जिसके साथ ही वेनेजुएला ने विश्वभर में सबसे बड़ा कच्चा तेल निक्षेप होने का दावा किया। **इसलिये कथन II सही है।**

अतः विकल्प (d) सही है।

4. भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये-

(आर्थिक गतिविधि)	(सेक्टर)
1. कृषि उत्पाद का भंडारण	– द्वितीयक
2. डेरी फार्म	– प्राथमिक
3. खनिज की खोज	– तृतीयक
4. कपड़ा बुनाई	– द्वितीयक

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

सही उत्तर: (b)

व्याख्या : भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि उपज के भंडारण को तृतीयक या सेवा क्षेत्र में रखा गया है। तृतीयक या सेवा क्षेत्र उत्पादन की प्रक्रिया को सहायता प्रदान करता है। इसमें उत्पादों का परिवहन, भंडारण, विपणन और बिक्री शामिल है। **अतः युग्म (1) सही नहीं है।**

- डेयरी क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक गतिविधियाँ प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। **अतः युग्म (2) सही है।**
- भारतीय अर्थव्यवस्था में खनिज अन्वेषण एक प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल का निष्कर्षण और कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ शामिल हैं। **अतः युग्म (3) सही नहीं है।**
- कपड़ों की बुनाई द्वितीयक गतिविधि के अंतर्गत आती है। इस क्षेत्र में तैयार माल का उत्पादन शामिल है। **इसलिये युग्म (4) सही है।**

अतः विकल्प (b) सही है।

2023

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

कथन-I: स्विट्ज़रलैंड, मूल्य के आधार पर, स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है।

कथन-II: स्विट्ज़रलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण निचय (रिज़र्व) है।

उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही है तथा कथन-II, कथन-1 की सही व्याख्या है

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही है तथा कथन-II, कथन-1 की सही व्याख्या नहीं है।

(c) कथन-I सही है किंतु कथन-II गलत है

(d) कथन-I गलत है किंतु कथन-II सही है

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: स्विट्ज़रलैंड मूल्य के आधार पर, स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। अत: कथन (1) सही है।

- वर्ष 2021 में स्विट्ज़रलैंड का **स्वर्ण** निर्यात लगभग 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के बराबर था। स्विट्ज़रलैंड लगातार मूल्य के आधार पर विश्व का अग्रणी स्वर्ण निर्यातक देश है।
- मूल्य के आधार पर स्वर्ण का सबसे बड़ा निर्यातक होने के अतिरिक्त, स्विट्ज़रलैंड विश्व में स्वर्ण का लगातार सबसे बड़ा आयातक भी रहा है। इसे इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि स्विट्ज़रलैंड विश्व के लगभग 70 प्रतिशत स्वर्ण को परिष्कृत करता है। स्विट्ज़रलैंड अपरिष्कृत स्वर्ण का आयात करता है एवं इसे अपने परिष्कृत रूप में निर्यात करता है।
- 1,040 टन स्वर्ण के साथ, स्विस नेशनल बैंक (SNB) के पास विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा स्वर्ण का भंडार है। **इसलिये कथन (2) सही नहीं है।**

अत: विकल्प (c) सही है।

2022

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है।

2. वियतनाम का नेतृत्व बहु-दलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है।

3. वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति शृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है।

4. लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है।

5. हिंद-प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक e-सेवा सेक्टर वियतनाम में है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) 2 और 4 **(b) 3 और 5**

(c) 1, 3 और 4 **(d) 1 और 2**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: 'https:statisticstimes.com' के अनुसार, वर्ष 2020 और 2021 में वियतनाम की विकास दर रैंक क्रमश: 15 और 38 है। अत: कथन 1 सही है।

- वियतनाम एक-दलीय प्रणाली वाला देश है, जहाँ वियतनाम की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी (CPV) दशकों से प्रभावी रही है। **अत: कथन (2) सही नहीं है।**
- विनिर्माण उद्योग कई प्रमुख कारकों द्वारा संचालित होता है। सबसे पहले, वियतनाम को प्रतिस्पर्द्धी श्रम लागत के साथ कम लागत वाला निर्माता माना जाता है। औसतन, वियतनाम की श्रम लागत चीन की श्रम लागत से आधी है।
- वर्ष 2015 से वियतनामी सरकार ने सरकार ने डॉलर के मुकाबले वियतनामी डोंग (VND) को वास्तविक रूप से स्थिर रखा है। **अत: कथन (4) सही है।**
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, 'COVID-19 के बावजूद, वियतनाम की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है'। वर्ष 2020 में, इसमें 2.9% का विस्तार हुआ। यह एशिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है; यह अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार युद्ध में चीन द्वारा खोए गए अधिकांश व्यवसाय को लेने में कामयाब रहा है, जबकि अभी भी दोनों देशों के साथ ठोस संबंध स्थापित कर रहा है। वियतनाम की अर्थव्यवस्था बढ़ती रहेगी और देश वैश्विक आपूर्ति शृंखला में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। **इसलिये कथन 3 सही है।**

अतः विकल्प (c) सही है।

2. निम्नलिखित में कौन-कौन-से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक (रियल सेक्टर) का निर्माण करते हैं?

1. किसानों को अपनी फसलें काटना

2. कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना

3. किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना

4. किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपया-अंकित मूल्य के बॉण्ड जारी करना

नीचे दिये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 2, 3 और 4**

(c) केवल 1, 3 और 4 **(d) 1, 2, 3 और 4**

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: वास्तविक क्षेत्रक वह क्षेत्र होता है, जहाँ वास्तविक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, रूपांतरण और वितरण होता है। इसके अंतर्गत कृषि, उद्योग, विनिर्माण, निर्माण तथा भौतिक सेवाएँ आती हैं।

- किसी समूह द्वारा अपनी फसलें काटना कृषि क्षेत्र की एक वास्तविक आर्थिक क्रिया है, जिसमें भौतिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। **अतः कथन (1) सही है।**
- कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना विनिर्माण (द्वितीयक क्षेत्रक) से संबंधित है, जिसमें कच्चे माल को मूल्यवर्द्धन द्वारा तैयार वस्तु में बदला जाता है। **अत: कथन (2) सही है।**
- किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना एक वित्तीय गतिविधि है। इसमें बैंक केवल धन का स्थानांतरण करता है, न कि किसी वस्तु या सेवा का प्रत्यक्ष उत्पादन। **अत: कथन (3) सही नहीं है।**
- बॉण्ड जारी करना पूंजी बाज़ार की एक गतिविधि है, जिसको उद्देश्य वित्तीय संसाधनों का संग्रह करना होता है। इसमें न तो उत्पादन होता है और न ही किसी वास्तुविक वस्तु का निर्माण। **इसलिये कथन (4) सही नहीं है।**

अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

2021

1. 'वाटरक्रेडिट' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिये सूक्ष्म वित्त साधनों (माइक्रोफाइनेंस टूल्स) को लागू करता है।

2. यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्त्वावधान में प्रारंभ किया गया है।

3. इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायिकी के बिना अपनी जल-संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये समर्थ बनाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 2 और 3**

(c) केवल 1 और 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: अमेरिका स्थित एनजीओ Water.org अपनी वाटरक्रेडिट पहल के माध्यम से विभिन्न देशों में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों को जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिये सूक्ष्म वित्तीय साधनों (Microfinance Tools) को लागू करता है। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायिकी (Subsidy) के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये समर्थ बनाना है। यह ज़रूरतमंद परिवारों को पानी और स्वच्छता के लिये किफायती वित्तपोषण प्रदान करने के लिये चयनित संस्थानों के साथ साझेदारी करता है। अत: कथन (1) और (3) सही हैं।

- Water.org एक वैश्विक गैर-लाभकारी संगठन है जो दुनिया में पानी और स्वच्छता लाने के लिये काम कर रहा है। इसने सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिये किफायती वित्तपोषण की बाधा को दूर करने के लिये 'वाटरक्रेडिट' कार्यक्रम की पहल शुरू की। अत: कथन (2) सही नहीं है। **अत: विकल्प (c) सही है।**

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिये बाज़ार मांग बढ़ सकती है, यदि

1. इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो।

2. इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो।

3. वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है।

4. इसकी कीमत घटती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 4 **(b) 2, 3 और 4**

(c) 1, 3 और 4 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: एक वस्तु की मात्रा जिसका चयन उपभोक्ता करता है, किसी संबंधित वस्तु की मूल्य वृद्धि के साथ बढ़ या घट सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों वस्तुएँ एक दूसरे की 'स्थानापन्न (Substitute)' या 'पूरक (Complement)' हैं या नहीं। जिन वस्तुओं का साथ-साथ उपयोग किया जाता है उन्हें 'पूरक वस्तुएँ' कहा जाता है। जैसे- चाय और चीनी, जूते और जुराब, कलम और स्याही इत्यादि। क्योंकि चाय और चीनी का एक साथ उपयोग में लाए जाते हैं, संभव है कि चीनी की कीमत में वृद्धि से चाय के लिये मांग घटाएगी तथा चीनी कीमत में कमी चाय की मांग में वृद्धि करेगी। पूरक वस्तुओं के विपरीत स्थानापन्न का एक साथ सेवन नहीं किया जाता है जैसे- चाय और कॉफी। वास्तव में चाय और कॉफी एक दूसरे के विकल्प हैं। चूँकि चाय कॉफी का विकल्प है, अगर कॉफी की कीमत बढ़ती है, तो उपभोक्ता चाय की ओर रुख कर सकते हैं, और इसलिये, चाय की मांग बढ़ने की संभावना है। दूसरी ओर, यदि कॉफी की कीमत घटती है, तो चाय की मांग कम होने की संभावना है। किसी वस्तु की मांग सामान्यत: उसके स्थानापन्नों की कीमत की दिशा में चलती है। अत: कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 सही नहीं है।

- उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ वस्तु की प्रकृति के आधार पर किसी वस्तु की मांग बढ़ या घट सकती है। अधिकांश वस्तुओं की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है और उपभोक्ता की आय घटने पर घट जाती है। ऐसी वस्तुएँ 'सामान्य वस्तु' कहलाती हैं। हालाँकि, कुछ ऐसी वस्तुएँ भी होती हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में चलती है। ऐसी वस्तुओं को 'निम्नस्तरीय (घटिया) वस्तु' कहा जाता है। जैसे-जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है, निम्नस्तरीय वस्तु की मांग घटती जाती है और आय घटने पर निम्नस्तरीय वस्तु की मांग बढ़ती जाती है। निम्नस्तरीय वस्तुओं में निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ जैसे मोटे अनाज शामिल हैं। अत: कथन 3 सही नहीं है।
- अन्य कारकों के अपरिवर्तित रहने पर उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिये मांग और वस्तु की कीमत के बीच संबंध साधारणता नकारात्मक होता है। दूसरे शब्दों में, वस्तु की मात्रा जो उपभोक्ता का इष्टतम चयन होगा, वह वस्तु की कीमत गिरने से संभावित रूप से बढ़ सकती है और वस्तु की कीमत में वृद्धि के साथ घट सकती है। अत: कथन (4) सही है। **अत: विकल्प (a) सही है।**

2020

1. 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता (2004-05 की कीमतों पर प्रति श्रमिक ₹) में वृद्धि हुई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई।

2. कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में, गैर-कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई।
4. ग्रामीण रोज़गार की वृद्धि दर में कमी आई।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 3 और 4**
(c) केवल 3 **(d) केवल 1, 2 और 4**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: 1991 का आर्थिक उदारीकरण मुख्यतया उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित रहा है। इसके अंतर्गत उद्योगों और व्यापार के लिये लाइसेंसिंग के स्थान पर उदारीकरण की नीति का पालन किया गया।

इस नीति से उद्योग एवं अवसंरचना क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसने औद्योगिक क्षेत्र में मंदी पर लगाम लगाने का काम किया। वहीं इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी परिलक्षित हुए, जो निम्नलिखित हैं-

- कुछ चुनिंदा राज्यों में ही निवेश होने से प्रादेशिक असमानता बढ़ी;
- ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल श्रमिकों के रोज़गार छिन जाने से कार्यबल में उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी में कमी दर्ज की गई;
- उद्योग और सेवा क्षेत्र के बढ़ने तथा कृषि की उपेक्षा के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखी गई;
- ग्रामीण रोज़गार की वृद्धि दर में कमी आई;
- कुशल श्रमिकों को अकुशल श्रमिकों पर वरीयता प्रदान करने से रोज़गार में असामनता दर्ज की गई। **अतः विकल्प (b) सही है।**

2019

1. वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट (ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट) कौन प्रकाशित करता है?

(a) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(b) संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट)
(c) विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम)
(d) विश्व बैंक

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट (Global Competitiveness Report) विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक प्रतियोगित्व (प्रतिस्पर्द्धा) सूचकांक 12 संकेतकों पर आधारित होता है-

1. संस्थान; 2. उपयुक्त आधारभूत संरचना; 3. स्थिर समष्टि आर्थिक ढाँचा; 4. अच्छा स्वास्थ्य एवं प्राथमिक शिक्षा; 5. उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण; 6. कुशल माल बाज़ार; 7. कुशल श्रम बाज़ार; 8. वित्तीय बाज़ारों का विकास; 9. मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता; 10. बाज़ार आकार-घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों; 11. सबसे परिष्कृत उत्पादन प्रक्रियाओं का उपयोग करके विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं का उत्पादन; 12. नवाचार

नोट: वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक, 2025 में विश्व के 69 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत का स्थान 41वाँ था।

2. किसी दिये गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएँ अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि

(a) गरीबी की दर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है
(b) कीमत-स्तर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है
(c) सकल राज्य उत्पाद अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है
(d) सार्वजनिक वितरण की गुणता अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: सामान्यतः भारत में आधिकारिक गरीबी रेखाएँ (Official Poverty Lines) किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिये किये गए प्रति व्यक्ति औसत व्यय से संबंधित होती हैं। अतः अलग-अलग राज्यों में कीमत स्तर अलग-अलग होने से राज्यों की आधिकारिक गरीबी रेखाओं में भिन्नता आती है। **इस प्रकार विकल्प (b) सही उत्तर है।**

3. निम्नलिखित में से कौन-सा देश पिछले पाँच वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है?

(a) चीन **(b) भारत**
(c) म्यांमार **(d) वियतनाम**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: भारत पिछले पाँच वर्षों से लगातार विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बना हुआ है। भारत सर्वप्रथम 2011-12 में थाईलैंड को विस्थापित करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बना था। इसका प्रमुख कारण था चावल की गैर-बासमती किस्मों के निर्यात पर चार साल से लगे प्रतिबंध को हटाना। इस अवधि के बाद भारत का प्रदर्शन बेहतर ही रहा। हाल के वर्षों (2014-18) में वैश्विक चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 25-26 प्रतिशत पर रही है। जबकि थाईलैंड में 22 से 25 प्रतिशत और वियतनाम में 13 से 16 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था।
2. वर्तमान में, कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है।
3. भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिये कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2 और 3**
(c) केवल 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: (a)

व्याख्या: भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। अत: कथन 1 सही है।

- वर्तमान में, कोयला ब्लॉकों का आवंटन कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत नीलामी (Auction) के आधार पर किया जाता है, न कि लॉटरी के आधार पर। अत: कथन 2 गलत है।
- कथन 3 गलत है क्योंकि कोयला उत्पादन में वृद्धि के बावजूद भी भारत इसमें आत्मनिर्भर नहीं हो सका है। गौरतलब है कि भारत में साधारण कोयले के भंडार तो प्रचुर मात्रा में प्राप्त हैं, किंतु कोक उत्पादन के लिये उत्तम श्रेणी का कोयला अपेक्षाकृत सीमित है। भारत को अपनी घरेलू कोयला मांग के लगभग $\frac{1}{4}$ हिस्से की पूर्ति आयात से करनी पड़ती है।

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) केंद्रीय (संशोधन) नियम, 2018 के अनुसार

1. यदि नियत अवधि रोज़गार के लिये नियमों को कार्यान्वित किया जाता है, तो फर्म/कंपनियों के लिये कामगारों की छँटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है

2. अस्थायी कामगारों के मामलों में रोज़गार समाप्त करने के लिये कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1, न ही 2**

सही उत्तर: **(c)**

व्याख्या: औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) केंद्रीय (संशोधन) नियम, 2018 के अनुसार कथन 1 तथा 2 दोनों सही हैं।

6. भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक ज़ोर दिया गया।

2. चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया।

3. पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, पहली बार, वित्तीय क्षेत्रक को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया।

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिये :

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 2**

(c) केवल 3 **(d) 1, 2 और 3**

सही उत्तर: **(a)**

व्याख्या: द्वितीय पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन (Substitution) की दिशा में निश्चयात्मक ज़ोर दिया गया।

- इस योजना के दौरान (1956-1961) राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किये गए। साथ ही चित्तरंजन लोकोमोटिव्स, सिंदरी उर्वरक कारखाना, इंटिग्रल कोच फैक्टरी आदि भी इसी योजना काल के दौरान स्थापित किये गए। अत: कथन 1 सही है।
- ध्यातव्य है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी।
- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-1974) का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति था। अत: कथन 2 भी सही है।
- ध्यातव्य है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी।
- पाँचवी पंचवर्षीय योजना (1974-1979) में नहीं बल्कि नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में पहली बार वित्तीय क्षेत्रक को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया था। अत: कथन 3 गलत है।
- विदित है कि पाँचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य थे। इस योजना के दौरान वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। 'राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' और 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' भी इसी योजना में क्रियान्वित किये गए।

7. किसी भी देश के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी (सोशल कैपिटल) के भाग के रूप में समझा जाएगा?

(a) जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात

(b) इसके भवनों, अन्य आधारिक संरचना और मशीनों का स्टॉक

(c) कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आमाप

(d) समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर

सही उत्तर: **(d)**

व्याख्या: समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का जो स्तर है, उसे किसी भी देश के संदर्भ में, उस देश की सामाजिक पूंजी (Social Capital) के भाग के रूप में समझा जाता है।

- प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधन का दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है। ये सामाजिक संसाधन 'पूंजी' के तीन रूपों में विभाजित किये जा सकते हैं: भौतिक संपत्ति एवं आय के रूप में 'आर्थिक पूंजी'; प्रतिष्ठा और शैक्षणिक योग्यताओं के रूप में 'सांस्कृतिक पूंजी' और सामाजिक संगतियों एवं संपर्कों के जाल के रूप में सामाजिक पूंजी।

- पूंजी के ये तीनों रूप अक्सर आपस में घुले-मिले होते हैं तथा एक को दूसरे में बदला जा सकता है। उदाहरणतया, एक संपन्न परिवार का व्यक्ति अपनी आर्थिक पूंजी के ज़रिये महँगी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है; इस तरह वह अपनी आर्थिक पूंजी को सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वरूप दे सकता है। उसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति अपने प्रभावशाली मित्रों व संबंधियों (यानी अपनी सामाजिक पूंजी) के ज़रिये अच्छी सलाह, सिफारिश या जानकारी पा सकता है और इनके द्वारा एक अच्छी आय वाली नौकरी पाकर सामाजिक पूंजी को आर्थिक पूंजी में बदल सकता है।

नोट: लेगाटम समृद्धि सूचकांक जिन 9 उप-सूचकांकों पर आधारित होता है, उसमें से एक 'सामाजिक पूंजी' है।

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. क्रय शक्ति समता [परचेज़िंग पावर पैरिटि (PPP)] विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एकसमान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना कर की जाती है।

2. PPP डॉलर के संदर्भ में, भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1, न ही 2**

सही उत्तर: **(a)**

व्याख्या: कथन 1 PPP की सटीक परिभाषा है इसलिये कथन 1 सही है।

- 2018 में विश्व बैंक द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार PPP डॉलर के संदर्भ में भारत, चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात् विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। (वर्ष 2021 में भी यही स्थिति बनी हुई है) अत: कथन 2 गलत है।

2018

1. निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊँची दर का संकेत नहीं करतीं, यदि

(a) औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है।

(b) कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है।

(c) निर्धनता और बेरोज़गारी में वृद्धि होती है।

(d) निर्यातों की अपेक्षा आयात तेज़ी से बढ़ते हैं।

सही उत्तर: **(c)**

व्याख्या: आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था के गुणात्मक पक्षों से संबंधित होता है। यह समाज के वंचित वर्गों के हितों का भी संवर्द्धन करता है। इस प्रकार, यदि प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP वृद्धि के बावजूद निर्धनता व बेरोज़गारी में वृद्धि हो रही हो, तो इसे आर्थिक विकास का पर्याय नहीं माना जाएगा। **अत: विकल्प (c) सही है।**

2. उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्त्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है?

(a) कमज़ोर प्रशासन तंत्र **(b) निरक्षरता**

(c) उच्च जनसंख्या घनत्व **(d) उच्च पूंजी-उत्पाद अनुपात**

सही उत्तर: **(d)**

व्याख्या: एक निश्चित उत्पादन के लिये वांछित कुल पूंजी के आनुपातिक मूल्य को पूंजी उत्पाद अनुपात (COR) कहते हैं। उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात निवेश को हतोत्साहित करता है। प्रतिस्पर्द्धी आर्थिक परिदृश्य में निवेशक-निम्न पूंजी उत्पाद अनुपात संबंधित गंतव्य की ओर उन्मुख होता है।

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम (प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन) अधिनियम, 1954 को प्रतिस्थापित किया।

2. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) (एफ.एस.एस.ए. आई.) केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों **(d) न तो 1, न ही 2**

सही उत्तर: **(a)**

व्याख्या: अगस्त 2016 में जिस दिन संसद द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSSA) पारित किया गया, उसी दिन खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम, 1954 रद्द हो गया। अत: कथन (1) सही है। FSSAI के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा खाद्य विज्ञान के क्षेत्र में प्रख्यात लोगों या एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित ऐसे लोगों, जो खाद्य क्षेत्र से संबंधित रहे हों तथा भारत सरकार के सचिव स्तर के पद पर कार्यरत हों या पूर्व में रहे हों, में से की जाती है। अत: कथन (2) सही नहीं है।

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो "गरीबी रेखा से नीचे" (बी.पी.एल) श्रेणी में आते हैं।

2. परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किये जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी।

3. गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छः महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) केवल 2

(c) 1 और 3 (d) केवल 3

सही उत्तर: (b)

व्याख्या:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में देश के गरीब नागरिकों को राजकीय सहायता पर अनाज प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की 75% तथा शहरी क्षेत्र की 50% आबादी को कवर किया गया है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार को चावल, गेहूँ व मोटे अनाज क्रमशः ₹ 3/₹ 2/₹ 1 प्रति किलो की सहायकी दर पर प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है।
- पात्र परिवारों की पहचान करना तथा उनको राशन कार्ड जारी करना राज्य सरकारों के अधीन है। राशन कार्ड पर 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाओं को मुखिया के तौर पर नामित करने एवं ऐसा नहीं होने पर परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य को मुखिया के तौर पर नामित करने का प्रावधान किया गया है।
- अधिनियम में गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाएँ तथा स्तनपान कराने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद तक भोजन के अलावा कम-से-कम ₹ 6000 मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार होंगी।

अतः केवल कथन 2 सही है।

5. अप्रवासी सत्त्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह आय कर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है।

2. भारत में विज्ञापन सेवाएँ देने वाले अप्रवासी सत्त्व अपने गृह देश में "दोहरे कराधान से बचाव समझौते" के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: भारत सरकार ने गूगल एवं फेसबुक जैसी बाहरी कंपनियों पर अप्रत्यक्ष रूप से कर लगाने के लिये वर्ष 2016 के बजट में इक्वलाइज़ेशन लेवी की घोषणा की थी-

- यह इनकम टैक्स एक्ट, 1961 का भाग नहीं है, अतः कथन 1 सही नहीं है।
- इस इक्वलाइज़ेशन लेवी के भुगतान के बदले भारत में विज्ञापन सेवाएँ देने वाली विदेशी कंपनियाँ अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकती हैं। अतः कथन 2 भी सही नहीं है।

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. पिछले पाँच वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा, खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है।

2. सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

सही उत्तर: (a)

व्याख्या:

पिछले 5 वर्षों में खाद्य तेलों का उत्पादन		पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा
2012–13	6.70 मिलियन टन	10.38 मिलियन टन
2013–14	7.11 मिलियन टन	11.62 मिलियन टन
2014–15	6.17 मिलियन टन	14.42 मिलियन टन
2015–16	5.82 मिलियन टन	14.59 मिलियन टन
2016–17	7.05 मिलियन टन	15.20 मिलियन टन
2017–18	7.66 मिलियन टन	15.12 मिलियन टन

अतः कथन 1 सही है।

चीन तथा अन्य एशियाई देशों से 10 सेक्टर के आयात को हतोत्साहित करने के लिये सरकार ने सीमा शुल्क को बढ़ाया है जिसमें खाद्य तेल भी शामिल है। इसलिये, कथन 2 सही नहीं है।

7. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत सरकार का/के "डिजिटल इंडिया" योजना का/के उद्देश्य है/हैं?

1. भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा कि चीन ने किया।

2. एक नीतिगत ढाँचे की स्थापना जिससे बड़े आँकड़े एकत्रित करने वाली समुद्रपारीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डाटा केंद्रों की स्थापना करें।

3. हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाई-फाई (Wi-Fi) लाना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: 'डिजिटल इंडिया' भारत सरकार का विस्तृत एवं समग्र कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य मुख्यत: तीन क्षेत्रों पर आधारित है-

1. प्रत्येक नागरिक के लिये सुविधा के रूप में बुनियादी ढाँचा।
2. गवर्नेंस व मांग आधारित सेवाएँ।
3. नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण।

उपरोक्त विज़न के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल जुड़ाव के लिये वैश्विक पहुँच, सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच कार्यक्रम, ई शासन-तकनीक के ज़रिये सरकारी सुधार, ई क्रांति-सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति की जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, लक्षित शून्य आयात, रोज़गार के लिये सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम इत्यादि उपलब्ध कराना है। इन उद्देश्यों के तहत यह कार्यक्रम भारत के अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ने तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाई-फाई लाने के लिये प्रतिबद्ध है।

इस तरह प्रश्न में दिये गए कथन 1 और 2 किसी भी तरह डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों से संबंधित नहीं हैं। केवल कथन 3 सही है, **अत: विकल्प (b) सही है।**

8. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यह श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है।

2. यह, अन्य चीज़ों के साथ-साथ, सॉफ्ट स्किल, उद्यमवृत्ति, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी।

3. यह देश के अविनियमित कार्यबल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा (नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क) के साथ जोड़ेगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के दिशा-निर्देश में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। यह युवाओं के प्रशिक्षण के लिये एक मुख्य योजना है। इन प्रशिक्षण केंद्रों में ऐसे उम्मीदवारों, जो स्कूल या कॉलेज छोड़ चुके हैं तथा बेरोज़गार हैं, को लघु अवधि प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इन प्रशिक्षण केंद्रों पर राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन ढाँचे के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा सॉफ्ट स्किल, उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश के अनियमित कर्मचारियों की दक्षता की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय कौशल ढाँचे के साथ संलग्न करना है। अत: कथन 2 और 3 सही हैं।

2017

1. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ/हुए है/हैं?

1. GDP में कृषि का अंश बृहत् रूप से बढ़ गया।

2. विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया।

3. FDI का अंतर्वाह (इनफ्लो) बढ़ गया।

4. भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहत् रूप से बढ़ गया।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 और 4 (b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 17.32 प्रतिशत है, जबकि उद्योग क्षेत्र का 29.02% तथा सेवा क्षेत्र का 53.66% है। आज़ादी के बाद भारत के GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक था, जबकि उदारीकरण के बाद प्रतिवर्ष कृषि क्षेत्र का योगदान घटता गया है और अन्य क्षेत्रों का योगदान बढ़ा है। इसके साथ ही विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ा है। साथ ही, अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी विनिमय भंडार में भी बढ़ोतरी हुई है।

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. पिछले दशक में भारत के GDP के प्रतिशत के रूप में कर-राजस्व में सतत वृद्धि हुई है।

2. पिछले दशक में भारत के GDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

सही उत्तर: (d)

व्याख्या: पिछले दशक में GDP के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत् वृद्धि नहीं हुई है। यह 2007 में 17 प्रतिशत के लगभग थी जो 2009 में घटकर 15 प्रतिशत व 2016 में पुन: बढ़कर 16.6 प्रतिशत हो गई है। अत: कथन 1 गलत है।

पिछले दशक में भारत के GDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा घटता-बढ़ता रहा है। अत: कथन 2 गलत है। इस प्रकार प्रश्न के संदर्भ में विकल्प (d) सही उत्तर है।

3. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा हाल ही में समाचारों में आए 'दबावयुक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचन पद्धति (स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स/S4A)' का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है?

(a) यह सरकार द्वारा निरूपित विकासपरक योजनाओं की पारिस्थितिकीय कीमतों पर विचार करने की पद्धति है।

(b) यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचन के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक की स्कीम है।

(c) यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में सरकार की विनिवेश योजना है।

(d) यह सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वित 'इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड' का एक महत्त्वपूर्ण उपबंध है।

सही उत्तर: (b)

व्याख्या: 'दबावयुक्त परिसंपत्तियों की धारणीय संरचन पद्धति' (S4A) योजना रिज़र्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना का पुनर्संरचना करना था। **अतः विकल्प (b) सही है।**

2015

1. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है।

2. पिछले दशक में बाज़ार कीमतों पर (रुपयों में) सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 | **(b) केवल 2**

(c) 1 और 2 दोनों | **(d) न तो 1 और न ही 2**

सही उत्तर: (b)

व्याख्या:

वर्ष	GDP (MP) (लाख करोड़ रुपये में लगभग मान)
2004–05	32 लाख करोड़
2005–06	37 लाख करोड़
2006–07	43 लाख करोड़
2007–08	50 लाख करोड़
2008–09	56 लाख करोड़
2009–10	65 लाख करोड़
2010–11	78 लाख करोड़
2011–12	90 लाख करोड़
2012–13	101 लाख करोड़
2013–14	114 लाख करोड़

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि बाज़ार मूल्यों पर GDP में लगातार वृद्धि हो रही है, किंतु भारत में वास्तविक GDP की वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव रहा है। अतः केवल कथन 2 सही है।

2013

1. प्रच्छन्न बेरोज़गारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि

(a) लोग बड़ी संख्या में बेरोज़गार रहते हैं

(b) वैकल्पिक रोज़गार उपलब्ध नहीं है

(c) श्रमिक की सीमान्त उत्पादकता शून्य है

(d) श्रमिकों की उत्पादकता नीची है

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: प्रायः ऐसा पाया जाता है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन के इष्टतम स्तर को प्राप्त करने के लिये जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग खेती में लगे रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें यदि खेत या कृषि से निकाल लिया जाए तो भी कृषि से प्राप्त कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। ऐसे श्रमिक जो ऊपर से देखने में तो रोज़गार में लगे रहते हैं पर वास्तव में रोज़गार में नहीं होते हैं क्योंकि उनसे प्राप्त होने वाली सीमान्त उत्पादकता शून्य है। इसीलिये उनके बाहर निकलने के बाद भी कुल उत्पादन पहले जैसा बना रहता है। ऐसे श्रमिकों को प्रच्छन्न बेरोज़गार कहते हैं।

2. x देश में आर्थिक संवृद्धि अनिवार्य रूप से होगी, यदि

(a) विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है

(b) x में जनसंख्या वृद्धि होती है

(c) x में पूंजी निर्माण होता है

(d) विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है

सही उत्तर: (c)

व्याख्या: विकल्प **(c)** सही है, क्योंकि पूंजी आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारकों में सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है। यह अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के स्तर, उत्पादन का ढाँचा, तकनीकी प्रगति, उत्पादन क्षमता आदि का निर्धारण करती है। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि लाई जाती है, उसे हम पूंजी निर्माण कहते हैं। पूंजी निर्माण से संबंधित महत्त्वपूर्ण पहलू निम्नवत् हैं-

- पूंजी निर्माण से ही निवेश (Investment) को गति मिलती है। बिना पूंजी निर्माण के कोई राष्ट्र विश्व अर्थव्यवस्था में आई तकनीकी प्रगति का लाभ नहीं उठा सकता। केवल तकनीकी प्रगति से आर्थिक संवृद्धि होना अनिवार्य नहीं है।

- विकल्प **(b)** गलत है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि नहीं बल्कि जनांकिकीय लाभांश अथवा देश की कुल कार्यशील जनसंख्या के कौशल विकास से आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित हो सकती है।
- विकल्प **(d)** सही नहीं है, क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ जाने पर भी x देश में आर्थिक संवृद्धि तब तक नहीं होगी जब तक कि पर्याप्त मात्रा में पूंजी सुलभता आयात-निर्यात के लिये न हो। इस प्रकार पूंजी निर्माण से x देश में आर्थिक संवृद्धि अनिवार्य रूप से होगी।

3. किसी दी गई अवधि के लिये एक देश की राष्ट्रीय आय-

(a) नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी

(b) कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी

(c) सभी व्यक्तियों की वैयक्तिक आय के योग के बराबर होगी

(d) उत्पादित अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी

सही उत्तरः **(d)**

व्याख्याः किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं या पूर्ण निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य 'राष्ट्रीय आय' कहलाता है। किसी देश के निवासियों की कुल आय जिसे ह्रास (Depreciation) घटाने के बाद साधन लागत पर मापा गया है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं।

2011

1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 'वित्तीय उत्प्रेरक' की समुचित व्याख्या करता है?

(a) यह सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्र में किया गया वृहद् निवेश है जिसका लक्ष्य माल की आपूर्ति की तीव्र आर्थिक विकास के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करना है

(b) यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्यवाही है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है

(c) यह सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों पर की गई गहन कार्यवाही है जिसका लक्ष्य कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रों को ऋण वितरित कराना है जिससे वृहत्तर खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके और खाद्य स्फीति पर अंकुश लग सके

(d) यह सरकार की चरम निश्चयात्मक कार्यवाही है जिसका लक्ष्य वित्तीय समावेशन नीति का अनुसरण करना है

सही उत्तरः **(b)**

व्याख्याः वित्तीय उत्प्रेरक की धारणा को वर्ष 2008-09 में वैश्विक स्तर पर आई आर्थिक मंदी से बल मिला। वित्तीय उत्प्रेरक एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा एक दबाव में पड़ी अर्थव्यवस्था को नया जीवन देने के लिये सरकार द्वारा सरकारी व्यय, लोक व्यय में वृद्धि की जाती है अथवा करों में कटौती की जाती है। इस प्रकार यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्यवाही है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. विगत पाँच वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सतत् रूप से बढ़ी है।

2. विगत पाँच वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सतत् रूप से बढ़ी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

सही उत्तरः **(d)**

व्याख्याः विगत पाँच वर्षों यानी 2006 से 2011 (प्रश्न पूछे जाने के वर्ष तक) के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सतत् रूप से बढ़ी नहीं है, बल्कि इसमें उतार-चढ़ाव विद्यमान रहा है। इसके साथ ही इन 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर भी सतत् रूप से नहीं बढ़ी है। इसमें भी उतार-चढ़ाव विद्यमान रहा है।

3. 'बंद अर्थव्यवस्था' वह अर्थव्यवस्था है जिसमें

(a) मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है

(b) घाटे की वित्त व्यवस्था होती है

(c) केवल निर्यात होता है

(d) न तो निर्यात, न ही आयात होता है

सही उत्तरः **(d)**

व्याख्याः बंद अर्थव्यवस्था में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये घरेलू स्तर पर उत्पादन, घरेलू स्तर पर आपूर्ति और घरेलू स्तर पर उपभोग पर बल दिया जाता है। द्विपक्षीय या बहुपक्षीय स्तर पर आर्थिक संबंधों को मज़बूत करने का प्रयास कम ही किया जाता है। आयात प्रतिस्थापन (Import Substitution) की नीति पर बल दिया जाता है। अर्थात् दूसरे राष्ट्र से आर्थिक विनिमय न होने के चलते निर्यात भी नहीं होता है।